R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 21 । अंक : 24
16 से 30 सितंबर 2023
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

जी 20 में दिखा दम... हम नहीं किसी से कम

भारत ने खेमों में बंटी दुनिया को एक किया

भारत की नेतृत्व क्षमता पर सभी ने लगाई मुहर

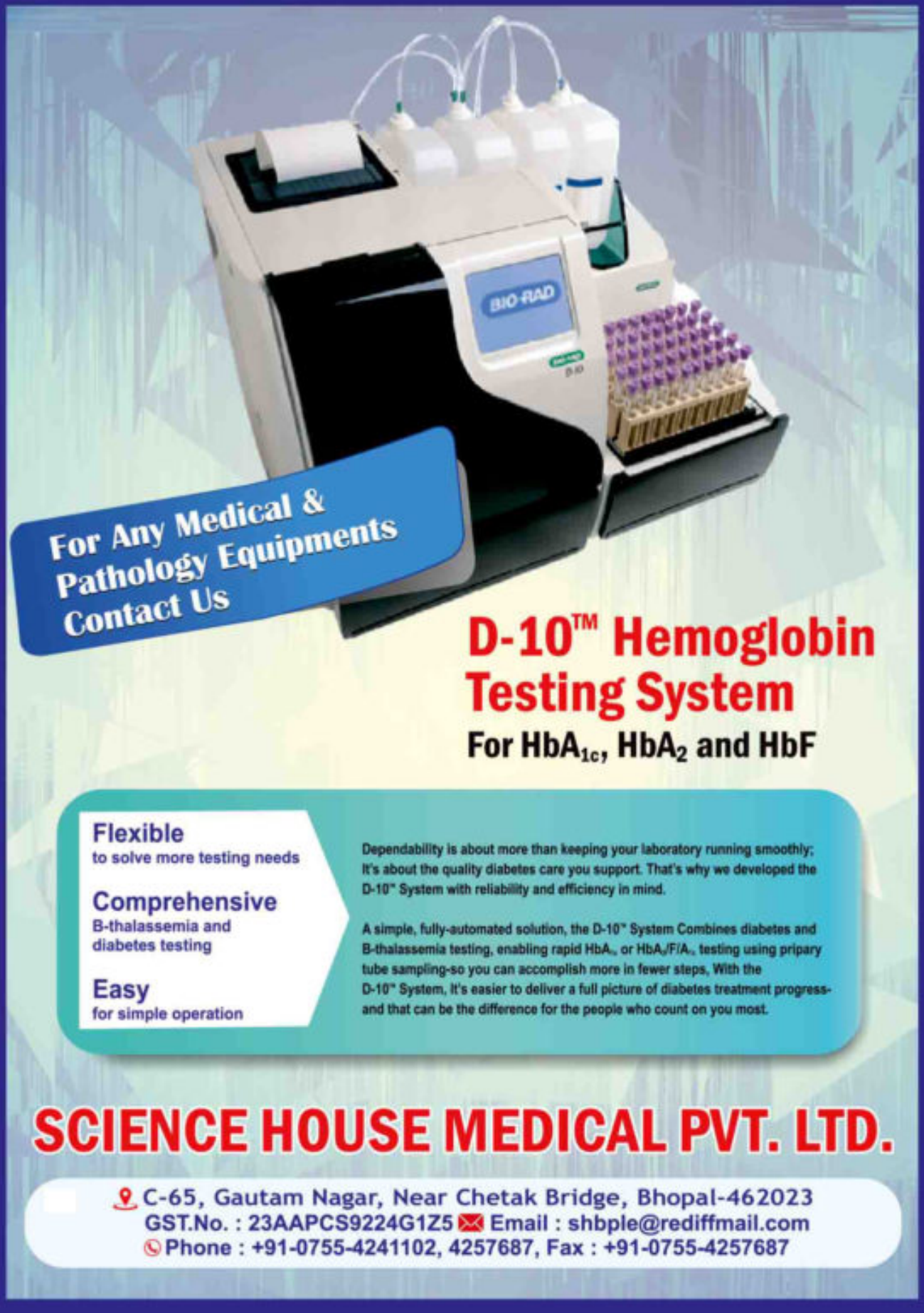

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

इस अंक में

लालफीताशाही

9 | आखिर कौन बचा रहा...

मप्र में सरकार सुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का दम भर रही है, वहीं दूसरी तरफ स्थिति यह है कि अफसर जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और भ्रष्टों के संरक्षक बने हुए हैं। ऐसा ही एक मामला मप्र...

राजपथ

10-11 | अबकी बार गारंटियों...

मप्र में विधानसभा चुनाव में वोटरों को रिझाने के लिए इस वक्त घोषणाओं का दौर चल रहा है। सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा और कांग्रेस में घोषणा करने की एक होड़ सी लगी हुई है। सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री...

तैयारी

15 | साढ़े पांच करोड़ मतदाता...

मप्र में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार की अगुवाई में गत दिनों केंद्रीय निर्वाचन दल तीन दिवसीय दौरे पर भोपाल आया। केंद्रीय निर्वाचन दल ने 4 सितंबर से 6 सितंबर...

विवाद

18 | बेरोजगारों से 696 करोड़ कमाए

कर्मचारी चयन बोर्ड, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, व्यापमं ये सरकार की वो संस्था, माफ कीजिए संस्था नहीं कंपनी है, जिसका नाम भले ही बदला हो, लेकिन घाटा कभी नहीं हुआ। अलबत्ता मुनाफा हर साल डबल होता गया। कर्मचारी चयन बोर्ड पर प्रदेश के सरकारी विभागों की...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

भारत की अध्यक्षता में जी-20 शिखर सम्मेलन अपने मूल एजेंडा और परिणामों के मामले में इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी व सफल सम्मेलन साबित हुआ है। इसमें कुल 112 परिणाम दस्तावेज व अध्यक्षीय दस्तावेज तैयार किए गए। पिछले सम्मेलन से तुलना करें, तो यह दोगुने से भी ज्यादा है। इसी वजह से इसे अब तक का सबसे सफल सम्मेलन माना जा रहा है। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि पूरे विश्व ने भारत की नेतृत्व क्षमता का दम देखा और उसका लोहा भी माना।

राजनीति

30-31 | 4 राज्यों में 'इंडिया'...

कुछ समय पहले तक यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि 2024 में 27 विपक्षी दल एक साथ आकर एक मजबूत विकल्प के रूप में केंद्रीय सत्ता के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। पर अब यह एक हकीकत है कि अपने तमाम मतभेदों, वैचारिक भिन्नताओं के बावजूद ये दल अब काफी...

महाराष्ट्र

35 | मराठा बनाम ओबीसी...

महाराष्ट्र के जालना जिले में मराठा आरक्षण को लेकर चला आंदोलन काफी हिंसक नजर आया। इसमें 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने दो बसों को आग के हवाले कर दिया और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। इस आंदोलन की आग में घी डालने के...

बिहार

38 | अपराधियों को राजनीतिक...

बिहार के मोतिहारी में नागपंचमी के मौके पर समुदाय विशेष से जुड़े लोगों ने एक शोभायात्रा पर पथराव कर दिया। इस पत्थरबाजी में न केवल महावीरी शोभायात्रा में शामिल भक्त घायल हुए बल्कि कुछ पुलिसवालों को भी चोट लगी। सोशल मीडिया पर...

6 -7 अंदर की बात
40 पड़ोस
41 विदेश
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

बहिष्कार की यह भी एक बानगी...

विश्व की ख्यातनाम अमेरिकी महिला पत्रकार हेलन थॉमस का कहना है कि हम पत्रकारिता में लोकप्रिय होने के लिए नहीं आते। यह हमारा कर्तव्य होता है कि हम सच्चाई की तलाश करें और जब तक जवाब नहीं मिले तब तक अपने नेताओं पर लगातार दबाव डालें। लेकिन आज देखने को यह मिल रहा है कि पत्रकारिता लोकप्रियता हासिल करने और नेताओं को परेशान करने का माध्यम बन गया है। दरअसल, वर्तमान में पत्रकारिता पार्टियों, विचारधारा आदि में बंट गई है। आलम यह है कि पत्रकार और पत्रकारिता सत्ता के सारथी बन गए हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक कहावत भी चल रही है- राजनीतिक रीत सदा चली आई, जिसकी लाठी उसी ने भैंस पाई। यानी मीडिया का एक वर्ग सत्ता के इशारे पर विपक्ष को निशाने पर रखता है। इसी का परिणाम है कि भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन यानी इंडिया ने आगामी चुनावों से पहले एक कड़ा फैसला लिया है। इसके मुताबिक देश के समावेशी ताने-बाने को खराब करने वाले एंकर और चैनलों पर अब इंडिया गठबंधन के सदस्य या प्रतिनिधि नजर नहीं आएंगे। गठबंधन ने जिन एंकरों के बहिष्कार का फैसला किया, उनमें अमन चोपड़ा (न्यूज 18), अमीश देवगन (न्यूज 18), अदिति त्यागी (भारत एक्सप्रेस), चित्रा त्रिपाठी (आज तक), रुबिका लियाकत (भारत 24), गौरव सावंत (इंडिया टुडे), प्राची पाराशर (इंडिया टीवी), आनंद नरसिम्हन (न्यूज 18), सुशांत सिन्हा (टाइम्स नाऊ नवभारत), शिव अरूर (इंडिया टुडे), सुधीर चौधरी (आज तक), अशोक श्रीवास्तव (डीडी न्यूज), नाविका कुमार (टाइम्स नाऊ), अर्णब गोस्वामी (रिपब्लिक भारत) आदि शामिल हैं। गठबंधन की मीडिया समिति के एक सदस्य के अनुसार, चैनलों के बहिष्कार का फैसला इस आधार पर लिया गया है कि वो जनसरोकार से जुड़े मुद्दों से कितने दूर हैं। उन्होंने लगे हाथ यह भी कहा कि कुछ चैनल और एंकर दिनभर सांप्रदायिक बहसें आयोजित करते हैं और लोगों को मंदिर-मस्जिद के झगड़ों में उलझाते हैं। इसलिए गठबंधन इनकी बहसों और चैनलों का हिस्सा नहीं बनना चाहता। दरअसल, वैश्विक स्तर पर एक बात पर हर देश सहमत है कि प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, जिसका अंदाजा शायद लोकतंत्र के सबसे बड़े और मजबूत गढ़ में लगाया जाना आसान है, जहां स्वाभाविक रूप से यह देखा जाता है कि हर शासनकाल में सत्ता केंद्र के अनुकूल विचारों का रुझान हर मीडिया चैनल पर दर्शक और जनता द्वारा महसूस किया जाता है, जो स्वाभाविक भी है, जिसे रेखांकित करना जरूरी है, क्योंकि अगर इतना बड़ा मीडिया हाउस चलना है तो बुराई अनैतिक व्यवहारों इत्यादि के खिलाफ लड़ाई करते हुए, कुछ सत्ता केंद्र की ओर रुझान भी जनता महसूस करती है। टीवी चैनलों पर करीब-करीब हर मीडिया चैनल पर हम अक्सर देखते हैं कि अनेक मुद्दों पर अनेक पार्टियों के प्रवक्ताओं को आमंत्रित कर उनसे उस मुद्दे पर डिबेट किया जाता है। परंतु सत्ता केंद्र रुझान वाले प्रवक्ताओं को कुछ बैकिंग मिलती है यह हम साफ महसूस करते हैं, इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं होता है। क्योंकि दर्शक और जनता जनार्दन समझती है कि यह उनके कर्तव्य, मजबूरी या नीति का होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि दिनांक 14 सितंबर को विपक्षी महागठबंधन इंडिया ने 14 पत्रकारों या यूं कहें कि मीडिया हाउसों पर अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेजने का निर्णय लिया है। इसके बाद सत्तापक्ष इसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार बता रहा है। लेकिन घायल की गति घायल ही जाने की तर्ज पर इंडिया गठबंधन वालों का कहना है कि हमने काफी सोच समझकर यह फैसला लिया है और अगर स्थिति में बदलाव नहीं हुआ तो हम अपने फैसले पर अडिग रहेंगे।

- राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 21, अंक 24, पृष्ठ-48, 16 से 30 सितंबर, 2023

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :

प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो

कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, **जयपुर:**- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता

094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय

नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर, मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

सख्त कार्यवाही हो

मप्र में आयुष्मान योजना की दुर्दशा हो रही है। भ्रष्टाचारियों ने आयुष्मान भारत को भ्रष्टाचार का जरिया बना लिया है। योजना के सबसे ज्यादा कार्डधारक भी मप्र में ही बताए गए। मप्र में आयुष्मान भारत योजना के तहत मुर्दों का भी इलाज किया गया। सरकार को इस मामले में सख्त कार्यवाही करनी चाहिए।

● **परशुराम शर्मा,** भोपाल (म.प्र.)

जातिगत जनगणना जरूरी

देश में जाति आधारित जनगणना 1931 के बाद से नहीं हुई है। आजादी के बाद से देश में अनुसूचित जाति और जनजातियों की गणना तो होती है, लेकिन ओबीसी और सामान्य वर्ग की जातियों को अलग-अलग नहीं गिना गया है। सरकार को एक बार जातिगत जनगणना करवानी ही चाहिए।

● **नितेश साहू,** इंदौर (म.प्र.)

खत्म हो रहे जंगल

मप्र में तेजी से जंगल खत्म हो रहे हैं। प्रदेश में जंगलों की कटाई कोई नई बात नहीं है। कई क्षेत्रों के जंगल बीते कुछ सालों में लगभग पूरी तरह साफ कर दिए गए हैं। इससे एक तरफ जहां पर्यावरण को नुकसान होता है, वहीं जानवरों के लिए भी परेशानी खड़ी हो जाती है।

● **अंकित पवार,** जबलपुर (म.प्र.)

लोकतंत्र के मंदिर में नोंकझोंक

पिछले कुछ सालों से देश के लोकतंत्र के मंदिर में जो तीखी नोंकझोंक हो रही है, वह बेहद शर्मनाक और अफसोसजनक है। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र के मंदिर संसद में पहले कभी इतनी तीखी बहस, वॉकआउट और एक-दूसरे के ऊपर छींटाकशी का दौर नहीं चला है। लेकिन जैसा पिछले कुछ सालों से संसद के अंदर हो रहा है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। सवाल यह है कि सांसदों की अभद्र और तल्ख भाषा से देश के लोगों की मानसिकता पर क्या असर पड़ेगा? वे एकता का पाठ कैसे सीखेंगे? क्या उनमें मतभेद पैदा नहीं होगा? क्या वे जगह-जगह लड़ने पर आमादा नहीं होंगे? ऐसा ही हाल राज्यों की विधानसभाओं का भी है। वहां भी मुख्य मुद्दों को दरकिनार करके आपस में झगने लगते हैं।

● **गीता श्रीवास्तव,** सीहोर (म.प्र.)

तैयार रहे विपक्ष

इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में विपक्ष को मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की जरूरत है। विपक्ष के पास जनता को बताने के लिए कोई काम या उपलब्धि नहीं है? क्या उसका सिर्फ यही काम है कि मोदी सरकार की निराधार निंदा करे, प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहे? राजनीति में सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों को काम करना पड़ता है। मोदी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की जो छवि बनाई है, क्या वैसी क्षमता किसी विपक्षी नेता में है? इन सभी सवालों को लेकर विपक्ष को तैयार रहना होगा।

● **जीवन यादव,** नई दिल्ली

चुनावी घमासान

मप्र में नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। नवंबर महीने के पहले हफ्ते में आचार संहिता लागू हो सकती है। ऐसे में अब पार्टियों के पास महज एक महीने का ही समय बचा है। चुनावी तैयारियों को लेकर एक तरफ जहां भाजपा ने जन आशीर्वाद यात्रा का मास्टर स्ट्रोक चलाया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी दिग्गज नेताओं को चुनाव प्रचार में उतारने की रणनीति बना चुकी है। वहीं तीसरे मोर्चे ने भी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है।

● **ऋषभ सिंह,** रायसेन (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

उप्र से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी!

अगले साल होने वाले आम चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस बड़ी योजना बना रही है। प्रदेश में अपनी खोई जमीन तलाशने के लिए कांग्रेस ने हाल ही में अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला है। माना जा रहा है कि अजय राय को उप्र कांग्रेस की कमान मिलने के पीछे कई राजनीतिक कारण हैं। जिसमें सबसे बड़ी वजह प्रियंका गांधी के उप्र से लोकसभा का चुनाव लड़ने के साथ ही पूर्वांचल में कांग्रेस को मजबूत किया जा सके। हालांकि प्रियंका गांधी उप्र की किस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगीं इसकी अभी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन, कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें चुनाव लड़ाने के लिए कांग्रेस संभावनाओं को तलाश रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने प्रियंका को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अभी तक जिन सीटों का चयन किया है उनमें प्रयागराज, फूलपुर और वाराणसी शामिल हैं। कहा जा रहा है कि इन तीन सीटों में से किसी एक सीट पर प्रियंका गांधी लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। संभावना यह भी है कि प्रियंका रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं क्योंकि सोनिया गांधी स्वास्थ्य कारणों से 2024 का चुनाव न लड़ने पर विचार कर रही हैं। उनके स्थान पर प्रियंका को रायबरेली से कांग्रेस चुनाव लड़ा सकती है। कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका कांग्रेस के लिए देशभर में प्रचार करती हैं।

एकला चलो की राह पर मायावती

इस साल होने वाले कई राज्यों के विधानसभा और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मायावती ने ट्वीट कर साफ किया कि उनकी पार्टी किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी। यानी मायावती न इंडिया और न ही एनडीए के साथ जाएंगी। बसपा सुप्रीमो ने एक के बाद एक ट्वीट कर कहा कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने इंडिया और एनडीए गठबंधन को सांप्रदायिक, पूंजीवादी और गरीब विरोधी पार्टियां बताकर कहा कि उनके साथ चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वहीं, बसपा चीफ ने कांग्रेस के वादे को हवा-हवाई बताते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सही तरह काम करती तो उसे सत्ता से बाहर ही नहीं होना पड़ता। हमारी पार्टी 2007 की तरह अकेले लोकसभा और राज्यों में होने वाले विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। हमारे साथ गठबंधन के लिए सब तैयार हैं लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं। इससे पहले भी बसपा सुप्रीमो ने अकेले चुनाव लड़ने की बात कही थी। मगर अब उन्होंने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि वह एकला चलो की राह पर हैं।

घर वापसी कर सकते हैं वरुण

बीते दिनों भाजपा के फायर ब्रांड नेता वरुण गांधी के बयानों के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। गांधी परिवार के बाबत दिए गए बयान से इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि वह अपने राजनीतिक भविष्य के लिए कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। बहन प्रियंका से उनके प्रेम को देखते हुए इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे घर वापसी कर सकते हैं। वरुण गांधी मौजूदा समय में पीलीभीत से सांसद हैं। इससे पहले भी वह दो बार सांसद रह चुके हैं। वह भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे हैं। उनकी मां मेनका गांधी भी केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं। लेकिन फिलहाल मां और बेटे दोनों ही खाली हाथ हैं। ऐसे में हाल ही में अपने संसदीय क्षेत्र के दो दिवसीय दौरे के दौरान वरुण गांधी ने इशारों में ही अपनी पार्टी को घेरते हुए कहा कि भारत माता की जय और जय श्रीराम के नाम पर वोट मांगने वालों को वोट न दें, क्योंकि उसके बाद आप एक मनुष्य नहीं रह जाते, सिर्फ एक आंकड़ा हो जाते हैं। आपका सम्मान नहीं रह जाता है। इसी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि गांधी परिवार उस किस्म का नहीं है, जो मीठी-मीठी बातें बताकर आपका वोट चोरी कर ले। वरुण गांधी के इस बयान पर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है।

पंजाब में लगेगा राष्ट्रपति शासन!

पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्यपाल ने मान सरकार पर संविधान के खिलाफ काम करने और उनके पत्रों का जवाब न देने का आरोप लगाया है। इस बीच बनवारीलाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री मान को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि अगर उनके पत्रों का जवाब नहीं दिया तो वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखेंगे और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करेंगे। पुरोहित ने यह भी चेतावनी दी कि वह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करेंगे। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच चल रहे तनाव के बीच पुरोहित ने मान से पंजाब में कथित तौर पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने से संबंधित उनके पत्रों का जवाब देने की मांग की है। पुरोहित ने पत्र में लिखा, मैं अगस्त महीने में ही कई पत्र आपको लिख चुका हूं। इन पत्रों के बावजूद, आपने अभी तक मेरे द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं दी है।

इंडिया का हिस्सा बनेगी इनेलो!

लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारी तेज कर दी है। 25 सितंबर को इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) देवीलाल की जयंती मनाएगी। माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे जिसके बाद इनेलो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो हरियाणा की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि इनेलो सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला ने पहले तो तीसरा मोर्चा बनाने की बात कही। इसके बाद उन्होंने भाजपा के खिलाफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से गठबंधन की इच्छा भी जाहिर की। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द इनेलो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। पार्टी के एकमात्र विधायक और वरिष्ठ नेता अभय चौटाला ने 24 फरवरी को नूंह से पदयात्रा शुरू की थी। इस पदयात्रा का समापन 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती पर कुरुक्षेत्र में होगा।

इकट्ठा हो गए सब साहेबान ?

झीलों की नगरी में विगत दिनों मप्र के मूल निवासी अखिल भारतीय सेवा के अफसरों का एक बड़ा जमावड़ा हुआ था, जो चर्चा का विषय बन गया है। यह आयोजन मप्र पुलिस के मुखिया ने किया था, जिसकी प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में चर्चा हो रही है। दरअसल, 1987 बैच के उक्त आईपीएस अधिकारी ने मप्र मूल के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भोपाल आमंत्रित किया था। पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक मप्र मूल के जितने भी अफसर विभिन्न राज्यों में विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं, उन्हें आमंत्रण भेजा गया था। सूत्रों के अनुसार इसमें लगभग वे सभी अफसर आए थे, जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस आदि के तहत देशभर में सेवाएं दे रहे हैं। इस आयोजन के पीछे साहब का उद्देश्य क्या था, यह तो सामने नहीं आया। यह बात जरूर सामने आई है कि अगले माह फिर यह बैठक आयोजित होने वाली है। इस बार इस बैठक की अध्यक्षता एक आईएफएस अधिकारी करने वाले हैं। इस बैठक को लेकर चर्चा होने लगी है कि आखिरकार किन कारणों से इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। देश में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है, जब देश के अन्य राज्यों में कार्यरत एक प्रदेश के मूल निवासी अखिल भारतीय सेवा के अफसरों की इस तरह की बैठक हो रही है। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक को लेकर अब सबकी नजर इस ओर हो गई है। लोग बैठक को लेकर तरह-तरह के कयास भी लगा रहे हैं।

आखिर कौन खेल बिगाड़ने पर तुला ?

चुनावी साल में राजनीतिक पार्टियों का सबसे अधिक फोकस इस बात पर है कि जैसे भी हो, हर वर्ग को साधा जाए। इसके लिए चुनावी साल में पार्टियों ने अपनी रणनीति और कार्यप्रणाली में भी पूरी तरह बदलाव कर लिया है। खासकर कुलीनों के कुनबे में विशेष बदलाव दिख रहा है। लेकिन विगत दिनों एक ऐसा माजरा सामने आया, जिससे लोग सवाल पूछने लगे कि आखिरकार इसके पीछे कौन है ? दरअसल, केंद्र सरकार का एक कमीशन प्रदेश में धर्मांतरण की पड़ताल करने आ धमका। सामान्यत: चुनाव के दौरान इस तरह के कमीशन नहीं आते हैं। फिर भी धर्मांतरण की पड़ताल करने के लिए गठित कमीशन प्रदेश में आ गया। गौरतलब है कि यह कमीशन एससी से मुसलमान और ईसाई बनने के मामलों की जांच करने के लिए गठित हुआ है। चुनावी साल में प्रदेश सरकार ने कमीशन को प्रदेश में न आने की बात कही थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रदेश सरकार की मनाही के बाद भी कमीशन प्रदेश में आ धमका। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस कदम से कुछ वर्गों की नाराजगी भी बढ़ी होगी। जबकि सरकार की कोशिश है कि जैसे भी हो, हर वर्ग को खुश किया जाए। यहां बता दें कि जिन साहब की अगुवाई में यह कमीशन गठित हुआ है, वे सुप्रीमो भी रह चुके हैं।

साहब की दरियादिली

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों एक आईएएस अधिकारी की दरियादिली का किस्सा लोग चटखारे लेकर सुन और सुना रहे हैं। दरअसल, साहब घूमने और घुमाने वाले विभाग में इन दिनों पदस्थ हैं। यहां साहब की तथाकथित तौर पर एक महिला अधिकारी से यारी हो गई है। इसका प्रमाण इससे भी मिलता है कि साहब ने हाल ही में उक्त महिला अधिकारी के खाते में अपने एसबीआई अकाउंट से राशि ट्रांसफर की है। इसको लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि साहब ने अपनी एक मातहत को पैसे ट्रांसफर किए हैं। इस प्रकरण को लेकर तरह-तरह की बातें की जा रही हैं। यहां बता दें कि अपनी पदस्थापना के बाद साहब ने सबसे पहले तो उक्त महिला अधिकारी के लिए पद खाली कराया। उस पद पर पहले एक पुरूष अधिकारी पदस्थ थे, जिन्हें हटाकर साहब ने अपनी महिला मित्र को पदस्थ किया। लोग अब इनकी जोड़ी को लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। इसमें हकीकत क्या है, यह तो साहब ही जानें। लेकिन यहां बता दें कि 2011 बैच के उक्त आईएएस बुंदेलखंड के एक जिले में भी कलेक्टर रह चुके हैं, जहां उनकी कार्यशैली के चलते कई विवाद पैदा हुए और तमाम राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों ने उन्हें हटाने की मांग की थी। यही नहीं साहब की अपने आशियाने में भी पटती नहीं है और वहां भी झगड़ा हो चुका है। यहां तक कि मामला थाने तक पहुंच चुका है।

हित सधा, विश्वास अर्जित नहीं

प्रदेश की राजधानी में एक महिला सीएसपी की पदस्थापना चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल, मैडम पर इन दिनों संघ के एक नेता मेहरबान हैं। वे प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ऐसे में उन्होंने अपने राजनीतिक रसूख का फायदा उठाते हुए उपरोक्त महिला अधिकारी को उनकी पसंद के क्षेत्र में सीएसपी बनवा दिया है। यहां बता दें कि मैडम ने बड़ा संघर्ष किया है और वे फॉरेस्ट गार्ड से एसएफ सूबेदार और फिर सीएसपी बनी हैं। मैडम की पदस्थापना करवाकर नेताजी ने अपना हित तो साध लिया, लेकिन इससे क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश सरकार के मंत्रीजी का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। दरअसल, मंत्रीजी उक्त क्षेत्र में अपनी पसंद के अफसर को सीएसपी बनवाना चाह रहे हैं। इसके लिए वे खूब हाथ-पांव मार रहे हैं, लेकिन संघ के पदाधिकारी के सामने उनकी एक नहीं चल पा रही है। इससे ऐसा हुआ है कि मंत्रीजी विश्वास अर्जित नहीं कर पाए हैं। अब देखना यह है कि सीएसपी के लिए छिड़ी यह जंग कहां तक पहुंचती है।

ये किस बात के मंत्री ?

शीर्षक पढ़कर आप भी आश्चर्यचकित हो रहे होंगे। लेकिन यह सवाल इन दिनों प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल, सबकी आर्थिक स्थिति का हिसाब-किताब रखने वाले मंत्रीजी के पास कुछ शिक्षक अपने तबादले के लिए पहुंचे। मंत्रीजी ने शिक्षकों का तबादला करवाने के लिए प्रयास शुरू किया। इसके लिए ऊपर से भी जोर लगवाया गया। लेकिन उसके बाद भी मंत्रीजी ने जिन अफसरों की सिफारिश भेजी थी, उनका तबादला आदेश जारी नहीं किया जा सका। इसके बाद जब दोबारा शिक्षक मंत्रीजी के पास पहुंचे तो उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि आप लोगों का तबादला आदेश जरूर निकलेगा। सूत्रों का कहना है कि उसके बाद मंत्रीजी खुद प्रमुख सचिव के पास पहुंचे और शिक्षकों के तबादले करने की बात कही। मंत्रीजी के इस रुख को देखकर अब हर कोई यही कह रहा है कि सभी विभागों का हिसाब-किताब रखने वाले मंत्रीजी किस बात के मंत्री हैं, जिनकी कोई सुन नहीं रहा है।

भाजपा शासित राज्यों में तेजी से विकास हो रहा है। अगर किसी को भाजपा द्वारा कराए गए विकास कार्यों को देखना है तो वह मप्र में आकर देखे। आज भाजपा सरकार ने बीमारू मप्र को विकासशील राज्य बना दिया है। आज मप्र विकास का पर्याय बना हुआ है।

● **नरेंद्र मोदी**

भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश को लूट डाला। उसका पैसा भाजपा नेताओं की जेब में पहुंच चुका है। 20-20 करोड़ रुपए प्रत्याशियों को दिए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत करके अपना काम चला रहे हैं। समय आने पर आचार संहिता लगने के आसपास ही टिकट वितरण का काम होगा। हमारे टिकट लगभग तय हैं। समय आने पर घोषित होंगे।

● **डॉ. गोविंद सिंह**

अंडर-19 वर्ल्डकप के दौरान मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ, उसका फायदा मैं अब उठा रहा हूं। मैं कोई प्री-प्लान बनाकर काम नहीं करता हूं। जैसा समय होता है, वैसा खेल दिखाना पड़ता है। एशिया कप में अभी तक मैंने जितने दांव चले हैं, वे सफल हुए हैं। मैं बॉलिंग के साथ ही बैटिंग पर भी पूरा ध्यान दे रहा हूं। टीम का मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है।

● **दुनिथ वेल्लालागे**

रूस के साथ बेहतर रिश्ते हमारी प्राथमिकता है। रूस अपने संप्रभुता और देश की रक्षा के लिए लड़ रहा है। हम साम्राज्यवाद के खिलाफ इस लड़ाई में हमेशा रूस के साथ थे और रहेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि मिलिट्री ऑपरेशन में रूस की हर हाल में जीत होगी।

● **किम जोंग उन**

मेरे पिता सबसे दुनिया के सबसे बेहतरीन पिता हैं। वह समय के साथ बदले और उन्होंने मुझे और मेरी बहन को फिल्मों में करियर बनाने के लिए मोटिवेट किया। आज भी जब वह मुझे फोन करते हैं और उन्हें पता चलता है कि मैं शूटिंग कर रही हूं, तो वह मुझे काम पर ध्यान देने की सलाह देते हैं। मेरे पिता एक बेहतरीन और खुले विचारों वाले इंसान हैं। वह हमेशा से ही हर चीज में बहुत अच्छे रहे हैं। वह अपने समय से बहुत आगे थे। वो मेरे दोस्त और गाइड भी हैं। 1970 के दशक में चीजें अलग थीं, वह समय बिल्कुल अलग था। वास्तव में हमारे परिवार की महिलाओं ने शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं किया था। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे पिता समय के साथ आगे बढ़े।

● **करीना कपूर**

वाक्युद्ध

देश में एक नया गठबंधन बना है, घमंडिया गठबंधन। यह गठबंधन भ्रष्टों और सनातन विरोधी पार्टियों का है। यह गठबंधन सनातन को समाप्त करना चाहता है। इसलिए देश में सनातन के विरोध में आवाज उठाई जा रही है। लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि सनातन का विरोध करने वालों को जनता ही चुप कराएगी।

● **जेपी नड्डा**

इंडिया गठबंधन को बदनाम करने के लिए भाजपा और उसके नेता तरह-तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। दरअसल, उन्हें अभी से हार का डर सताने लगा है। इसलिए वे बेवजह के मुद्दे उठाकर आरोप लगा रहे हैं। हम भाजपा से बड़े सनातनी हैं। लेकिन हम इसका प्रचार नहीं करते। भाजपा ने न तो हिंदू के लिए और न ही सनातन के लिए कुछ किया है।

● **राहुल गांधी**

आखिर कौन बचा रहा सरकार को चपत लगाने वालों को?

मप्र में सरकार सुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का दम भर रही है, वहीं दूसरी तरफ स्थिति यह है कि अफसर जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और भ्रष्टों के संरक्षक बने हुए हैं। ऐसा ही एक मामला मप्र ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण में सामने आया है। आलम यह है कि मप्र ग्रामीण सड़क योजना में एल/डी प्रकरणों (कार्यों में समय वृद्धि) में भारी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था और इसकी शिकायत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल में की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए ईओडब्ल्यू ने 04.10.2022 मुख्य कार्यपालन अधिकारी मप्र ग्रामीण सड़क विकास परियोजना से मामले से संदर्भित दस्तावेज मांगे थे, लेकिन विभाग की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई। उसके बाद ईओडब्ल्यू ने 01.12.2022 को पुन: पत्र लिखा। तब ईओडब्ल्यू की मांग पर प्राधिकरण की मुख्य महाप्रबंधक प्रशासन अर्चना सोलंकी ने 22.12.2022 को मुख्य महाप्रबंधक ग्वालियर, रीवा और सागर संभाग से दस्तावेज मंगाए थे, लेकिन तकरीबन एक साल बाद भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। दरअसल, इसके पीछे वजह यह थी कि एल/डी प्रकरणों में भारी भ्रष्टाचार करने का आरोप तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक मप्र ग्रामीण सड़क योजना केसी ध्रुवकर पर लगाया गया था। जब इसकी जानकारी मांगी गई तब ध्रुवकर प्रमुख अभियंता मप्र ग्रामीण विकास प्राधिकरण थे। उनका तबादला आदेश 04.08.2023 को निकला। तब तक उन्होंने विभाग और ईओडब्ल्यू द्वारा मांगी गई जानकारी न दी और न ही देने दी।

गौरतलब है कि विष्णुप्रसाद मेश्राम नामक व्यक्ति ने ईओडब्ल्यू में शिकायत की थी कि मप्र ग्रामीण सड़क योजना में पदस्थ मुख्य महाप्रबंधक केसी ध्रुवकर के द्वारा एल/डी प्रकरणों में ठेकेदारों से 2 प्रतिशत की राशि वसूल कर 68.78 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है तथा शासन को लगभग 217 करोड़ की हानि पहुंचाई गई है। मप्र शासन का नियम है कि यदि ठेकेदार द्वारा निर्धारित समयावधि से विलंब से कार्य कराया जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट वेल्यू के 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से एल/डी राशि अधिरोपित की जाती है और अधिकतम 10 सप्ताह का विलंब होने पर अधिकतम 10 प्रतिशत की राशि ठेकेदार से वसूल कर शासन के खाते में जमा की जाती है। इसमें कार्यवाही का अधिकार मप्र शासन ने मुख्य महाप्रबंधक को दिया गया है और ध्रुवकर इस पद पर 8 वर्ष से अधिक समय रह चुके हैं। वे ग्वालियर, सागर एवं रीवा संभाग के प्रभारी भी रहे हैं। इस दौरान इन्होंने तीनों संभागों के ठेकेदारों द्वारा विलंब से किए गए कार्य में नियमानुसार एल/डी न लगाते हुए 0 प्रतिशत अथवा 1 प्रतिशत से कम लगाई है। जिसके एवज में उन्होंने समान रूप से 2 प्रतिशत की ठेकेदारों से अवैध वसूली की है। जिसकी राशि 68.78 करोड़ रुपए होती है।

मेश्राम की शिकायत के अनुसार ध्रुवकर द्वारा 327 प्रकरणों में से 285 प्रकरणों में यानि 87 प्रतिशत में 0 अथवा 1 प्रतिशत की एल/डी अधिरोपित की गई है। जबकि यह सब कार्य 10 हफ्ते के विलंब के हैं जिसमें शासन के नियमानुसार 10 प्रतिशत एल/डी अधिरोपित की जानी थी। इस प्रकार ध्रुवकर ने शासन को 217 करोड़ की हानि पहुंचाई तथा 68.78 करोड़ रुपए व्यक्तिगत तौर पर प्राप्त किए।

ठेकेदारों और ध्रुवकर की मिलीभगत से सरकार को करोड़ों रुपए की चपत लगाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए ईओडब्ल्यू ने 04.10.2022 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी मप्र ग्रामीण सड़क विकास परियोजना को पत्र भेजा। जिसे 06.10.2022 को प्राधिकरण मुख्यालय ने प्राप्त भी कर लिया। इस पत्र के माध्यम से ईओडब्ल्यू ने विभाग से 5 बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। लेकिन उसकी जानकारी एक महीने के अंदर नहीं भेजी गई तो ईओडब्ल्यू ने 22.12.2022 को दूसरा पत्र भेजा। इस बार मुख्य महाप्रबंधक ग्वालियर, रीवा और सागर संभाग को भेजा गया। जिसका प्रभार ध्रुवकर के पास था। ध्रुवकर का तबादला आदेश 04.08.2023 को निकला। तब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। अब इनके हटने के बाद दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं। इस संदर्भ में प्रमुख अभियंता मप्र ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण एमएल डाबर ने बताया कि सीजीएम प्रशासन के 22.12.2022 को लिखे गए पत्र के जवाब में ग्वालियर एवं सागर के मुख्य महाप्रबंधक ने जानकारी भेज दी है, जबकि रीवा से जानकारी आना शेष है।

● **जितेंद्र तिवारी**

ईओडब्ल्यू ने मांगी थी ये जानकारियां

ईओडब्ल्यू ने 04.10.2022 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी मप्र ग्रामीण सड़क विकास परियोजना को पत्र लिखकर कहा था कि मुख्य महाप्रबंधक के द्वारा एल/डी प्रकरणों में भ्रष्टाचार कर शासन को करोड़ो रुपए की हानि पहुंचाने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। अत: अविलंब मय दस्तावेजों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। ईओडब्ल्यू ने जानकारी मांगी थी कि यदि ठेकेदार द्वारा निर्धारित समयावधि से विलंब से कार्य किया जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट वेल्यू के 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से एलडी राशि अधिरोपित की जाती है। ओर अधिकतम 10 सप्ताह का विलंब होने पर अधिकतम 10 प्रतिशत की राशि ठेकेदार से वसूल कर शासन के खाते में जमा की जाती है। उक्त संबंध में मप्र शासन के दिशा-निर्देश एवं नियमावली की छायाप्रति उपलब्ध कराएं। विगत 8 वर्षों में ग्वालियर संभाग के 137, रीवा संभाग के 83 व सागर संभाग के 107 एल/डी प्रकरण निर्णित कर कार्यवाही का अधिकार मप्र शासन द्वारा किस मुख्य महाप्रबंधक को दिया गया था उनका नाम, पदनाम, वर्तमान पदस्थापना एवं सेवानिवृत्ति दिनांक उपलब्ध कराएं। उपरोक्त ग्वालियर संभाग के 137 रीवा संभाग के 83 व सागर संभाग के 107 एल/डी प्रकरणों में की गई समस्त कार्यवाही के समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति उपलब्ध कराएं। शिकायत अनुसार ग्वालियर संभाग के 137 एल/डी प्रकरणों में से 73 प्रकरणों में कॉन्ट्रैक्ट वेल्यू का 0 प्रतिशत व 49 प्रकरणों में कॉन्ट्रैक्ट वेल्यू का 1 प्रतिशत, रीवा संभाग के 83 एल/डी प्रकरणों में से 51 प्रकरणों में कॉन्ट्रैक्ट वेल्यू का 0 प्रतिशत व 24 प्रकरणों में कॉन्ट्रैक्ट वेल्यू का 1 प्रतिशत, सागर संभाग के 107 एल/डी प्रकरणों में से 67 प्रकरणों में कॉन्ट्रैक्ट वेल्यू का 0 प्रतिशत व 21 प्रकरणों में कॉन्ट्रैक्ट वेल्यू का 1 प्रतिशत एल/डी अधिरोपित की गई, जबकि यह सब कार्य 10 हफ्ते के विलंब के हैं जिसमें शासन को नियमानुसार 10 प्रतिशत, एल/डी अधिरोपित की जानी थी। इस संबंध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन दस्तावेजों की छायाप्रति उपलब्ध कराएं। उपरोक्त 285 प्रकरणों में कितने सप्ताह का विलंब हुआ प्रत्येक की सूचीवार जानकारी उपलब्ध कराएं।

मप्र में विधानसभा चुनाव में वोटरों को रिझाने के लिए इस वक्त घोषणाओं का दौर चल रहा है। सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा और कांग्रेस में घोषणा करने की एक होड़ सी लगी हुई है। सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगभग हर दिन कुछ न कुछ घोषणा कर रहे हैं तो विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से भाजपा की काट के लिए उससे बढ़कर घोषणाएं की जा रही है। दरअसल, कांग्रेस सत्ता में लौटने के लिए घोषणाओं के भरोसे है।

अबकी बार गारंटियों की भरमार

विधानसभा चुनाव से 3 माह पहले मप्र की राजनीति दिलचस्प दौर में है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां रणनीतिक रूप से हॉकी की तरह पोजीशन बदलकर खेलने की कोशिश में हैं और इसी आधार पर चुनावी मैच जीतने की 100 फीसदी उम्मीद पाले हुए हैं। मसलन एक तरफ जहां अमूमन धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाली मध्यमार्गी कांग्रेस आजकल हिंदुत्व की रामनामी माला जप रही है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर शिवराज सरकार को घेर रही है तो दूसरी तरफ तो मुफ्तखोरी के लिए आम आदमी पार्टी को कोसने वाली भाजपा खुद दोनों हाथों से रेवड़ियां बांटने में लगी है। उधर पहली बार बड़े पैमाने पर चुनाव मैदान में उतरने का दावा करने वाली आप असमंजस में है कि वो कौन सी राह पकड़े।

साल के अंत में देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से एक राज्य मप्र भी है जहां मतदाताओं को लुभाने के लिए तमाम राजनीतिक दल तरह-तरह के वादे और गारंटियां दे रहे हैं। गत दिनों भाजपा सरकार ने महिलाओं के लिए सम्मान राशि, किफायती गैस सिलेंडर और सस्ती बिजली मुहैया कराने का वादा किया। तो वहीं कांग्रेस ने अपनी चुनावी गारंटियों को 6 से बढ़ाकर अब 11 वचन कर दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 27 अगस्त को जंबूरी मैदान भोपाल में लाड़ली बहना सम्मेलन में कई घोषणाएं कीं। उन्होंने रक्षाबंधन पर महिलाओं के खाते में 312.64 करोड़ रुपए की राशि डाली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में बहनों को प्रतिमाह दी जा रही 1000 रुपए की राशि के स्थान पर अक्टूबर माह से 1250 रुपए की राशि दी जाएगी। राखी पर्व पर प्रत्येक बहन को उपहार के रूप में 250 रुपए दिए जा रहे हैं। बहनों के खाते में 10 सितंबर को योजना के एक हजार रुपए डाले जाएंगे। इसके बाद अक्टूबर माह से 1250 रुपए की राशि दी जाएगी।

दरअसल, राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस बार छह चुनावी गारंटियों के साथ राज्य में चुनाव के लिए उतरी है। लाड़ली बहना के बाद कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना की घोषणा कर दी। इसमें उन्हें 1,500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया था। पार्टी की तरफ से हजारों महिलाओं के फॉर्म भरवाए गए। हालांकि, मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहना की राशि 1,250 रुपए कर दी। इसे 3000 तक करने की घोषणा मुख्यमंत्री कई बार कर चुके हैं।

एक अन्य घोषणा में मुख्यमंत्री ने कहा कि सावन के अवसर पर लाड़ली बहनों को एक रसोई गैस सिलेंडर 450 रुपए में पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि लाड़ली बहनों के हित में रसोई गैस सिलेंडर के लिए आगे स्थायी व्यवस्था की जाएगी। राज्य शासन संबंधित गैस एजेंसी से जानकारी प्राप्त करेगी और सावन के इस पवित्र अवसर पर लाड़ली बहनों को 600 रुपए प्रतिमाह तक की राशि की प्रतिपूर्ति उनके बैंक खातों में राशि डालकर की जाएगी। ताकि बहनों को रसोई गैस सिलेंडर की लागत 450 रुपए ही आए।

कांग्रेस की चुनावी गारंटियों में से एक किफायती दाम में रसोई गैस सिलेंडर मुहैया कराना भी था। कांग्रेस ने कहा था कि राज्य में उसकी सरकार आई तो महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। अब भाजपा सरकार ने इससे 50 रुपए और कम करने की घोषणा कर दी। अपने भाषण में शिवराज सिंह ने कहा कि सरकार फैसला करती है कि बढ़े हुए बिजली के बिलों की वसूली नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गरीब बहन का बिल हर महीने 100 रुपए आए, इसका इंतजाम किया जाएगा। वहीं, इससे पहले कांग्रेस ने 100 यूनिट बिजली फ्री देने और 200 यूनिट तक का बिल आधा माफ करने का ऐलान किया था। इसके जवाब में

कमलनाथ की राजनीतिक दिशा किस ओर है?

ये देश सभी धर्मों का है। हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या बात है, 82 फीसदी लोग तो हिंदू हैं। कमलनाथ की इस व्याख्या से कांग्रेस में ही बहुत से लोग सहमत नहीं हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने तो छिंदवाड़ा में पं. धीरेंद्र शास्त्री की कथा कराने पर ही सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना था कि धीरेंद्र शास्त्री राजनीतिक पार्टी का वरदहस्त है, सबको पता है। दूसरे, कमलनाथ की यह लाइन पार्टी के एक और दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह की विचारधारा से मेल नहीं खाती। निजी तौर पर खांटी हिंदू होने के बाद भी राजनीतिक स्तर पर दिग्विजय धर्मनिरपेक्षता के अडिग समर्थक हैं। कमलनाथ की इस लाइन पर कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेताओं में भी शंका है और एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने तो इसकी खुलकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जिस लाइन पर चल रहे हैं, वो तो आरएसएस की है। भाजपा तो हिंदू धर्म की बात करने वाले हिंदुओं को इच्छाधारी हिंदू पहले ही घोषित कर चुकी है। बहरहाल, कमलनाथ ने जो कहा वो तथ्यात्मक रूप से सही है, क्योंकि इस देश की 82 फीसदी आबादी हिंदू है। इस अर्थ में यह बहुसंख्यक हिंदुओं का देश ही है।

मुख्यमंत्री ने बिजली बिल 100 रुपए महीना करने की घोषणा कर दी।

उधर 17 जुलाई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शाजापुर जिले में प्रदेश के पहले सीएम राइज विद्यालय का लोकार्पण किया था। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सीएम राइज स्कूलों में विश्वस्तरीय शिक्षा निशुल्क प्रदान की जाएगी। गरीबों के बच्चे फ्री में यहां पढ़ेंगे। सीएम राइज स्कूल मतलब शानदार बिल्डिंग, अच्छा क्लासरूम, स्मार्ट क्लास, दिल्ली-मुंबई का शिक्षक स्मार्ट क्लास में ऑनलाइन बैठकर पढ़ा सकेगा। प्रयोगशाला, खेल मैदान, अच्छा पुस्तकालय होगा। स्वीमिंग पूल होगा। इन स्कूलों तक पहुंचने के लिए बस चलाई जाएगी। बच्चों को बस से घर ले जाएंगे, स्कूल छोड़ेंगे। आवागमन की सुविधा, तैरने की सीख के लिए स्वीमिंग पूल बनाएंगे। उधर कुछ दिनों पहले शिवराज सरकार ने प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के लिए कई घोषणाएं की थीं। उन्होंने कहा था कि प्रदेश में अब संविदा कर्मचारियों की वार्षिक अनुबंध प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। अब प्रदेश के सवा लाख से अधिक संविदा कर्मचारियों को 90 प्रतिशत के स्थान पर 100 प्रतिशत वेतन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन, भत्ते, ग्रेच्युटी और बीमा देने की घोषणा की थी। इसके साथ ही संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह छुट्टियां, सीएल, ईएल, ऐच्छिक अवकाश और अनुकंपा नियुक्तियां भी दी जाएंगी।

आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सतना में बेरोजगार युवाओं को तीन हजार रुपए के मासिक भत्ते के अलावा मुफ्त बिजली, चिकित्सा उपचार और गुणवत्तापूर्ण स्कूलों के निर्माण सहित कई गारंटियों का आश्वासन दिया था। केजरीवाल ने आगे कहा कि अगर सत्ता में आए तो आप सरकार मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए गुणवत्तापूर्ण स्कूलों का निर्माण करेगी। उन्होंने कहा कि (हम अस्पतालों में 20 लाख रुपए की लागत वाले परीक्षण और सर्जरी सहित मुफ्त इलाज प्रदान करेंगे) और बेरोजगार युवाओं को तीन हजार रुपए प्रतिमाह का बेरोजगारी भत्ता

प्रदान करेंगे। बिजली के मोर्चे पर, आप नेता ने 24 घंटे निर्बाध आपूर्ति के साथ 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा किया। उन्होंने कहा कि अगर आप सत्ता में आई तो 30 नवंबर तक बकाया बिजली बिल माफ कर दिए जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि अस्थायी या संविदा नौकरियों में लगे कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने दिल्ली और पंजाब का उदाहरण दिया जहां आप सत्ता में है। केजरीवाल ने कहा कि अगर मप्र की सत्ता में आप की सरकार आई तो उन बुजुर्ग लोगों के लिए तीर्थ दर्शन योजना लागू करेगी जो अपनी पसंद के स्थान पर तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सैनिकों और कांस्टेबलों समेत अन्य लोगों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। केजरीवाल ने कहा कि विस्तृत योजना तैयार कर किसानों और आदिवासियों के लिए अलग से घोषणा की जाएगी। हालांकि, मप्र सरकार ने जून 2012 में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना में प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को देश के चिन्हित तीर्थ स्थल की निशुल्क यात्रा कराई जाती है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लाड़ली बहना सम्मेलन में शामिल होने से पहले कमलनाथ ने भाजपा को चित करने जनता को 11 बड़ी सौगात देने का वादा किया है। साथ ही बड़ा हमला करते हुए कहा कि शिवराज सरकार जनता को राहत देने नहीं बल्कि अपनी डूबती नैय्या को बचाने रोज मुखौटे बदल रही है।

पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मप्र की जनता को 11 वचन दिए हैं। इसके साथ पीसीसी चीफ ने कहा कि अपने 11 वचनों के साथ मप्र के हर घर में खुशहाली लाने के संकल्प के साथ आपके बीच है। मप्र की जनता को सुनिश्चित करना है कि वोटों की बोली लगाने वाली सौदागर सरकार के नापाक मंसूबे कामयाब न हों। अब सच्चाई की राजनीति को ही समर्थन और आशीर्वाद मिले। कमलनाथ ने कहा कि मैं बार-बार दोहरा रहा हूं कि भाजपा सरकार इस समय जनता को राहत देने के लिए बनीं बल्कि अपनी डूबती नैय्या बचाने के लिए रोज मुखौटे बदल रही है। 18 साल के शासनकाल के बाद भी जिन्हें चुनावी चाल चलना पड़े, वो दल और उनकी सरकार बनावटी, दिखावटी और सजावटी है। जो जनता का कभी हित नहीं चाह सकती है।

कांग्रेस के वचनों में महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली बिल माफ और 200 यूनिट का हाफ, किसानों का सपुल कर्ज माफ, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ, किसानों का 5 हॉर्स पावर बिजली बिल माफ, 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का लाभ, 12 घंटे सुनिश्चित सिंचाई बिजली का रास्ता साफ, जातिगत जनगणना का लाभ और किसान आंदोलन के मुकदमे माफ आदि शामिल हैं।

● **कुमार विनोद**

भाजपा के लिए चुनौती ना बन जाएं कमलनाथ?

कमलनाथ का प्रयोग यदि सफल रहा तो भाजपा और आरएसएस को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा, अन्यथा विधानसभा चुनाव में खुद कमलनाथ और उनकी पार्टी कांग्रेस के हिट विकेट होने का खतरा ज्यादा है। डर यह भी है कि खुद को बेहतर हिंदू साबित करने के चक्कर में कांग्रेस अल्पसंख्यक वोट और हिंदुओं के पारंपरिक वोट से भी हाथ न धो बैठे। यह भी संभव है कि जो वोटर कांग्रेस को भाजपा के विकल्प के रूप में स्वीकार करने को मानसिक रूप से तैयार हैं, वह दूसरे विकल्पों जैसे कि आम आदमी पार्टी की तरफ झुके। इससे चुनाव नतीजों का समीकरण गड़बड़ा सकता है। कम से कम कांग्रेस के पक्ष में तो नहीं ही होगा। अब सवाल यह है कि कमलनाथ आखिर इतना रिस्की दांव क्यों चल रहे हैं? क्या उनका मकसद कांग्रेस को निर्णायक रूप से सत्ता पर काबिज कराना है या फिर छिंदवाड़ा में विधायक के रूप में अपनी और सांसद के रूप में अपने पुत्र नकुलनाथ की सीट सुरक्षित करना है? क्या वो मानते हैं कि छिंदवाड़ा में कथा प्रवचन का राजनीतिक महापुण्य कांग्रेस को पूरे प्रदेश में मिलेगा और कांग्रेस पर लगा अहिंदू होने का चोला खुद-ब-खुद तार-तार हो जाएगा?

विवादों में फंसा मास्टर प्लान

एक बार फिर ऐसा लगता है कि भोपाल का मास्टर प्लान अधर में लटक जाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मास्टर प्लान से न तो भाजपा के और न ही कांग्रेस के विधायक और नेता खुश हैं। इस कारण मास्टर प्लान विवादों में फंस गया है। हालांकि भोपाल मास्टर प्लान-2031 में आई कुल 3005 आपत्तियों की सुनवाई पूरी हो गई है। सुनवाई के बाद इसे विभागीय मंत्री के पास भेज दिया गया है। वहां से मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मास्टर प्लान अधर में लटक सकता है।

गौरतलब है कि वर्तमान में सत्तापक्ष और विपक्ष का पूरा फोकस विधानसभा चुनाव पर है। ऐसे में मास्टर प्लान पर किसी की नजर नहीं जा रही है। हालांकि मास्टर प्लान की आपत्तियों पर सुनवाई के अंतिम दिन जमकर हंगामा हुआ था। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा, कांग्रेस नेता नरेश ज्ञानचंदानी समेत किसानों ने कृषि भूमि को कैचमेंट एरिया में शामिल करने समेत कई बिंदुओं पर नाराजगी जताई थी। इसके चलते एक घंटा पहले ही सुनवाई बंद हो गई। बता दें कि भोपाल के मास्टर प्लान का ड्राफ्ट 2 जून को सरकार ने जारी कर दिया था। ड्राफ्ट जारी होने के 30 दिन के अंदर कुल 3005 आपत्तियां और सुझाव मिले। इनकी सुनवाई छह चरणों में हुई। प्रथम चरण में 9 से 11 अगस्त तक, द्वितीय चरण में 16 से 18 अगस्त तक, तीसरे चरण की सुनवाई 21 से 25 अगस्त तक चली। वहीं, चतुर्थ चरण 28 से 29 अगस्त तक, पांचवें चरण में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक सुनवाई की गई। छठवें एवं अंतिम चरण में 4 से 5 सितंबर तक सुनवाई की गई।

कांग्रेस नेता ज्ञानचंदानी ने भी नए मास्टर प्लान को लेकर अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराई। ज्ञानचंदानी ने नगरीय प्रशासन के अधिकारियों को बताया कि नए मास्टर प्लान में बैरागढ़ से सीहोर रोड तक की जमीनों का उपयोग कृषि से हटाकर कैचमेंट में प्रस्तावित किया है, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से 2 दिक्कतें हो रही हैं। पहली बैरागढ़ की आबादी तीन गुना तक बढ़ चुकी है, उसके हिसाब से मास्टर प्लान में कोई प्लानिंग नहीं है। इसी कारण आसपास की जमीनों पर अवैध रूप से कॉलोनियां काटी जा रही हैं। इस पर ध्यान दिया जाए तो विकास का पैमाना तय हो सकता है। बड़े दुख की बात है कि अब तक कैचमेंट से लगी हुई जो कृषि भूमि थी, उन्हें भी पूरी तरह से कैचमेंट में शामिल किया जा रहा है, जबकि कमलनाथ सरकार के वक्त जो मास्टर प्लान आया था उसमें तालाब से महज 50 मीटर तक ही कैचमेंट एरिया था। कैचमेंट से लगी अधिकांश कृषि भूमि पर अभी खेती की जा रही है, जिसमें भारी मात्रा में पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है, जो कि सीधे तालाब में पहुंच रहा है। यदि तालाब के पानी की जांच कराएंगे तो पूरा पानी जहरीला मिलेगा।

कमलनाथ सरकार के मास्टर प्लान में वीआईपी रोड की तर्ज पर तालाब के किनारे रीवर फ्रंट में सड़क का प्लान तैयार किया गया था। अगर ये रोड बन जाता है तो न सिर्फ तालाब संरक्षित होगा बल्कि तालाब की सीमा में होने वाले अतिक्रमण और खेती के कारण तालाब में मिल रहे पेस्टिसाइड पर भी रोक लग सकेगी। तालाब किनारे से सड़क बनाने से तालाब का सौंदर्य बढ़ेगा और तालाब संरक्षित होगा। देश के नक्शे में यह एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में अपनी पहचान बना पाएगा।

मास्टर प्लान में बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया में कृषि भूमि को शामिल कर दिया गया है। इसके चलते किसान भी नाराज हैं। भौंरी, भैंसाखेड़ी, लालघाटी, काजीपुरा, संत हिरदाराम नगर, रायसेन रोड, अशोक विहार कॉलोनी, बीडीए कॉलोनी कोहेफिजा, ईदगाह हिल्स, जमोनियाछीर, अरेरा कॉलोनी, नीलबड़, रातीबड़, कोलार रोड, नर्मदापुरम रोड, हथाईखेड़ा, रायसेन रोड, पुराने शहर, करोंद समेत शहर के अलग-अलग इलाकों के लोगों ने भी आपत्तियां दर्ज कराई थीं। ड्राफ्ट पर आई आपत्तियों के आधार पर शहर के बाहरी इलाके में बेस एफएआर 0.25 से बढ़ाकर 1 किया जा रहा है। अरेरा कॉलोनी और विजय नगर में भी बेस एफएआर 0.75 से बढ़ाकर 1 होगा। शहर के बाहरी इलाके में बेस एफएआर 0.25 से बढ़ाकर 1 किया जा रहा है। अरेरा कॉलोनी और विजय नगर में भी बेस एफएआर 1 और प्रीमियर एफएआर 0.25 यानी कुल 1.25 होगी। अवधपुरी से हथाईखेड़ा के ड्राफ्ट में 24 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रावधान किया गया। यह भी निरस्त की गई।

● **प्रवीण सक्सेना**

रामेश्वर शर्मा ने अफसरों को सुनाई खरी-खोटी

गौरतलब है कि इस बार मास्टर प्लान की आपत्तियों पर ऑनलाइन सुनवाई की गई। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने मास्टर प्लान-2031 को शहर के लाखों रहवासियों के साथ धोखा बताया है। साथ ही इसे अमलीजामा पहनाने वाले अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। इसके प्रस्तावों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शर्मा ने कहा कि प्रस्तावित मास्टर प्लान बिना भौतिक सत्यापन और शहर की परिस्थितियों को समझे बिना ही आंख बंद करके बना दिया गया है। 60-70 वर्षों से लेकर 100 साल तक पुराने गांव हैं जो कि अब नगर निगम सीमा में हैं उनकी भूमि कृषि थी। उनकी भूमि को ग्रीन बेल्ट और कैचमेंट में डाल दिया गया है, जिसके कारण वह अपनी भूमि पर खेती से संबंधित भी कोई उपक्रम या डेयरी आदि भी संचालित नहीं कर पाएंगे। ऐसे में उनके बेटा-बेटी कहां जाएंगे। इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। ऐसे किसानों के परिवार का जीवन-यापन कैसे होगा। मास्टर प्लान इंसानों के लिए होता है, लेकिन प्रस्तावित प्लान से इंसानों को बेघर किया जा रहा है। शर्मा ने बताया कि कलेक्टर के आदेश से जिन बस्तियों को पुनः बसाया गया है, उसे भी कैचमेंट में डाल दिया गया है। नीलबड़ की 45 कॉलोनियों सहित रातीबड़, नीलबड़ एवं अन्य क्षेत्रों में सैकड़ों अवैध कॉलोनियों को मुख्यमंत्री ने वैध घोषित किया है, लेकिन प्रस्तावित मास्टर प्लान में इस एरिया को कैचमेंट में डालकर लोगों को बेघर करने का काम किया जा रहा है। विधायक शर्मा ने आपत्तियों पर जनसुनवाई के दौरान मांग की है कि जिसने भी भोपाल का मास्टर प्लान बिना देखे आंख बंद करके चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया है, उसकी जांच होना चाहिए।

चकाचक होंगी सड़कें

मप्र में विधानसभा चुनाव के पहले शहरी क्षेत्र की सड़कों के सुधार को लेकर सरकार इतनी सतर्क है कि टेंडर की शर्तों में बदलाव के साथ-साथ नगरीय निकायों को राशि का आवंटन भी कर दिया। ताकि वह अगले 15 दिन में टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर लें। साथ ही इसी माह सड़कों के काम चालू करने के लिए वर्क ऑर्डर जारी कर सकें। बता दें कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में चुनाव आचार संहिता लगना तय है। इसलिए अक्टूबर के पहले सप्ताह में प्रदेश के सभी 413 नगरीय निकायों में सड़कों के उन्नयन और पुल, पुलिया संबंधी अन्य कार्य तेजी से शुरू किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि आचार संहिता लागू होने के पहले शुरू होने वाले काम अनवरत चलते रहेंगे। इसलिए सड़कों के मेंटनेंस का काम 5 अक्टूबर से पहले शुरू कर दिया जाए।

नगरीय विकास और आवास विभाग ने कायाकल्प योजना 2.0 के अंतर्गत प्रदेश के 16 नगर निगमों में सड़कों के उन्नयन और निर्माण पर खर्च होने वाली राशि का आवंटन कर दिया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर नगर निगमों के लिए सबसे अधिक 18-18 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अलावा उज्जैन, देवास, मुरैना, सतना, सागर, रतलाम, रीवा, कटनी, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर और खंडवा नगर निगम के लिए पांच-पांच करोड़ रुपए खर्च करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। नगर निगम कमिश्नर, नगर पालिका और नगर परिषद सीएमओ को जारी निर्देश में कहा गया है कि यह सभी काम करने के दौरान पुल-पुलिया, ड्रेनेज, डिवाइडर और सेंट्रल लाइटिंग आदि का काम भी शामिल रहेगा। कायाकल्प योजना 2.0 के प्रस्तावों और सिटी रोड एक्शन प्लान का मेयर इन काउंसिल और प्रेसिडेंट एंड काउंसिल से अनुमोदन प्राप्त कर संभागीय अधीक्षण यंत्री की अनुशंसा के साथ शासन को जानकारी देना होगा। पात्रता से अधिक राशि परियोजना में खर्च होने पर अतिरिक्त राशि की व्यवस्था नगर निगमों, नगर पालिका, नगर परिषदों को खुद करनी पड़ेगी। इन सब कामों की जांच राज्य शासन द्वारा अर्बन स्टेट क्वालिटी मॉनीटर्स के माध्यम से कराई जाएगी।

इसी तरह सभी संभागों के अंतर्गत आने वाले नगरीय निकायों नगर पालिका परिषद और नगर परिषद के लिए संभागवार राशि का आवंटन किया गया है। सतना जिले की नगर पालिका मैहर को 2 करोड़, नगर परिषद डभौरा को 90 लाख, चित्रकूट, नागौद, न्यू रामनगर के लिए 90-90 लाख रुपए और नगर परिषद मऊगंज के लिए डेढ़ करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अलावा नगर पालिका सीधी के लिए 2 करोड़, नगर परिषद सरई के लिए 90 लाख, बरगांव के लिए 90 लाख, नगर पालिका शहडोल के लिए 2 करोड़, नगर पालिका धनपुरी के लिए 1.20 करोड़, नगर पालिका बिजुपी के लिए 1.20 करोड़, नगर पालिका अनूपपुर के लिए डेढ़ करोड़, नगर पालिका उमरिया के लिए डेढ़ करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

नगर पालिका बीना, मकरोनिया और खुरई के लिए 2-2 करोड़ रुपए, छतरपुर के लिए 2.30 करोड़, टीकमगढ़ के लिए 2 करोड़, दमोह के लिए 2.30 करोड़, निवाड़ी के लिए डेढ़ करोड़, पन्ना के लिए 2 करोड़, राजगढ़ के लिए डेढ़ करोड़, नगर पालिका रायसेन के लिए 1.20 करोड़, नगर पालिका मंडीदीप के लिए 2 करोड़, नगर पालिका मऊगंज के लिए डेढ़ करोड़, गंजबासौदा के लिए 2 करोड़, विदिशा के लिए 2.30 करोड़, नगर पालिका सीहोर के लिए 2.30 करोड़, नगर पालिका आष्टा के लिए 2 करोड़, नगर पालिका नर्मदापुरम के लिए 2.30 करोड़, नगर पालिका इटारसी के लिए 2 करोड़, नगर पालिका बैतूल के लिए 2.30 करोड़, नगर पालिका सारणी के लिए 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं। विभाग द्वारा जिन अन्य प्रमुख निकायों के लिए राशि सड़कों के सुधार के लिए दी गई है उसमें नगर पालिका हरदा के लिए 2 करोड़, नगर पालिका खरगोन के लिए 2.30 करोड़, नगर पालिका झाबुआ के लिए डेढ़ करोड़, नगर पालिका पीथमपुर के लिए 2.30 करोड़, नगर पालिका धार के लिए 2 करोड़, नगर पालिका सेंधवा के लिए 2 करोड़, नगर पालिका बड़वानी के लिए 2 करोड़, नगर पालिका डबरा के लिए 2.30 करोड़, नगर पालिका अशोकनगर के लिए 2 करोड़, नगर पालिका गुना के लिए 2.30 करोड़, नगर पालिका राघौगढ़ के लिए 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

इसी प्रकार नगर पालिका दतिया के लिए 2.30 करोड़, नगर पालिका शिवपुरी के लिए 2.30 करोड़, नगर पालिका भिंड के लिए 2.30 करोड़, नगर पालिका गोहद के लिए 2 करोड़, नगर पालिका बालाघाट के लिए 2 करोड़, नगर पालिका मंडला के लिए डेढ़ करोड़, नगर पालिका डिंडोरी के लिए डेढ़ करोड़, नगर पालिका नागदा के लिए 2.30 करोड़, नगर पालिका आगर के लिए डेढ़ करोड़, नगर पालिका नीमच के लिए 2.30 करोड़, नगर पालिका मंदसौर के लिए 2.30 करोड़, नगर पालिका शुजालपुर के लिए 2 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा अन्य नगर निगम परिषदों को 1.20 करोड़, 90 लाख और 50 लाख रुपए का आवंटन सड़कों के मेंटेनेंस के लिए किया गया है।

● **बृजेश साहू**

घटाई गई निविदा अवधि

नगरीय निकायों की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत समय-सीमा में कराने के उद्देश्य से निविदा अवधि में कमी की गई है। अब मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना, कायाकल्प योजना, विशेष निधि एवं अन्य राज्य प्रवर्तित योजनाओं में स्वीकृत सड़कों तथा अधोसंरचना विकास कार्यों में 10 लाख रुपए से अधिक मूल्य की निविदाओं के लिए प्रथम आमंत्रण में 10 दिन तथा द्वितीय आमंत्रण में 7 दिन की अवधि निर्धारित की गई है। यह छूट 15 अक्टूबर 2023 तक आमंत्रित की गई निविदाओं पर प्रभावशील रहेगी। पूर्व में यह अवधि क्रमशः 30 तथा 15 दिवस थी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह बताया है कि सभी 413 नगरीय निकायों में सड़कों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। इस कार्य के लिए अन्य मदों के अतिरिक्त कायाकल्प योजना के प्रथम चरण में 350 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा द्वितीय चरण में स्वीकृत 800 करोड़ रुपए में से 470 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नगरीय स्टेट क्वालिटी मॉनीटर नियुक्त किए गए हैं। गुणवत्ता नियंत्रण के उद्देश्य से गोपनीयता के लिए सैंपल की बार-कोडिंग कर रैंडम लैब का चयन कर टेस्टिंग की जाएगी।

10 लाख से अधिक अभिमन्यु

बाल्यकाल से ही पुरुषों में लैंगिक समानता और महिलाओं के प्रति विशेष सम्मान की भावना जाग्रत कर उन्हें महिला अपराधों के प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से मप्र पुलिस द्वारा अभिमन्यु अभियान का संचालन किया गया। प्रथम चरण की भांति ही अभिमन्यु अभियान के द्वितीय चरण में भी प्रदेशभर के लोगों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। प्रदेश के सभी जिलों में 1 से 15 अगस्त तक चलाए गए इस अभियान में 10 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। अभिमन्यु अभियान के द्वितीय चरण के दौरान स्कूलों, कॉलेजों व सार्वजनिक स्थानों पर वाद-विवाद प्रतियोगिता, संगोष्ठी, नुक्कड़ नाटक, स्लोगन, प्रश्नावली हल करवाने, समूह चर्चा, लघु फिल्मों का प्रदर्शन एवं मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया।

सभी जिलों के प्रमुख स्थानों जैसे- रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पर्यटन स्थलों, तहसील कार्यालयों, कलेक्टर कार्यालय, शॉपिंग मॉल आदि स्थानों पर अभिमन्यु के शुभंकर के कट-आउट का सेल्फी प्वाइंट बनाया गया और विभिन्न प्रतिभागियों को अभिमन्यु बैज व अभिमन्यु स्टीकर प्रदान किए गए। पुलिस के प्रति बालक-बालिकाओं व आम जन की सोच के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जागरुकता कार्यक्रम के दौरान पुलिस मुख्यालय द्वारा तैयार प्रश्नावली स्कूल-कॉलेजों एवं सार्वजनिक स्थानों पर वितरित कर हल करवाई गई। विशेष तौर पर अधिक से अधिक पुरुष वर्ग को सम्मिलित किया गया और उन्हें अभिमन्यु के पोस्टर सहित मैं हूं अभिमन्यु लिखी टीशर्ट भी वितरित की गई।

मप्र पुलिस द्वारा इस अभियान के दौरान बालकों व पुरुषों को लैंगिक समानता एवं संस्कारों का ज्ञान देने के साथ ही उन्हें महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने की भी पहल की गई। इस अभियान के दौरान समय-समय पर बालकों के क्रियाकलापों का आंकलन किया गया। साथ ही उन्हें विभिन्न अपराधों की जानकारी देकर उनके दुष्परिणामों से भी अवगत करवाया गया। अभिमन्यु अभियान को स्कूल एवं शिक्षा विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग, ग्रामीण एवं पंचायत विभाग, परिवहन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग तथा विभिन्न एनजीओ के समन्वय से संचालित किया गया। विशेष जागरूकता अभियान अभिमन्यु के प्रथम चरण में 300 से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था और उसमें 1 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। अभियान के प्रथम चरण में भी अभिमन्यु के शुभंकर के कटआउट के साथ कई प्रतिभागियों ने सेल्फी ली थी। उस दौरान कटआउट के साथ महिला हेल्पलाइन नंबरों का प्रचार-प्रसार भी किया गया था।

50,000 विद्यार्थियों को प्रश्नावली वितरित

अभियान के दौरान प्रदेश के स्कूल-कॉलेजों के लगभग 50,000 विद्यार्थियों को प्रश्नावली वितरित की गई। इसके साथ ही जिले के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों, एनजीओ एवं स्थानीय कलाकारों के सहयोग से नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया गया। साथ ही लोगों को मनोरंजन के साथ ही समाज के गंभीर विषयों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर लघु फिल्में भी दिखाई गईं। अभियान के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन के साथ ही महिला अपराध को रोकने में अहम भूमिका निभाने वालों, पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कार्यक्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाली महिलाओं तथा महिला उत्थान के क्षेत्र में कार्य कर रहे पुरुषों का सम्मान किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी जिलों में ऐसे 1200 लोगों को जिला स्तर पर पुरस्कृत किया गया। अभियान के दौरान शुभंकर अभिमन्यु के कटआउट एवं फ्लेक्स लगाकर आमजन को लैंगिक भेदभाव दूर कर महिलाओं को उनकी योग्यता अनुरूप समान अवसर उपलब्ध करवाने संबंधी शपथ दिलाई गई।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में स्वतंत्रता दिवस पर अभिभावकों से बालकों और पुरुष वर्ग को जागरूक करने का आह्वान किया था, जिसके बाद मप्र पुलिस द्वारा अभिमन्यु अभियान की परिकल्पना की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आओ लड़कों को सिखाएं थीम पर कार्य करते हुए बालकों व पुरुषों को लैंगिक समानता एवं संस्कारों का ज्ञान देकर महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास करना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए मप्र को समय-समय पर प्रेरित करते रहते हैं। हाल ही में भोपाल के लाल परेड मैदान स्थित मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में हुए एक कार्यक्रम में उन्होंने बालकों एवं पुरुषों को महिला संबंधी अपराधों एवं लैंगिक समानता के प्रति जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे विशेष जागरूकता अभियान अभिमन्यु के लिए महिला सुरक्षा शाखा द्वारा तैयार की गई पोस्टर पुस्तिका का विमोचन किया था। इस पुस्तिका में प्रकाशित पोस्टरों के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों और रूढ़ियों को समाप्त करने के लिए आमजन को जागरूक करने का प्रयास किया गया।

● **डॉ. जय सिंह सेंधव**

साढ़े पांच करोड़ मतदाता चुनेंगे नई सरकार

पोलिंग बूथ की दूरी दो किमी से अधिक नहीं

आयोग ने मतदान के लिए जो व्यवस्था की है, उसके तहत एक परिवार के सभी सदस्यों का मतदान एक ही पोलिंग बूथ पर होगा। संवेदनशील केंद्रों पर पैरामिलिट्री बलों को तैनात किया जाएगा। जो पहले आएगा, उसका वोट पहले पड़ेगा। धन-बल और बाहुबल पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। 50 प्रतिशत से अधिक पोलिंग बूथों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। इसके साथ ही घर से पोलिंग बूथ की दूरी दो किमी से अधिक नहीं होगी। इसके लिए 362 नए पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों ने तीन स्तरों पर चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। पहले चरण में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत की, उनके मुद्दों को समझा। उसके बाद जिलों के कलेक्टरों और एसपी से तैयारियों पर चर्चा की गई। इसके बाद मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक स्तर पर बैठक की गई। निर्वाचन आयोग ने बताया कि राजनीतिक दलों ने मांग उठाई थी कि एक ही परिवार के सदस्यों का मतदान केंद्र एक ही होना चाहिए। इसे मान लिया गया है। इसी तरह 50 वोट डालकर मॉक पोल की मांग उठी है। फेक न्यूज पर रोक लगाने की मांग की थी, इसके लिए जिलाधिकारी की जवाबदेही तय की गई है। सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। चुनाव प्रभावित करने वाले अधिकारियों का तबादला करने की मांग उठी थी, उस पर विचार किया जाएगा।

मप्र में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार की अगुवाई में गत दिनों केंद्रीय निर्वाचन दल तीन दिवसीय दौरे पर भोपाल आया। केंद्रीय निर्वाचन दल ने 4 सितंबर से 6 सितंबर तक प्रदेश में रहकर राज्य में चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया और निर्वाचन दल ने प्रदेश में आगामी चुनाव के निर्वाचन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप शांतिपूर्ण चुनाव के लिए कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बुधवार को दौरे के अंतिम दिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने राजधानी भोपाल में प्रेस वार्ता को संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि मप्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में राज्य सरकार का कार्यकाल समाप्त होने के ठीक पहले चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रदेश के सभी मतदाताओं से आगामी चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीते दो दिनों में हमने विभिन्न राजनीतिक दलों, कानून व्यवस्था से जुड़ी एजेंसियों और जिलाधिकारियों, कमिश्नर, आईजी, एसपी आदि के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक की। प्रदेश में कुल 5.52 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें पुरुष व महिला मतदाता लगभग बराबर हैं, महिलाएं थोड़ी कम हैं। 2.67 करोड़ महिला मतदाता हैं। ट्रांसजेंडर वोटर्स की संख्या 1336 है। प्रदेश में 7.12 लाख मतदाताओं की उम्र 80 साल या इससे अधिक है। वहीं 6,180 मतदाता ऐसे हैं, जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर है। वरिष्ठ नागरिकों को मतदान में दिक्कत न हो इसके लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। वह घर से वोटिंग कर सकेंगे। 18.86 लाख वोटर 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के हैं और पहली बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में फिलहाल मतदाता सूची में संशोधन का काम चल रहा है। 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। मतदाता सूची से किसी भी मतदाता का नाम तभी विलोपित किया जाएगा, जब फॉर्म 7 मिलेगा। बीएलओ के मैदानी सत्यापन के बगैर कोई भी स्व: संज्ञेय विलोपन नहीं होगा। यहां तक कि किसी की मृत्यु होने की स्थिति में डेथ सर्टिफिकेट के बगैर मतदाता का नाम नहीं काटा जाएगा। जिस किसी को भी वोटर लिस्ट से शिकायत है या नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो उनके लिए अभी भी समय है। वे आएं और यदि उनकी कोई शिकायत है तो उसकी भी सुनवाई की जाएगी। वरिष्ठ नागरिक फॉर्म 12 को भरकर घर से वोटिंग कर सकेंगे। वरिष्ठ नागरिकों को नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पांच दिन के भीतर फॉर्म 12 डी भरकर जमा करना होगा। वोटिंग के लिए निर्वाचन टीम उनके घर जाकर वोटिंग कराएगी। इसकी रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी घर जा सकेंगे। बुजुर्गों और दिव्यांगों को यह सुविधा दी जाएगी। सक्षम एप के माध्यम से इस सुविधा को लिया जा सकता है।

इस बार कुल 5.52 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर नई सरकार चुनेंगे। इनमें 6,180 मतदाता ऐसे हैं, जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर है। प्रदेश में 7.12 लाख मतदाताओं की उम्र 80 साल या इससे अधिक है। वरिष्ठ नागरिकों की वोटिंग के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। 18-19 साल के वोटरों की संख्या 18.86 लाख है। यह लोग पहली बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 230 विधानसभाओं में एक-एक एईआरओ नियुक्त किए जाएंगे। इस बार कुल 64,523 मतदान केंद्र होंगे। 50 प्रतिशत से अधिक मतदान केंद्रों से वेब कास्टिंग होगी। 15 हजार आदर्श मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। 6,920 मतदान केंद्रों पर महिलाओं की वोटिंग पुरुषों के मुकाबले 10 प्रतिशत या इससे भी कम रही थी। इसे बढ़ाने के लिए खास प्रयास किए जाएंगे। हर बूथ पर औसत 843 वोटर होंगे।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि संवेदनशील मतदान केंद्रों पर ऐसी व्यवस्था होगी कि अप्रिय घटना की सूचना मिलने पर 100 मिनट के भीतर रिस्पॉन्स टीम पहुंच जाएगी। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों को तीन अखबारों में अपनी जानकारी देनी होगी। इसमें उन्हें बताना होगा कि उनके खिलाफ क्या-क्या अपराध दर्ज हैं। राजनीतिक दलों को भी बताना होगा कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी क्यों बनाया? इसके अलावा 5 बजे के बाद एटीएम के लिए भी नोटों का परिवहन नहीं हो सकेगा।

● **अरविंद नारद**

'जन आशीर्वाद' से उत्साह

मप्र ही नहीं देशभर में विकास का पोस्टर बॉय बने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी साल में जनता के बीच पहुंचने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा का जो फॉर्मूला बनाया था, वह हर बार सत्ता की चाबी साबित हुआ है। इस बार पार्टी ने 5 जन आशीर्वाद यात्राएं निकालकर सत्ता पर काबिज होने का जो प्लान बनाया है, उससे कांग्रेस के सपनों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। क्योंकि प्रदेश में निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्राओं को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है।

मप्र में अभी तक चुनावी साल में हर साल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा निकालते थे और जनता के बीच पहुंचकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे। इस बार भाजपा आलाकमान ने प्रदेश में एक नहीं पांच जन आशीर्वाद यात्राएं निकालने की रणनीति बनाई और शिवराज सिंह के नेतृत्व में उस पर अमल शुरू हो गया है। प्रदेश में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 3 सितंबर को चित्रकूट में कामतानाथ मंदिर में पूजा करने के बाद भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरूआत की। यह यात्रा 12 जिलों के 48 विधानसभा सीटों से गुजरेगी। यह यात्रा 19 दिन में 2343 किलोमीटर का सफर तय करेगी। वहीं 4 सितंबर को नीमच में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने दूसरी जन आशीर्वाद यात्रा को रवाना किया। 17 दिनों में 2,000 किलोमीटर तय करने वाली यह यात्रा 12 जिलों के 44 विधानसभाओं को कवर करेगी। 5 सितबंर को महाकौशल के मंडला से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने तीसरी जन आशीर्वाद यात्रा रवाना की। यह यात्रा 18 दिन में 2303 किलोमीटर की यात्रा करते हुए 10 जिलों की 45 विधानसभा सीटों से गुजरेगी। वहीं इसी दिन चौथी यात्रा ग्वालियर चंबल संभाग के श्योपुर कस्बे से शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के जरिए रवाना की। 17 दिन में 1997 किलोमीटर का सफर करने वाली यह यात्रा 11 जिलों के 42 विधानसभाओं से गुजरेगी। वहीं पांचवी और अंतिम यात्रा 6 सितंबर को खंडवा से धूनीवाले बाबा का आशीर्वाद लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रवाना की। यह यात्रा 21 दिन में 2,000 किलोमीटर के सफर में 10 जिलों के 42 विधानसभाओं से गुजरेगी।

मप्र में निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्राएं 24 सितंबर तक 10 हजार 543 किलोमीटर का सफर कर 210 विधानसभाओं को कवर करेंगी। यात्राओं के इस सफर के दौरान मप्र में 211 बड़ी सभाएं, 678 छोटी सभाएं होगी। 998 स्थानों पर यात्राओं का स्वागत और नुक्कड़ सभाएं होगी। 25 सितंबर को पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भोपाल में यात्राओं का समापन होगा जिसे प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। भाजपा के रणनीतिकारों का कहना है कि इस दिन तय हो जाएगा, कि मप्र में भाजपा की सरकार एक बार फिर बड़े बहुमत के साथ आएगी। हालांकि भाजपा की ये राजनीतिक यात्राएं कितनी फायदेमंद होती हैं यह तो आने वाला समय बताएगा। राजनीति में यात्राओं का बड़ा महत्व होता है। यही कारण है कि जब भी चुनावी समर शुरू होता है, राजनीतिक पार्टियां जनता तक पहुंचने के लिए यात्राओं का सहारा लेने लगती हैं। मप्र के इतिहास में मिशन 2023 ऐसा है, जिसको साधने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां यात्राओं का सहारा ले रही हैं। दरअसल, 2018 में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नर्मदा यात्रा निकालकर कांग्रेस के लिए जीत की पृष्ठभूमि तैयार की थी। उसको देखते हुए अब मप्र में भाजपा और कांग्रेस दोनों का फोकस यात्राओं पर है। वैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो बराबर यात्राएं निकालते रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस भी यात्राओं के सहारे वोटबैंक मजबूत करने में लगी हुई है। यात्राओं का फायदा किसको होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन दोनों पार्टियां दावा कर रही हैं कि प्रदेश के मतदाता उनको अधिक महत्व दे रहे हैं। यह महत्व वोट में कितना तब्दील हो पाता है, यह तीन महीने बाद होने वाले चुनाव में सबके सामने आ जाएगा।

सबको साधने की नीति

मिशन 2023 और 2024 की तैयारी में जुटी भाजपा किसी एक वर्ग को साधने की बजाय सबको साधने की नीति पर काम कर रही है। भाजपा न केवल मंदिर निर्माण और उनके पुनरुद्धार की रणनीति पर चल रही है, बल्कि पिछड़ों और अति पिछड़ों को रिझाने के लिए तमाम प्रयास भी कर रही है। भाजपा इस समय ओबीसी ही नहीं बल्कि अति पिछड़ा कार्ड खेल रही है। ओबीसी के नाम पर हिंदी प्रदेशों में यादव, गुर्जर, कुर्मी, बिश्नोई और जाट समुदाय ने ज्यादातर लाभ उठाया है जो पहले से ही साधन संपन्न ताकतवर जातियां हैं। इन शक्तिशाली पिछड़ी जातियों के कारण अति पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ। भाजपा इन्हीं अति पिछड़ी जातियों को गोलबंद कर रही है। उप्र में वह ऐसा कर चुकी है। पार्टी ने अति पिछड़ों के कारण ही उप्र में दो लोकसभा और दो विधानसभा चुनावों में सफलता प्राप्त की है। भाजपा इसी फॉर्मूले को छत्तीसगढ़, राजस्थान, मप्र और बिहार में आजमाने जा रही है। महाराष्ट्र में भी भाजपा अति पिछड़ी जातियों को गोलबंद करने की सोशल इंजीनियरिंग कर रही है। मप्र में ओबीसी सबसे बड़ा वोटबैंक है। भाजपा के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उसके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे ओबीसी नेता हैं। लेकिन मप्र में कांग्रेस का नेतृत्व कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। इसलिए ओबीसी वोटबैंक मप्र में कांग्रेस के पास जाएगा इसकी संभावना कम है। इसलिए भाजपा का पूरा फोकस अति पिछड़ी जातियों को साधने पर है।

प्रदेश में पांचों जन आशीर्वाद यात्राओं के शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय नेताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विकास पर मुहर लगाकर यह संकेत दे दिया है कि मप्र में विधानसभा चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। पांचवीं जन आशीर्वाद यात्रा को शुरू करने के अवसर पर खंडवा में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री शिवराज की तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने कहा, विकास का पावर स्टेशन अगर मप्र बना है तो इसका श्रेय शिवराज सिंह को जाता है। अभी तो विकास का ट्रेलर है, सही फिल्म शुरू होना बाकी है। उन्होंने कहा कि मप्र में शिवराज सिंह के आने से पहले रोड की हालत मुझे याद है। मैं नागपुर से छिंदवाड़ा जा रहा था। रोड पर गड्ढे थे। एक कार्यकर्ता बार-बार पलटकर देख रहा था कि उसकी पत्नी स्कूटर पर बैठी है या गिर गई। उन्होंने कहा कि शिवराज और मोदी के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 5 से 30 हो गई है। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी की बात को हाथ में लेकर शिवराज ने कृषि उत्पादन बढ़ाया और 7 बार प्रथम होने का अवॉर्ड लिया। मप्र में सिंचाई का क्षेत्र बढ़ने से उत्पादन बढ़ा है। आज मप्र बीमारू से विकासशील प्रदेश है। इसके लिए शिवराज सिंह चौहान को बधाई। गडकरी ने कहा, कपास सस्ता है, कपड़ा महंगा है, तिलहन सस्ती है, तेल महंगा है...। हमने सपना देखा था कि किसान केवल अन्नदाता नहीं, किसान ऊर्जादाता बनेगा। यह सपना पूरा हो रहा है। 6-7 दिन पहले टोयोटा गाड़ी किसानों के तैयार किए इथेनॉल से चली। टाटा के विस्तारा का हवाई जहाज किसानों के बॉयो फ्यूल पर आया। इस तरह किसान ऊर्जादाता बनेगा। शिवराज ने थर्मल पावर, विंड पावर, सोलर पावर प्लांट तैयार किए। आने वाले दिनों में हाइड्रोजन फ्यूल होगा। मेरे पास दिल्ली में एक गाड़ी है। मप्र ग्रीन फ्यूल उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य होगा। अब तो हमारे यहां पराली से बिटुमिन भी तैयार हो रहा है।

मप्र में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां एक्टिव मोड़ में आ गई हैं। भाजपा और कांग्रेस अपने-अपने स्तर पर रणनीति बना रही हैं। चुनावी माहौल से पहले मप्र की सियासत इन दिनों सुर्खियों में है। इसकी मुख्य वजह है यात्रा पॉलिटिक्स। मप्र में विधानसभा चुनाव से पहले हर एक व्यक्ति तक पहुंच बनाने के लिए भाजपा और कांग्रेस यात्राओं के सहारे हैं। भाजपा 24 सितंबर तक जनआशीर्वाद यात्रा निकालेगी। 10,000 किलोमीटर का सफर तय कर भाजपा एक बड़ी आबादी को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। 24 सितंबर को सभी रथ जब वापस लौट आएंगे। उसके दूसरे ही दिन 25 सितंबर को भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रदेश में अक्टूबर में आचार संहिता लग सकती है। आपको बता दें कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता 6 अक्टूबर को लग गई थी। इससे पहले साल 2013 के चुनाव में 8 अक्टूबर को आचार संहिता लागू की गई थी।

गौरतलब है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दो जन आशीर्वाद यात्राओं में शामिल हुए। अमित शाह खराब मौसम के चलते श्योपुर नहीं पहुंचे सके। उन्होंने फोन पर ही सभा को संबोधित किया। शाह ने कहा कि ग्वालियर में बारिश की वजह से हेलिकॉप्टर श्योपुर के लिए नहीं उड़ सका। लेकिन मैं इसी चुनाव अभियान में श्योपुर जरूर आऊंगा। शाह ने फोन पर अपने छोटे संबोधन में कहा कि मप्र में डबल इंजन की सरकार विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। 2003 से 2023 तक भाजपा ने मप्र को एक बीमारू राज्य से बेमिसाल राज्य बनाया है। इससे पूर्व मंडला में सभा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दावा किया कि मप्र में इस बार 150 सीटों के साथ भाजपा की सरकार बनने जा रही है। शाह ने मंडला में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके पहले उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा- आपके आशीर्वाद के साथ जन आशीर्वाद यात्रा शुरू कर रहे हैं। ऐसी 5 यात्रा प्रदेश की 210 विधानसभा क्षेत्र में घूमकर भोपाल जाएंगी। शाह ने कहा - मैं आज दावे से कहने आया हूं, बंटाधार जी आप और करप्शन नाथ दोनों सुन लो, जब 25 सितंबर को हमारी जन आशीर्वाद यात्रा समाप्त होगी, उसी दिन तय हो जाएगा कि मप्र में अगली बार 150 सीटों के साथ फिर से भाजपा की सरकार बनेगी।

● **कुमार राजेन्द्र**

'अच्छी तरह फिनिश कर जीतना जानते हैं शिवराज'

वहीं नीमच में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी जी और शिवराज जी को आपका आशीर्वाद चाहिए। आपके मामा शिवराज राजनीति के धोनी हैं। राजनीति का धोनी इसलिए कह रहा हूं। क्योंकि इन्हें 30 सालों से जानता हूं। शुरुआत जैसी भी हो, अच्छी तरह से ये फिनिश कर जीतना जानते हैं। शिवराज जी कला के

माध्यम से ही चुनावी कामयाबी हासिल नहीं करते। उन्होंने सेवक के रूप में जनता की सेवा की है। ऐसी मान्यता है कि मालवा खुशहाल होता है तो पूरा प्रदेश खुशहाल होता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के भीतर गरीबों के प्रति संवेदनशीलता जो मैंने देखी है, राजनीति में बिरले लोगों में ही यह देखने को मिलती है। मप्र आज विकासित राज्यों की कतार में खड़ा है। देश के रक्षामंत्री ने कहा कि 2047 यानी आजादी के 100 पूरे होते-होते हम भारत को अर्थव्यवस्था में विश्व में सबसे बड़ा देश बनाना चाहते हैं। यही हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि राज्यों में भी अनुकूल सरकारें होनी चाहिए। मोदी जी कुछ कहें और राज्यों की सरकार सुने ही नहीं। ऐसे में हम कैसे आगे बढ़ेंगे। मप्र में जो बदलाव आया है, वह किसी भी सूरत में रुकना नहीं चाहिए। बीच में कमलनाथ जी आए थे। उन्होंने गरीबों के सिर से छत छीनने का काम किया। हमारी पुरानी योजनाओं को बंद करने का काम किया। मोदी जी की योजनाओं पर बाधाएं डालीं। कोई सरकार शायद ही इतनी असंवेदनशील हो सकती है।

बेरोजगारों से 696 करोड़ कमाए

कर्मचारी चयन बोर्ड, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, व्यापमं ये सरकार की वो संस्था, माफ कीजिए संस्था नहीं कंपनी है, जिसका नाम भले ही बदला हो, लेकिन घाटा कभी नहीं हुआ। अलबत्ता मुनाफा हर साल डबल होता गया। कर्मचारी चयन बोर्ड पर प्रदेश के सरकारी विभागों की भर्ती परीक्षाएं कराने का जिम्मा है। पिछले कुछ सालों में हर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। कुछ परीक्षा रद्द कर दी गईं तो कुछ होल्ड कर दीं, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड का रेवेन्यू कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कर्मचारी चयन बोर्ड एक छात्र से औसतन 500 रुपए एप्लीकेशन फीस लेता है। परीक्षा कराने पर उसका खर्च 250 रुपए आता है। यानी 50 प्रतिशत मुनाफा। आइए जानते हैं क्या है मुनाफे का गणित।

मप्र में ऐसे लाखों युवा हैं जो सरकारी नौकरी के चक्कर में फीस देकर भर्ती फॉर्म भरते हैं, लेकिन उनके सपने किसी न किसी घपले की भेंट चढ़ जाते हैं। कुछ दिनों पहले सरकार ने हर परीक्षा के लिए एक ही फीस की घोषणा की है, लेकिन अभी तक युवाओं को इसका सीधा फायदा नहीं मिला है। प्रवेश परीक्षा हो या भर्ती परीक्षा, छात्रों से औसत 500 रुपए प्रति छात्र एप्लीकेशन फीस ली जा रही है और परीक्षा का पूरा सिस्टम ठेके पर है। एक स्टूडेंट की परीक्षा के लिए औसत 250 रुपए में ठेका दिया जा रहा है। नौकरी मिले या न मिले। पेपर लीक हो या सेंधमारी, सारी गलती की जिम्मेदारी परीक्षा कराने वाली कंपनी की है। कार्रवाई करनी भी हो तो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी पर छोटा मोटा-जुर्माना करके जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। गड़बड़ी ज्यादा बड़ी हो तो जांच कमेटी बनाकर उसकी सिफारिशों के आधार पर एफआईआर हो जाती है, लेकिन एफआईआर पर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कभी आगे नहीं बढ़ पाती। कम से कम पिछली परीक्षाओं में हुई सेंधमारी में तो यही दिखा है। किसान कल्याण, नर्स भर्ती, शिक्षक भर्ती-3 और पटवारी भर्ती परीक्षा में ऐसी ही गड़बड़ियां सामने आईं, लेकिन वही कंपनी परीक्षा करा रही है। ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें सरकार को नहीं मालूम हैं। 20 अप्रैल को सरकार ने इस संबंध में एक ऑर्डर जारी कर कहा कि अब एक साल के लिए एक ही बार एग्जाम फीस देनी होगी। हालांकि, इस चुनावी साल में अब तक इस आदेश का बहुत ज्यादा छात्रों को फायदा नहीं हुआ है।

कांग्रेस नेता पारस सकलेचा कहते हैं कि जनवरी 2023 से 15 जून 2023 के साढ़े पांच महीने में कर्मचारी चयन बोर्ड ने 6 परीक्षाओं का आयोजन किया। इसमें 32.60 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा फीस के 107 करोड़ रुपए दिए। 2008 से 2022 तक 15 सालों में व्यापमं की परीक्षाओं में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 2.21 करोड़ थी, लेकिन परीक्षा में 1.86 करोड़ छात्र ही शामिल हुए। 34 लाख आवेदकों ने परीक्षा ही नहीं दी। सकलेचा कहते हैं कि जिन छात्रों ने परीक्षा नहीं दी, उनका भुगतान भी कंपनी को किया जाता है। चयन बोर्ड का तर्क ये होता है कि चूंकि कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा होता है। अब सवाल ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किस आधार पर बनते हैं?

बात 2013 की है, जब व्यापमं महाघोटाले की परतें खुलनी शुरू हुईं। धीरे-धीरे पता चला कि यहां तो कमोवेश हर एग्जाम में धांधली हो रही है। कहीं परीक्षा सेंटर में नकल हो रही है, तो कभी पेपर चुनिंदा परीक्षार्थियों को एडवांस में मिल रहा है। कहीं व्यापमं में ओएमआर शीट के मूल्यांकन में गड़बड़ी हो रही है। व्यापमं की परीक्षाओं में घोटाला उजागर होने के बाद 2014 में एक प्रस्ताव बना कि पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन एग्जाम करवाए जाने चाहिए, इसमें लोगों का कम से कम हस्तक्षेप होगा।

व्यापमं के तत्कालीन अफसरों ने बैंकिंग परीक्षाएं कराने वाले आईबीपीएस का सिस्टम समझा। ऑनलाइन परीक्षाओं की तैयारी की, लेकिन साथ ही इस बात के लिए अलर्ट भी किया कि ऑनलाइन एग्जाम का ये मतलब नहीं कि व्यापमं अपनी जिम्मेदारी से बच जाए। हमें अलर्ट रहना होगा। रिजल्ट घोषित करने से पहले विभिन्न टूल से रिजल्ट का एनालिसिस करना होगा। जैसे, किसी एक ही सेंटर के स्टूडेंट्स के समान नंबर तो नहीं हैं। पास-पास बैठे स्टूडेंट्स के सही और गलत सवालों को मैच करना होगा। ये इसलिए, ताकि यह पता किया जा सके कि किसी स्तर पर गड़बड़ी तो नहीं हुई है। इसके बाद 2015 में ऑनलाइन एग्जाम शुरू हुईं। एग्जाम का जिम्मा टाटा कंसल्टेंसी कंपनी को दिया गया। ये भी तय हुआ कि हर बार परीक्षा प्रणाली में होने वाली चूक से सीख लेकर उसे दुरुस्त किया जाएगा। हर बार ज्यादा फुलप्रूफ सिस्टम बनाया जाएगा, लेकिन ऑनलाइन परीक्षा को व्यापमं के अफसरों ने अपनी ढाल बना लिया। ऑनलाइन परीक्षा में भी धांधली होती रही, लेकिन अफसरों की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई। आज तक किसी अफसर पर एग्जाम में धांधली को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

● धर्मेंद्र सिंह कथूरिया

फीस से परेशान हैं छात्र, हजारों रुपए भर चुके

अजय गौर बताते हैं कि मैं 2018 से कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हूं। इस दौरान 5 साल में करीब 12 से ज्यादा भर्तियों की परीक्षा दी है। हर बार हर परीक्षा के लिए 500 से 700 रुपए तक फीस दी है। कुल मिलाकर 7 से 8 हजार रुपए अभी तक भर चुका हूं, लेकिन समय से परीक्षाएं न होने, रिजल्ट नहीं आने, और धांधलियां होने से बहुत हताश हूं। सीहोर निवासी राजेश बताते हैं कि मप्र में सरकारी नौकरी के नाम पर हमें लूटा जा रहा है। मैंने कॉन्स्टेबल भर्ती के 3, एसआई के 2 और एमपीपीएससी के 2 एग्जाम दिए हैं। इनकी हजारों रुपए फीस तो भर ही चुका हूं। मुझे किसी भी एग्जाम का सेंटर जिला जो मैंने चुना था वो नहीं मिला। मैं सभी एग्जाम देने दूसरे जिलों में गया। बस, ट्रेन से आने-जाने के टिकट का खर्चा, स्टेशन से एग्जाम सेंटर भी बहुत दूर होते हैं तो ऑटो-टैक्सी का किराया, खाना-पीना और अगर सुबह की शिफ्ट का एग्जाम हो तो रहने का खर्चा, सब मिलाकर एक परीक्षा 2 से 3 हजार की पड़ती है। शुभम गौर कहते हैं, मै हरदा जिले से हूं और 2015 से भोपाल में भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूं। 8 सालों में मप्र कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो भी परीक्षाएं कराईं लगभग सभी एग्जाम दिए और हजारों रूपए फीस भरी। 70 परसेंट से ज्यादा भर्तियों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। मप्र विधानसभा में नौकरी के नाम पर 1000 रुपए का फॉर्म भरा था, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ।

123 साल में सबसे कम वर्षा

सूखे अगस्त में जलाशयों में रही 38 फीसदी की कमी

मानसून के तीसरे यानी अगस्त महीने में 123 वर्षों की अब तक की सबसे कम वर्षा दर्ज की गई है। इसका असर भारत के जलाशयों में भी देखने को मिल रहा है। पूरे महीने में भारत के कुल 150 जलाशयों में जल भंडार का स्तर लाइव स्टोरेज कैपिसिटी से करीब 38 फीसदी कम ही बना रहा है। केंद्रीय जल आयोग की ओर से 31 अगस्त, 2023 को जारी बुलेटिन के मुताबिक जलाशयों में लाइव स्टोरेज 113.417 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) है जो कि कुल लाइव स्टोरेज कैपेसिटी का 63 फीसदी है। जलाशयों के स्टोरेज की यह स्थिति न सिर्फ 2022 की समान अवधि से 23 फीसदी कम है बल्कि बीते दस वर्षों की समान अवधि में भी 9 फीसदी कम है। तीन हफ्ते पहले 10 अगस्त, 2023 को जलाशयों में लाइव स्टोरेज 109.98 बीसीएम था जो कि कुल लाइव स्टोरेज कैपिसिटी का 62 फीसदी था। इसके एक हफ्ते बाद 17 अगस्त, 2023 को जलाशयों के लाइव स्टोरेज में सुधार नहीं हुआ और बुलेटिन के मुताबिक लाइव स्टोरेज 111.285 बीसीएम था जो कि कुल लाइव स्टोरेज कैपेसिटी का 62 फीसदी ही था।

देश में अगस्त, 2023 न सिर्फ 123 सालों का सबसे सूखा महीना रहा बल्कि सबसे गर्म भी रिकॉर्ड किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की ओर से महानिदेशक एम महापात्रा ने 31 अगस्त, 2023 को एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि अगस्त महीने में ऑल इंडिया रेनफॉल 161.7 मिलीमीटर (एमएम) दर्ज किया गया जो कि सामान्य से 35 फीसदी कम है और 1901 के बाद से सबसे कम है। वहीं आईएमडी के रिकॉर्ड से पता चलता है कि देश में अगस्त में अब तक का सबसे अधिक औसत तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया (1901 के बाद से जब मौसम मापदंडों का वैज्ञानिक रिकॉर्ड रखना शुरू हुआ) जो सामान्य औसत तापमान से 0.84 डिग्री सेल्सियस अधिक था। अगस्त महीने में 1901 के बाद से उच्चतम औसत दिन (अधिकतम) तापमान और दूसरा सबसे अधिक रात (न्यूनतम) तापमान भी दर्ज किया गया।

देश में सर्वाधिक कम वर्षा वाले क्षेत्र केंद्रीय और दक्षिणी प्रायद्वीप रहे। केंद्रीय (164.5 एमएम) और दक्षिणी प्रायद्वीपीय (73.5 एमएम) भारत में भी 1901 के बाद से सबसे कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। महापात्रा ने कहा, इसका प्रमुख कारण अल नीनो और अन्य मौसम कारक हैं। उन्होंने कहा कि अल नीनो मजबूत हो रहा है और 2026 तक इसकी परिस्थितियां बनी रह सकती हैं। हालांकि, वर्षा को बढ़ाने वाला इंडियन ओसियन डायपोल (आईओडी) पूरे साल पॉजिटिव बना रह सकता है जो अल नीनो के असर को कम कर सकता है। इससे पहले अगस्त महीने में बेहद कम वर्षा (सामान्य से 25 फीसदी कम) का रिकॉर्ड 2005 में दर्ज हुआ था। आईएमडी ने सितंबर महीने में सामान्य वर्षा होने की उम्मीद जताई है। हालांकि पूरे मानसून सीजन (जून-सितंबर) में कुल औसत वर्षा सामान्य से कम रह सकती है।

आईएमडी ने मानसून सीजन शुरू होने से पहले यह फोरकॉस्ट किया था कि पूरे सीजन में 96 फीसदी यानी सामान्य से 4 फीसदी ज्यादा और सामान्य से 4 फीसदी कम वर्षा हो सकती है। महापात्रा ने कहा कि मानसून सीजन की वर्षा के सामान्य से कम रहने की आशंका है, हालांकि वह सीजन के सामान्य वर्षा के पुराने फोरकास्ट को चेंज नहीं करेंगे। आईएमडी ने लॉन्ग पीरियड एवरेज (एलपीए-1971-2020) के आधार पर सितंबर महीने में सामान्य वर्षा होने का फोरकॉस्ट किया है। आईएमडी के मुताबिक सितंबर महीने में सामान्य वर्षा 167.9 एमएम वर्षा 91 से 109 फीसदी के बीच संभव है। हालांकि, यदि सामान्य वर्षा सितंबर में दर्ज भी होती है तो भी पूरे मानसून सीजन की वर्षा सामान्य से कम हो सकती है।

आईएमडी के मुताबिक मानसून के शुरुआती तीन महीनों में जुलाई को छोड़कर जून और अगस्त महीने में सामान्य से बहुत कम वर्षा रिकॉर्ड की गई। जुलाई में सामान्य से 13 फीसदी अधिक 315.9 एमएम वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं, सामान्य से कम वर्षा वाले महीनों में जून महीने की बात की जाए तो सामान्य 165.3 एमएम की तुलना में 151.2 एमएम वर्षा यानी सामान्य से -9 फीसदी कम रही। अगस्त महीने में सामान्य से -36 फीसदी वर्षा (162.7 एमएम) कम रही। एम महापात्रा वर्षा में कमी के कारकों में अल नीनो के अलावा अन्य कारकों के बारे में बताते हैं कि न ही ज्यादा लो प्रेशर सिस्टम बने और न ही वर्षा बढ़ाने वाला मैडन जूलियन ऑसिलेशन (एमजेओ) फेवरेबल रहा। इसके अलावा अगस्त के महीने में इंडियन ओसियन डायसपोल (आईओडी) भी निगेटिव रहा। आईओडी के कारण वर्षा होती है। यह अगस्त के अंत में जाकर अपने थ्रेशहोल्ड को पार कर गया है यानी पॉजिटिव है जिसका परिणाम सितंबर में वर्षा के रूप में मिल सकता है। आईएमडी के मुताबिक इस बार अगस्त महीने में 24 तारीख तक सामान्य 16 निम्न दाब वाले दिनों में सिर्फ 9 दिन निम्न दाब वाले बने और सामान्य 5 लो प्रेशर सिस्टम की तुलना में सिर्फ दो लो प्रेशर सिस्टम बने। अगस्त महीने में करीब 20 दिन तक ब्रेक डे रहा। इससे पहले 1979 और 2005 में सर्वाधिक मानसून ब्रेक डे रिकॉर्ड किए गए थे।

31 अगस्त, 2023 तक पूर्वी उप्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, गंगेटिक वेस्ट बंगाल, एनएमएमटी, केरल, लक्षद्वीप साउथ इंटीरियर कर्नाटक, रायलसीमा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में डिफिशिएंट रेनफॉल दर्ज किया गया। पूर्वी उप्र, बिहार-झारखंड में कम वर्षा और राजस्थान में अत्यधिक वर्षा पर महापात्रा ने कहा कि यह ट्रेंड देखा जा रहा है कि पूर्वी उप्र बिहार और झारखंड में कम वर्षा हो रही है जबकि राजस्थान में अत्यधिक वर्षा रिकॉर्ड की जा रही है। इस बार राजस्थान में अधिक वर्षा का कारण बिपरजॉय तूफान था। जुलाई में सामान्य से अधिक वर्षा ने खेती-किसानी को चौपट होने से बचा लिया है। आईएमडी का मानना है कि यदि जुलाई में वर्षा में कमी होती तो बुआई संभव न हो पाती।

● **लोकेंद्र शर्मा**

आशियाना पाने चक्कर काट रहे लोग

एक तरफ सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में हर व्यक्ति के सिर पर पक्की छत हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगभग हर सभा में इसकी घोषणा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ स्थिति यह है कि सरकारी योजनाओं के तहत बनने वाले मकानों की रफ्तार इतनी धीमी है कि हजारों लोग आशियाना पाने के लिए चक्कर काट रहे हैं। आलम यह है कि सात साल में जहां 50128 आवास बनाने थे, लेकिन अभी तक सिर्फ 23156 ही बन पाए हैं। स्थिति यह है कि हर शहर में प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा है।

प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के निर्माण की गति धीमी होने से लोग परेशान हैं। लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में आवास बुक कराए, लेकिन नगरीय निकायों के अफसरों की लापरवाही के कारण लोग आवास से वंचित हैं। अपने घर को पाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन अभी तक उन्हें अपना आशियाना नहीं मिला। प्रदेश के 40 शहरों में 26 हजार 972 आवास अभी तक बन ही नहीं पाए। चारों बड़े शहरों ग्वालियर, सागर, जबलपुर और इंदौर पर नजर डालें तो यहां 16 हजार 252 लोग आवास विहीन हैं। यानी इन्हें आवास मिल ही नहीं पाया। बता दें कि योजना के तहत 40 शहरों में 50128 आवास बनने थे। मार्च-2022 तक काम पूरा होना था, लेकिन हालात ऐसे हैं कि अब तक सिर्फ 23156 आवास ही बन पाए। इसमें भी 15459 लोगों को ही पजेशन मिल पाया है। 2015 से शुरू हुई योजना पर गौर करें तो कोई भी ऐसा शहर नहीं है, जहां प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो गए हों।

छोटे शहरों की बात तो छोड़िए, बड़े शहरों में भी स्थिति चिंताजनक है। राजधानी में ही नगर निगम के 31 प्रोजेक्ट में से सिर्फ राहुल नगर, सनखेड़ी और कोकता के प्रोजेक्ट पूरे हुए और लोगों को आवास मिल पाया। अन्य प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं। लोगों को आवास पाने के लिए बार-बार निगम अफसरों के सामने प्रदर्शन करना पड़ रहा है। भोपाल में 7755 में से सिर्फ 3556 आवास ही बन पाए हैं। यहां सिर्फ 1559 आवासों का ही पजेशन मिल पाया। इंदौर की भी यही स्थिति है, यहां 12448 आवास में से सिर्फ 7008 आवास ही बन पाए हैं। यहां 7 प्रोजेक्ट में से राउ स्थित पलाश परिसर और नर्मदा परिसर में ही लोगों को अपने आशियाने मिल सके। उधर, ग्वालियर में 2112 आवास बने लेकिन अब तक किसी को पजेशन नहीं मिला। वहीं, उज्जैन में 440 में 136 आवास ही बन पाए हैं। चार शहरों में 6 ठेका कंपनियों को हटाना पड़ा। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के गृह जिले में भी योजना के हाल अच्छे नहीं है। 1764 आवासों का निर्माण होना था। अब तक यहां 408 मकानों में ही पजेशन मिल पाया है। वहीं, सारणी में 456 में 237 और बालाघाट में 468 में से 308 आवास ही मिल पाए। विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि कई प्रोजेक्ट में हितग्राहियों ने पूरा पैसा ही जमा नहीं कराया। कई प्रोजेक्ट की लोकेशन ऐसी थी कि लोगों ने वहां फ्लैट बुक कराने में दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। इस कारण भी प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं हो पाए।

प्रदेश में सात साल में जहां 50128 आवास बनाने थे, लेकिन अभी तक सिर्फ 23156 आवास ही बन पाए हैं। यानी प्रदेश में 26972 आवास अब भी तैयार नहीं हो पाए हैं। प्रोजेक्ट पिछड़े तो इसकी समय सीमा बढ़ाकर दिसंबर-24 कर दी गई। कई निकायों के सामने इस समय सीमा में भी इन प्रोजेक्ट को पूरा करना बड़ी चुनौती है। भोपाल के 3, विदिशा का 1, इटारसी का 1 और टीकमगढ़ का 1 प्रोजेक्ट कई सालों से अधूरा था, ठेकेदार इन्हें समय पर बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे तो निगमों को इन ठेकेदारों को हटाना पड़ा। निगम अब यहां नई ठेका कंपनी से काम कराने की जुगत कर रहा है। इससे निर्माण लागत भी बढ़ गई है। प्रोजेक्ट निगम ने शहर के इतने आउटर क्षेत्र में बना दिए कि वहां गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को रोजगार के लिए आना-जाना ही मुश्किल बना देगा। भोपाल में 7755 में से 4425 हितग्राही ही आए तो जबलपुर में 5184 में से 482 आवास ही बुक हो पाए। नगरीय आवास एवं विकास आयुक्त भरत यादव का कहना है कि योजना की लगातार मॉनीटरिंग की जा रही है। जहां ठेकेदार काम में लापरवाही बरत रहे थे। उन्हें हटा दिया गया। हमारी कोशिश है कि सभी हितग्राहियों को जल्द से जल्द आवास मिल जाएं।

● **सुनील सिंह**

गरीबों के लिए मुख्यमंत्री जन आवास योजना

प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आवासहीनों के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना लागू की है। इसमें भूखंड देने के अलावा हाइराइज बिल्डिंग बनाकर आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए वे गरीब व्यक्ति पात्र होंगे, जिनके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं जुड़ पाए हैं। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना लागू करने के बाद अब सरकार मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना लागू करेगी। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह गए लोगों को आवास बनाने के लिए सरकार द्वारा राशि दी जाएगी। गत दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रदेश में 22.92 लाख आवासहीन प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल होने से वंचित रह गए थे। आवास प्लस में इनके नाम जोड़कर प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया लेकिन अनुमति नहीं मिली। इनमें से विभिन्न कारणों से 3.78 लाख अपात्र हो गए। मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना केवल एससी-एसटी वर्ग के लिए थी। ऐसे में बाकी वर्ग के लोगों को लाभ नहीं दिया जा सकता था। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री जन आवास योजना प्रस्तावित की गई थी लेकिन कैबिनेट ने इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना रखने का निर्णय लिया।

स्कूलों की 'सेहत' खराब

हम इस समय नई शिक्षा नीति और प्रणाली की चिंता और चिंतन के दौर से गुजर रहे हैं। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव का दौर शुरू हुआ और 1986 में बनी नीतियों में व्यापक परिवर्तन कर स्कूली शिक्षा को विद्यार्थियों के लिहाज से अधिक बेहतर बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़े हैं। लेकिन यह सवाल अब भी अनसुलझा ही है कि शिक्षा नीति को उसके अंतिम छोर यानि स्कूलों तक पूरी तरह लागू कैसे किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में सरकारी स्कूल सबसे अहम कड़ी है। लेकिन प्रदेश में सरकारी स्कूल अब भी व्यवस्थागत विसंगतियों से जूझते नजर आते हैं।

निजी स्कूलों की सुविधाओं और संसाधनों से किसी तरह मुकाबला करते प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर लोग अब भी विश्वास जताकर अपने बच्चों को भविष्य निर्माण के लिए सौंप देते हैं। इसका प्रमाण है इस वर्ष निजी स्कूलों के मुकाबले सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों का अधिक प्रवेश। परेशानी तब खड़ी होती है जब शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था से लड़ते-लड़ते थककर चूर हो जाते हैं और यहां कुछ नहीं हो सकता की सोच के साथ किनारे हो जाते हैं।

प्रदेश के ज्यादातर सरकारी स्कूलों के हाल क्या हैं यह परिसर में कदम रखते ही पता चल जाता है। दूरस्थ इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल आज भी बिजली, पेयजल और बच्चों के लिए बेहतर आवागमन व्यवस्था से रोज जूझते हैं। लेकिन व्यवस्था पर सवाल तब खड़े होते हैं जब प्रदेश के महानगर कहे जाने वाले बड़े शहरों के स्कूल कस्बों के स्कूलों से भी पीछे नजर आते हैं। स्कूली शिक्षा विभाग ने जब प्रदेशभर के स्कूलों को लेकर जिला स्तरीय रिपोर्ट तैयार की तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों के स्कूल बी ग्रेड ही प्राप्त कर सके। यह स्थिति तब है जब इन शहरों के स्कूल सुविधाओं के मामले में छोटे शहरों के स्कूलों से कहीं अधिक साधन-संपन्न हैं।

सीखने के परिणाम-गुणवत्ता, शिक्षकों की उपलब्धता, समानता, अधोसंरचना व सुविधाएं, वित्तीय प्रबंधन और साक्षरता कार्यक्रम जैसे बिंदुओं पर भोपाल-इंदौर जैसे शहर छिंदवाड़ा, बालाघाट और सिवनी जैसे जिलों के सामने टिक नहीं पाए। संख्या से अधिक शिक्षक, अच्छे भवन और तमाम अन्य सुविधाओं के बावजूद बीते वर्ष की तुलना में इनकी स्थिति खराब है। जबकि छिंदवाड़ा ने पहला, बालाघाट ने दूसरा और सिवनी ने तीसरा स्थान हासिल कर लिया। बड़े जिलों के सरकारी स्कूलों के लिए यह आंकड़े और स्थान आईना दिखाने के समान हैं। निगरानी का तंत्र मुख्यालय पर ही होने, साधन-सुविधाएं होने के बाद भी प्रदेश की सूची में एक से दसवें स्थान पर कोई बड़ा जिला स्थान नहीं पा सका।

दरअसल इस अव्यवस्था के लिए शिक्षा क्षेत्र की व्यवस्था सर्वाधिक जिम्मेदार है। सवाल यह भी है कि जब सीएम राइज, उत्कृष्ट और मॉडल स्कूलों की व्यवस्था पर तंत्र इतना ध्यान दे रहा है तो आमजन के लिए स्कूलों की व्यवस्था को बेहतर क्यों नहीं किया जा सकता। इससे उलट छोटे-छोटे गांवों के वे सरकारी स्कूल भी हैं जिन्होंने जनभागीदारी से न सिर्फ बच्चों के लिए अच्छे संसाधन और सुविधाएं जुटाई बल्कि शिक्षकों की मदद कर विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ वातावरण तैयार किया। आज ऐसे स्कूलों के विद्यार्थी जिले और प्रदेश स्तर पर अपनी प्रतिभा से सबको कायल कर रहे हैं।

अब सिक्के के दूसरे पहलू पर भी विचार कीजिए। तमाम कमियों और अव्यवस्थाओं के बावजूद प्रदेश के लोग सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पर निर्भर भी हैं और उसके प्रति विश्वास भी जता रहे हैं। बढ़ती व्यावसायिकता की वजह से निजी स्कूलों की फीस सामान्य वर्ग की पहुंच से दूर होती जा रही है। निजी स्कूलों पर नियंत्रण की व्यवस्था कागजों से बाहर नहीं निकल पाती है, वहीं फीस नियमन के लिए बने नियम जिम्मेदारों को याद नहीं रहते। भारी-भरकम खर्च के बाद भी अपेक्षानुरूप परिणाम नहीं मिलने पर पालक सरकारी स्कूलों का रुख इस विश्वास के साथ करते हैं कि यहां अच्छे शिक्षक और सामान्य गुणवत्ता के साथ उनके नौनिहालों को अच्छी शिक्षा तो मिल ही जाएगी। इस वर्ष भी प्रदेश में निजी स्कूलों के मुकाबले सरकारी स्कूलों में प्रवेश अधिक होना व्यवस्था को यह बताने के लिए काफी है कि लोग अब भी सरकारी व्यवस्था पर भरोसा कर रहे हैं बस जरूरत है उस भरोसे को कायम रखते हुए उन्हें अच्छे परिणाम और सुविधाएं उपलब्ध करवाने की। नौंवी से बाहरवीं की कक्षाओं में इस बार प्रदेश के निजी स्कूलों में साढ़े दस लाख विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया जबकि सरकारी स्कूलों में 22 लाख विद्यार्थियों ने प्रवेश प्राप्त किया है। इस तस्वीर का एक सुखद पहलू यह भी है कि 51 उत्कृष्ट और 250 से ज्यादा मॉडल स्कूलों में प्रवेश परीक्षा में आने वाले 60 प्रतिशत विद्यार्थी निजी स्कूलों में अध्ययन करने वाले होते हैं।

● **राकेश ग्रोवर**

आधुनिकीकरण की रफ्तार बेहद धीमी

सरकार की मंशा और योजना सरकारी स्कूलों के उन्नयन और उन्हें सुविधा संपन्न बनाने की है लेकिन इसकी धीमी गति इस बड़े लक्ष्य तक कब पहुंचाएगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। फिलहाल प्रदेश के 9 हजार 200 सरकारी स्कूलों को सीएम राइज योजना के तहत साधन संसाधनों से लैस करना है लेकिन पहले चरण में सिर्फ 379 स्कूलों का उन्नयन ही हो पाया है। तकनीक के इस दौर में स्कूलों की निगरानी और शिक्षकों की जवाबदेही तय करना उतना कठिन भी नहीं है। बस जरूरत ऐसे तंत्र और इच्छाशक्ति की है जो स्कूलों की व्यवस्था को शिक्षित कर सके ताकि महर्षि सांदीपनि की उस भूमि जहां योगेश्वर कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की थी, वहां के स्कूलों को सही मायनों में शिक्षा के मंदिर बना सकें और इन शिक्षा मंदिरों से निकली प्रतिभाएं प्रदेश और देश के क्षितिज पर सूर्य की तरह चमक सकें।

अधर में चंबल अभयारण्य

चंबल अभयारण्य के डिनोटिफाई क्षेत्र को लेकर स्थिति अब तक साफ नहीं हुई है। मामला केंद्र सरकार में विचाराधीन है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं के लिए 31 जनवरी 2023 को डिनोटिफाई किए गए 207.049 हेक्टेयर क्षेत्र के मामले में केंद्र सरकार ने सवाल उठाया है कि डिनोटिफाई क्षेत्र के बदले समतुल्य भूमि क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि वन भूमि डिनोटिफाई करने पर समतुल्य भूमि देनी होगी। इसके बाद अब मप्र का वन विभाग नए सिरे से इसकी कवायद में जुट गया है। इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में रेत का भंडार है और डिनोटिफाई होने से स्थानीय लोगों को रेत की उपलब्धता आसान होगी।

उधर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने राजस्थान, मप्र और उप्र के अधिकारियों को राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य (एनसीएस) में अवैध खनन को नियंत्रित करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने अधिकारियों से रेत खनन संबंधी दिशा-निर्देशों को भी लागू करने को कहा है। कोर्ट ने इसकी निगरानी के साथ अगले तीन महीनों में किए गए कामों पर रिपोर्ट भी मांगी है। यह निर्देश न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह और न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी की पीठ ने दिया है। इस मामले में कोर्ट ने राजस्थान, मप्र और उप्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, एसपीसीबी के साथ भिंड, मुरैना, ग्वालियर, आगरा, इटावा, झांसी, धौलपुर और भरतपुर के पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट से अवैध खनन को नियंत्रित करने, उस पर निगरानी रखने और तीन महीनों के भीतर इस मामले में क्या कार्रवाई की गई, उस पर रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है। अदालत के मुताबिक राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य (एनसीएस) को अवैध रेत खनन से बचाने के लिए यह कदम आवश्यक हैं। कोर्ट का यह भी कहना है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) के सचिव को 31 जनवरी, 2023 को जारी अधिसूचना की स्वीकृति को स्पष्ट करने के लिए मप्र के मुख्य सचिव के साथ स्थिति की निगरानी करने को कहा है, जिसके तहत अभयारण्य में 207 हेक्टेयर भूमि को गैर-अधिसूचित किया गया था। कोर्ट ने वन्यजीवों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी खनन या अन्य हानिकारक गतिविधियों को रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठकें करने की बात भी कही है।

ट्रिब्यूनल ने पाया कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के भीतर रेत खनन तेजी से बढ़ा है। कई स्थान, जो पहले इससे अछूते थे, वहां भी अब रेत के लिए लगातार खनन किया जा रहा है। इसकी वजह से कई दुर्लभ जीवों के महत्वपूर्ण आवास नष्ट हो गए हैं। अवैध खनन क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को प्रभावित कर रहा है और इन लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। एनजीटी ने 25 जुलाई 2023 को दिए आदेश में कहा है कि रिठौरा रेत तट को पूरी तरह से समतल कर दिया गया है। 2019 तक, रिठौरा रेत तट पर कम से कम घड़ियालों के 35 घोंसले हुआ करते थे। हालांकि, अवैध खनन के चलते घोंसला बनाने की जगह अब नष्ट हो चुकी है। गौरतलब है कि एनजीटी की यह कार्रवाई धौलपुर के पास केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में बने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य (एनसीएस) के करीब हो रहे अवैध खनन के खिलाफ थी, जो जीवों की दुर्लभ प्रजातियों विशेष रूप से घड़ियाल, रूफ्ड कछुओं और नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिनों का आवास है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें यह जानकारी देनी है कि एक इंडस्ट्री मैसर्स ओबेटी प्राइवेट लिमिटेड को गंगा नदी में मिलने वाले झिरिया नाले में अपशिष्टों को छोड़ने की अनुमति क्यों दी गई है। साथ ही अदालत ने उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) से नाले में अपशिष्ट छोड़ने वाली अन्य मृत इकाइयों के बारे में भी अपडेट देने को कहा है। कोर्ट ने सीवेज प्रबंधन पर विवरण और गोपीगंज नगर पालिका परिषद (एनपीपी) से इसके बारे में समय सीमा का विवरण मांगा है।

पता चला है कि गोपीगंज नगर पालिका परिषद (एनपीपी), झिरिया नाला में औद्योगिक और घरेलू सीवेज छोड़ रही है जो आखिर में गंगा में मिल रहा है। एनजीटी ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) से झरिया नाला में बहने वाले सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों के संबंध में स्थिति की समीक्षा करने और नाले को रोकने का निर्देश दिया है ताकि अपशिष्टों को गंगा में न छोड़ा जाए। 24 जुलाई 2023 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) और संबंधित अधिकारियों से बारिश के पानी को पाइपलाइनों की मदद से सड़कों पर बहाने के बजाय उपयोग करने के लिए उचित तरीका विकसित करने का आदेश दिया है, जो समस्याओं का कारण बन रहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली नगर निगम और डीएमआरसी की एक संयुक्त समिति बनाने का भी निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने बारिश के पानी के दोबारा उपयोग के लिए एक मेथड या मॉडल बनाने के लिए तकनीकी अधिकारियों की मदद लेने और उस पर एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य बारिश के पानी का उपयोग पौधारोपण और भूजल पुनर्भरण के लिए करना है। कोर्ट के अनुसार इस योजना को डीएमआरसी के सभी खंभों पर लागू किया जाना चाहिए।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

रेत खनन का भी रास्ता साफ नहीं

स्थानीय निवासियों को रेत आपूर्ति की व्यवस्थाओं के लिए राज्य सरकार ने सात माह पहले मुरैना वनमंडल में स्थित राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य का कुछ हिस्सा डिनोटिफाई होने के बाद मुरैना डीएफओ की आपत्ति है कि अभयारण्य की सीमा से एक किमी बाहर का क्षेत्र इको सेंसेटिव जोन है तथा इसमें रेत का खनन नहीं हो सकता है। इस पर तय हुआ कि इको सेंसेटिव जोन को खत्म किया जाए। राज्य के पर्यावरण विभाग के माध्यम से इसका प्रस्ताव केंद्र की स्वीकृति के लिए भेजा गया, लेकिन केंद्र ने कहा है कि पहले इको सेंसेटिव जोन की सीमा तो तय करें। अभयारण्य से रेत खनन के लिए जो तीन अलग-अलग हिस्से डिनोटिफाई किए गए हैं, वे अभयारण्य की सीमा पर न होकर अंदर स्थित हैं। वन कानूनों के अनुसार, वन क्षेत्र में मार्ग बनाकर रेत का परिवहन नहीं किया जा सकता है।

बाघ, घड़ियाल बचाने 3186 करोड़ होंगे खर्च

केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के साथ-साथ मप्र और उप्र के 11 जिलों में ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान लागू किया जाएगा। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा तैयार किए गए इस प्लान को मप्र के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की अध्यक्षता वाली ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल ने मंजूरी दे दी है। इस प्लान पर केंद्र, मप्र और उप्र सरकार मिलकर वर्ष 2032 तक 3186 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय तथा मप्र और उप्र वन विभाग संयुक्त रूप से इसकी फंडिंग और क्रियान्वयन करेंगे। केंद्र, मप्र और उप्र सरकार के 18 प्रतिनिधि पदेन इस काउंसिल के मेंबर हैं।

इस प्लान में 10 साल के भीतर बाघ, गिद्ध और घड़ियाल के संरक्षण के लिए 47000 वर्ग किलोमीटर जमीन में हैबिटेट डेवलपमेंट और कॉरिडोर प्रोटेक्शन से जुड़े काम किए जाएंगे। इस क्षेत्र में पन्ना, रानीपुर और प्रस्तावित नौरादेही-दुर्गावती टाइगर रिजर्व में करीब 150-200 बाघ और घड़ियालों की संख्या करीब 90 है। गिद्ध की चार प्रजातियां हैं। ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान को लागू कराने और इसके कामों की निगरानी के लिए पन्ना जिले में इंटीग्रेटेड रिसर्च एंड लर्निंग सेंटर (आईआरएलसी) स्थापित किया जाएगा। ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप में सागर, दमोह, छतरपुर, नरसिंहपुर, पन्ना, कटनी, सतना, रीवा, बांदा, चित्रकूट जिले शामिल किए गए हैं। एसीएस वन जेएन कंसोटिया का कहना है कि ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप प्लान को केंद्र, मप्र और उप्र की संयुक्त काउंसिल ने स्वीकार करते हुए मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार द्वारा गठित इस काउंसिल के अध्यक्ष मप्र के मुख्य सचिव हैं। यह प्लान केन-बेतवा प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा है, जिसके तहत 10 साल में 3186 करोड़ की लागत से संकटग्रस्त वन्यजीव बाघ, गिद्ध और घड़ियालों के संरक्षण से जुड़े काम होंगे। गौरतलब है कि जनवरी में केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के कार्यान्वयन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मप्र और उप्र की सरकार ने तीन वन्यजीव अभयारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम के दायरे में लाने को मंजूरी प्रदान की गई है। इससे पन्ना बाघ अभयारण्य की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम के दायरे में लाने को लेकर जिन तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, उनमें मप्र स्थित नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य और रानी दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य तथा उप्र स्थित रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं। गौरतलब है कि केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के कारण पन्ना बाघ अभयारण्य में वन्य जीवों पर पड़ने वाले प्रभावों से निपटने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई थी। भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) द्वारा विस्तृत अध्ययन के बाद तैयार ताजा रिपोर्ट में इस कार्ययोजना को लागू करने के लिए विशेष उद्देश्यीय कंपनी गठित करने का सुझाव दिया गया था। इस विशेष उद्देश्यीय कंपनी को ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल (जीपीएलसी) का नाम दिया गया था।

रिपोर्ट में मप्र में नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य और दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य तथा उप्र में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य के साथ संपर्क गलियारा स्थापित करने का सुझाव दिया गया था। इस कदम से इस क्षेत्र में मानव-पशु संघर्ष को कम करने तथा बाघ पर्यावास की क्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद की गई थी। वहीं, जल शक्ति मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, संचालन समिति की गत दिनों हुई बैठक में मुआवजे के तौर पर जमीन स्थानांतरित करने को लेकर जानकारी दी गई। इसके अनुसार मुआवजे के रूप में पौधारोपण के लिए पन्ना और छतरपुर जिले में 5480 हेक्टेयर गैर वन सरकारी भूमि को पन्ना बाघ अभयारण को हस्तांतरित करने का आदेश जारी किया गया है। परियोजना के पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं इससे जुड़े कार्यों के अनुपालन के लिए ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल (जीपीएलसी) का भी गठन किया गया है।

केन-बेतवा लिंक परियोजना की अंतिम रिपोर्ट में पूरे इलाके में नदियों को जोड़ने के रोडमैप के साथ पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण के लिहाज से विस्तृत कार्ययोजना को तैयार किया गया है। इस कार्ययोजना में वन्यजीव संरक्षण के लिए भी विशेष प्रयास किए गए हैं। इसमें मप्र के नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य और दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य, उप्र के रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य के मध्य संपर्क मार्ग बनाकर एक ऐसे कॉरिडोर के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जिसकी मदद से तीन सेंचुरी में बाघ संरक्षण के लिए उपयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध हो सकेगा। इससे बाघों के संरक्षण के साथ रानीपुर में भी बाघ और दूसरे वन्यजीवों की आबादी को स्थापित करने में मदद मिलेगी। केन-बेतवा लिंक के वन्यजीवों और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप के लिए एकीकृत लैंडस्केप प्रबंधन योजना की अंतिम रिपोर्ट जारी की। इसे भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) देहरादून ने तैयार किया है। डब्ल्यूआईआई के वैज्ञानिक डॉ. रमेश प्रधान के नेतृत्व में परियोजना दल ने उन्नत वैज्ञानिक उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग कर रिपोर्ट बनाई है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

बाघ के साथ गिद्ध और घड़ियाल का भी होगा संरक्षण

दोनों नदियों और उनके आसपास के पूरे इलाके का व्यापक अध्ययन और डाटा विश्लेषण किया गया है। साथ ही प्रस्तावित गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए विस्तार पूर्वक प्रत्येक साइड का इनपुट भी एकत्र किया गया है, जिसमें बाघ, गिद्ध और घड़ियाल जैसी प्रमुख जातियों के संरक्षण और उन्हें आवास के साथ-साथ बेहतर प्रबंधन देने के लिए भी इस एकीकृत प्लान में व्यापक प्रावधान किए गए हैं। रिपोर्ट में स्थानीय परिदृश्य में जैव विविधता संरक्षण और मानव कल्याण के साथ रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा वन आश्रित समुदायों को समायोजित करने के लिए इसके तहत विशेष रूप से प्रावधान किए गए हैं। इस परियोजना की वजह से पन्ना टाइगर रिजर्व का करीब आधा हिस्सा पानी में डूब जाएगा। ऐसे में टाइगर रिजर्व के वन्य प्राणियों को सुरक्षित दूसरे स्थान पर बसाने के लिए कोर एरिया को विस्तार देने की योजना है। दोनों नदियों केन और बेतवा पर बनने वाले ढोढन बांध में अब सबसे बड़ी अड़चन पन्ना टाइगर रिजर्व ही है। पहले यहां से वन्यप्राणियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना है। इसके लिए कार्रवाई तेज हो गई है।

जी 20 में दिखा दम... हम नहीं किसी से कम

भारत की अध्यक्षता में जी-20 शिखर सम्मेलन अपने मूल एजेंडा और परिणामों के मामले में इतिहास का सबसे महत्त्वाकांक्षी व सफल सम्मेलन साबित हुआ है। इसमें कुल 112 परिणाम दस्तावेज व अध्यक्षीय दस्तावेज तैयार किए गए। पिछले सम्मेलन से तुलना करें, तो यह दोगुने से भी ज्यादा है। इसी वजह से इसे अब तक का सबसे सफल सम्मेलन माना जा रहा है। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि पूरे विश्व ने भारत की नेतृत्व क्षमता का दम देखा और उसका लोहा भी माना।

● राजेंद्र आगाल

देश की राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को आयोजित हुआ जी-20 शिखर सम्मेलन अब तक का सबसे सफल सम्मेलन साबित हुआ है। इस सम्मेलन की थीम थी वसुधैव कुटुम्बकम्। यानी पूरा विश्व एक परिवार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन के माध्यम से जहां पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोने का काम किया, वहीं भारत ने पूरे विश्व को दिखा दिया कि भारत को आखिरकार विश्व गुरू क्यों कहते हैं। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वह हासिल कर दिखाया जिसे राजनीतिक संकटों के समाधान के लिए बने अंतरराष्ट्रीय मंच हासिल नहीं कर पा रहे थे। भारत की अध्यक्षता में हुआ नई दिल्ली जी-20 शिखर सम्मेलन संतुलित विकास को लेकर अतीत में हुए संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न शिखर सम्मेलनों की लंबी शृंखला में एक अहम कड़ी जैसा रहा। इसलिए इसके समापन के बाद आज पूरा विश्व भारत की मेजबानी और ताकत का लोहा मान रहा है।

जी-20 की सफलता ने यह दर्शा दिया कि वर्तमान समय भारत का है। जी-20 में भारत के नेतृत्व पर अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक ने मुहर लगाई। इस एक सम्मेलन से भारत ने खेमों में बंटी दुनिया को एक सूत्र में बांधकर भी दिखाया। इसका परिणाम आज यह हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की क्षमता का अब पूरा विश्व कायल हो गया है। जी-20 सम्मेलन में जहां वैश्विक कर्ज के मुद्दे पर गरीब देशों की परेशानियां दूर करने के लिए विश्व बैंक जैसी संस्थाओं में सुधार पर सहमति बनी, वहीं कमजोर देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अधिक वित्तीय मदद देने पर जोर दिया गया। भारत ने इस दिशा में एक नई पहल ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की भी शुरुआत की। यह जी-20 सम्मेलन अब तक का सबसे सफल सम्मेलन माना जा रहा है।

प्लान में कामयाब भारत

भारत की अध्यक्षता में राजधानी दिल्ली में संपन्न जी-20 शिखर सम्मेलन अब तक का सबसे सफल सम्मेलन माना जा रहा है। जी-20 नेताओं ने इस सम्मेलन के पहले दिन जहां गंभीर चुनौतियों पर चर्चा करने के बाद कई फैसले किए। इसमें मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर लॉन्च और अफ्रीकी यूनियन की एंट्री पर मुहर लगी, तो वहीं दूसरे दिन भी ग्रुप में शामिल सभी देशों ने नई दिल्ली घोषणापत्र को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की जानकारी शेयर की।

जी-20 सदस्य देशों के बीच सबकी सहमित से नई दिल्ली लीडर्स समिट डिक्लेरेशन (नई दिल्ली घोषणापत्र) को अपनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी शेयर की। उन्होंने कहा कि हमारी टीमों की कड़ी मेहनत और आपके सहयोग के कारण नई दिल्ली जी-20 लीडर्स शिखर सम्मेलन घोषणा पर आम सहमति बन गई है। मैं अपने मंत्रियों, शेरपा और सभी अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इसे संभव बनाया। गौरतलब है कि पहले रूस-यूक्रेन के मुद्दे को लेकर इस घोषणा-पत्र को मंजूरी मिलने में दिक्कतें आ रही थीं।

जी-20 सम्मेलन के पहले दिन इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर लॉन्च हुआ। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इन्फ्रा डील से शिपिंग समय और लागत कम होगी, जिससे व्यापार सस्ता और तेज होगा। इसे चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना के विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा है। इस कॉरिडोर का उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल से होते हुए

15 मसौदे, 200 घंटे की वार्ता, 300 बैठकें

राजधानी दिल्ली में आयोजित जी-20 की बैठक की चर्चा हर तरफ हो रही है। इस ऐतिहासिक शिखर सम्मलेन की खास बात यह रही कि इसमें सभी देशों की सहमति के बाद पहले ही दिन वह घोषणापत्र जारी हो गया, जिसके बारे में तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। दरअसल किसी भी सम्मेलन को तभी सफल माना जाता है जबकि उसका एक घोषणा पत्र जारी हो और इस जी-20 घोषणापत्र की खास बात ये रही कि इस पर 100 प्रतिशत सहमति बनी। घोषणापत्र पर ना तो रूस-यूक्रेन विवाद का साया पड़ा और ना ही चीन की पैंतरेबाजी काम आई। नई दिल्ली घोषणापत्र पर सबकी सहमति बनाने में पर्दे के पीछे काफी मेहनत की गई। भारत के जी-20 शेरपा अमिताभ कांत ने बताया कि कैसे इस घोषणापत्र को तैयार किया गया। जी-20 में चर्चा से लेकर व्यवस्थाओं तक का जिम्मा अमिताभ कांत के पास था और कुशल नेतृत्व के कारण उन्हें न केवल प्रधानमंत्री बल्कि विपक्ष के सदस्यों से भी प्रशंसा मिली। अमिताभ कांत ने बताया कि शिखर सम्मेलन में अपनाए गए जी-20 घोषणापत्र पर आम सहमति बनाने के लिए भारतीय राजनयिकों की एक टीम को 200 घंटे से अधिक की लगातार बातचीत करनी पड़ी। कांत ने कहा, संपूर्ण जी-20 का सबसे जटिल हिस्सा राजनीतिक पैरा (रूस-यूक्रेन) पर आम सहमति बनाना था। यह 200 घंटे की नॉन-स्टॉप वार्ता, 300 द्विपक्षीय बैठकें, 15 मसौदों के बाद तैयार किया गया था। संयुक्त सचिव ईनम गंभीर और के नागराज नायडू सहित राजनयिकों की टीम ने 300 द्विपक्षीय बैठकें कीं और विवादास्पद यूक्रेन संघर्ष पर अपने समकक्षों के साथ 15 मसौदे वितरित किए, ताकि जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के पहले दिन ही सहमति बन सके। कांत ने बताया कि नायडू और गंभीर के प्रयासों से उन्हें काफी मदद मिली।

भारत से यूरोप तक फैले रेलवे मार्गों और बंदरगाह लिंकेज को एकीकृत करना है। रेल लिंक से भारत और यूरोप के बीच व्यापार करीब 40 प्रतिशत तक तेज हो सकता है। भारत के इस प्रस्ताव पर सदस्य देशों की रजामंदी, चीन के लिए बड़े झटके से कम नहीं है। इस ऐलान से चीन के प्रोजेक्ट बीआरआई को तगड़ा झटका लगा है, जिसे भारत पहले से विरोध करता रहा है। भारत के एक और प्रस्ताव पर रजामंदी दी गई है। समिट के पहले दिन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य टिकाऊ बायोफ्यूल का इस्तेमाल बढ़ाना है। बायोफ्यूल पेड़-पौधों, अनाज, शैवाल, भूसी और फूड वेस्ट से बनने वाला ईंधन होता है और इसे कई तरह के बायोमास से निकाला जाता है। इसमें कार्बन की कम मात्रा होती है। अगर इसका इस्तेमाल बढ़ेगा तो दुनिया में पारंपरिक ईंधन पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने वन अर्थ पर जी-20 समिट में पर्यावरण और जलवायु अवलोकन के लिए जी-20 सैटेलाइट मिशन शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा और नेताओं से ग्रीन क्रेडिट पहल पर काम शुरू करने का आग्रह किया। जी-20 समिट के पहले दिन में भारत ने अफ्रीकन यूनियन को जी-20 का स्थायी मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा था। बतौर अध्यक्ष सभी देशों की सहमति से प्रधानमंत्री मोदी ने इसे पारित किया। एक्सपर्ट्स की मानें तो अफ्रीका में चीन का प्रभाव बढ़ा है। ऐसे में भारत का कदम अफ्रीकी महाद्वीप पर चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए काफी अहम है। अफ्रीका को देखें तो सबसे तेजी से विकास करने वाले 12 देशों में से छह अफ्रीका से हैं। इसलिए, अगर दुनिया को उस तरफ बढ़ना है तो आपको उन्हें एक हिस्सा बनाने की जरूरत है। दूसरी ओर भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार और शिक्षा से लेकर हेल्थ और तकनीकी तक सहयोग का एक लंबा इतिहास है। जी-20 में अफ्रीकी यूनियन को शामिल करने के समर्थन की पहल दोनों देशों के बीच इसी साझेदारी का प्रतीक भी है। भारत और

संतुलित विकास पर फोकस

भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुआ जी-20 शिखर सम्मेलन संतुलित विकास को लेकर अतीत में हुए संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न शिखर सम्मेलनों की लंबी श्रृंखला में एक अहम कड़ी जैसा रहा। जून के अंत में पेरिस में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसमें जी-20 सम्मेलन से एक ऐसे विश्व के निर्माण की आशा रखी गई थी, जिसमें गरीबी न रहे, पृथ्वी का संतुलन बहाल हो और कमजोर देशों के पास भी जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाले संकटों का सामना करने का सामर्थ्य हो। लगभग यही आशा नैरोबी में हुए अफ्रीका शिखर सम्मेलन में दोहराई गई। भारत ने नई दिल्ली के जी-20 शिखर सम्मेलन में खेमों में बंटी दुनिया को एक साझा घोषणा पत्र के लिए राजी करते हुए उत्तर और दक्षिण के बीच बने असंतुलन को दूर करने, नए गलियारे बनाकर आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने, ऋण संकट समाधान के लिए विश्व बैंक जैसी वित्तीय संस्थाओं को वित्तपोषित करने और जलवायु संकट से निपटने के लिए विश्व जैव-ईंधन अलायंस बनाने जैसी दर्जनों पहल कीं, जो कुछ दिनों बाद होने वाले सतत् विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलन और अगले साल होने वाले विकास-वित्त सम्मेलन को दिशा और गति देने में सहायक सिद्ध होंगी। एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने राजनीतिक और आर्थिक खेमों में बंटी दुनिया को एक कुटुम्ब के रूप में जोड़ने का प्रयास करते हुए ऐतिहासिक सफलता हासिल की है।

अमेरिका के बीच 6जी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पर सहमति बनी है। इसके लिए जो अलायंस और एमओयू तैयार हुआ है, वह सिर्फ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने पर ही नहीं, बल्कि उसकी सप्लाई चेन विकसित करने पर भी केंद्रित है। ये चीन के कनेक्टिविटी डिवाइस सेक्टर में बाहुबल को कम करेगा। अभी 5जी के मामले में चीन का दुनिया के बाजार में दबदबा है।

जी-20 घोषणा पत्र पर सहमति

देश की राजधानी नई दिल्ली में जी-20 समिट में जी-20 लीडर्स घोषणा पत्र पर सभी देशों की सहमति बनी। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि हमारे टीम के हार्ड वर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली जी-20 लीडर्स घोषणा पत्र पर आम सहमति बन गई है। जी-20 शिखर सम्मेलन का पहला सत्र वन अर्थ था तो दूसरा सत्र, वन फैमिली रहा। इसी बीच जी-20 लीडर्स घोषणा पत्र की अहम जानकारियां सामने आईं। कई खास बातों के बीच इसमें जो ध्यान देने वाली एक बड़ी बात थी, जो कि यूक्रेन को ध्यान में रखकर की गई थी। गौरतलब है कि इस वक्त रूस और यूक्रेन युद्ध में लगे हुए हैं। दोनों देशों के बीच बीते तकरीबन ढाई साल से टकराव बना हुआ है। जी-20 समिट के दौरान यह मुद्दा भी खासतौर पर उठा है, जिसमें कहा गया कि आज का यह दौर बेशक युद्ध का नहीं है। घोषणापत्र के जारी हुए पन्नों पर ध्यान दें तो 37 पन्नों की इस घोषणा में चार बार यूक्रेन का जिक्र हुआ है। घोषणापत्र में कहा गया कि, हम गहरी चिंता के साथ अपार मानवीय पीड़ा और उस बुरे असर पर ध्यान दिलाना चाहते हैं, जो कि दुनियाभर में युद्ध और संघर्ष की वजह से पड़ता है।

यूक्रेन में युद्ध के संबंध में बाली में हुई चर्चा को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि, सभी राज्यों को संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप, सभी राज्यों को खतरे से बचना चाहिए और क्षेत्रीय अखंडता के विरूद्ध क्षेत्रीय अधिग्रहण के लिए बल का प्रयोग करने से भी दूर रहना चाहिए। किसी राज्य की संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता पर आंच नहीं आनी चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा गया कि परमाणु का उपयोग या उपयोग की धमकी दिया जाना भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। परमाणु हथियारों की धमकी से बचने का आव्हान किया गया।

घोषणापत्र में कहा गया कि, हमने यूक्रेन में युद्ध के मानवीय कष्टों और नकारात्मक प्रभावों पर प्रकाश डाला। वैश्विक खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, बड़े वित्तीय स्थिरता के संबंध में, मुद्रास्फीति और विकास, इन सभी के

भारत का जयघोष

सम्मेलन में शामिल वैश्विक नेताओं ने एक स्वर में माना कि भारत ने जिस तरह की नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया है वह अद्भुत है। जी-20 की अगली अध्यक्षता संभालने वाले ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा तो मानते हैं कि भारतीय नेतृत्व ने जो लकीर खींच दी है उस तक पहुंचना बहुत बड़ी चुनौती होगी। भारत के विरूद्ध बोलने वाले तुर्किए के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन अचंभित हैं। दिसंबर, 2022 में इंडोनेशिया से जी-20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बतौर अध्यक्ष भारत इस समूह का अपने तरीके से नेतृत्व करेगा, इसमें सभी देशों की बात सुनी जाएगी, विकासशील देशों की बात ज्यादा प्रमुखता से रखी जाएगी और ज्वलंत वैश्विक मुद्दों का न्यायसंगत निर्णय करने की कोशिश की जाएगी। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन के समापन के बाद कहा जा सकता है कि इन तीनों मुद्दों पर भारतीय प्रधानमंत्री ने जो कहा, वह कर दिखाया। हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के विरूद्ध बोलने वाले तुर्किए के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन अचंभित हैं और उनके स्वर भी बदले हुए हैं। वह कहते हैं कि भारत ने बेहद सफलतापूर्वक अध्यक्ष की भूमिका निभाई है। अगर भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनता है तो यह उनके लिए गर्व की बात होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, मैं खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को भारत की अध्यक्षता के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मौजूदा वैश्विक हालात में शांति और अमन के लिए जो अधिकतम किया जाना चाहिए, वह भारत ने बतौर अध्यक्ष किया है। भारत ने अमन का संदेश पूरी दुनिया को दिया है। उन्होंने कहा कि घोषणापत्र रूस की कूटनीतिक जीत नहीं है। यूक्रेन को हर तरह से समर्थन देने वाले यूरोपीय संघ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, जब जी-20 के अध्यक्ष के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे थे, तब भारत ने बहुत मजबूती से अपनी भूमिका निभाई। जो देश अब भविष्य में अध्यक्ष बनेंगे उनके लिए काम कैसे किया जाए, इसका एक रोडमैप दे दिया है। सिर्फ कूटनीतिक मुद्दों पर ही नहीं, बल्कि जो मुद्दे विश्व के लिए बड़ी चुनौती बनने की क्षमता रखते हैं जैसे पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा आदि, उनका संभावित समाधान देने की पहली बार कोशिश जी-20 अध्यक्ष के तौर पर हुई है। जी-20 के विकासशील देश भी खुलकर भारत के साथ हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अलबर्टो फर्नांडीस ने कहा कि विकासशील देशों के मुद्दे को अभी तक विश्व मंच पर नहीं लाया गया था। भारत ने दिखाया कि इस बारे में अब खुलकर बात होनी चाहिए। इसका असर भावी बैठकों में दिखेगा। दरअसल, भारत के बाद ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका भी विकासशील देशों की श्रेणी में हैं और भारत ने जो मुद्दे तय किए हैं, वे उन पर अमल कर सकते हैं। बताते चलें कि अफ्रीकी संघ को जी-20 में शामिल करने की बात काफी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन विकसित देश इसको लेकर गंभीर नहीं थे। भारत ने कुछ महीनों में ही इसे संभव कर दिखाया। कहा जा रहा है कि जो काम चीन अफ्रीका में अरबों डॉलर निवेश करके नहीं कर सका, उसे भारत ने अफ्रीकी यूनियन को जी-20 का सदस्य बनाकर कर दिखाया है।

जी20 शिखर सम्मेलन...

60 शहरों में 220 से ज्यादा बैठकें, 115 देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी

भारत की अध्यक्षता में दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत की अध्यक्षता इतिहास में अब तक हुई सबसे समावेशी, सांस्कृतिक रूप से जीवंत के रूप में दर्ज की गई। इस कार्यक्रम के जरिए दुनिया ने विकास के लिए भारत के प्रयासों को देखा। इस कार्यक्रम ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जीवन में आसानी सुनिश्चित करने और शांति लाने में मदद की। जी-20 कार्यक्रम के तहत दुनियाभर के 115 से ज्यादा देशों के 25,000 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ 60 शहरों में 220 से अधिक बैठकें आयोजित की गईं। ये आयोजन वसुधैव कुटुम्बकम् की अपनी थीम पर खरा उतरा क्योंकि इसमें अफ्रीकी संघ की सबसे बड़ी भागीदारी थी। भारत की ओर से आयोजित जी-20 कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यक्रमों की झड़ी लग गई। इससे विभिन्न क्षेत्रों में भारत के समावेशी विकास को प्रदर्शित करने में मदद मिली। भारत की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के दौरान खाद्य सुरक्षा और पोषण पर उच्च-स्तरीय सिद्धांत तय किए गए, पर्यटन के लिए गोवा रोडमैप, भूमि बहाली के लिए गांधीनगर कार्यान्वयन रोडमैप, एमएसएमई की सूचना तक पहुंच बढ़ाने के लिए जयपुर कॉल फॉर एक्शन, दिल्ली शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को जी-20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना शामिल है। अफ्रीकी संघ की भागीदारी ने समावेशी विकास और सभी देशों को आवाज प्रदान करने के भारत के बढ़ते संदेश ने बड़ा असर डाला। जी-20 कार्यक्रम ने भावी पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया प्रदान करने के लिए स्थिरता-आधारित विकास को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया। बाजरा को बढ़ावा देने और सभी के लिए समान स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के माध्यम से खाद्य सुरक्षा पर जोर दिया गया।

लिए युद्धों ने देशों के नीतिगत माहौल को जटिल बना दिया है। विशेष रूप से विकासशील और अल्प विकसित देश जो अभी भी इससे उबर रहे हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किलें हैं। कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक व्यवधान ने कई देशों की प्रगति को बेपटरी किया है।

घोषणा पत्र में कहा गया कि, हम तुर्की और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाले इस्तांबुल समझौतों के प्रयासों की सराहना करते हैं। इसमें रूसी संघ और तुर्की के बीच समझौता ज्ञापन शामिल है, जिसका प्रमुख उद्देश्य रूसी खाद्य उत्पादों और उर्वरकों को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय विश्व बाजारों और अनाज के सुरक्षित परिवहन पर पहल के लिए काम कर रहा है, और यूक्रेनी बंदरगाहों से खाद्य पदार्थों को पूर्ण, समय पर और सुरक्षित तरीके से पहुंचाने के लिए कदम उठाया जा रहा है। इसके साथ ही, रूसी संघ और यूक्रेन से खाद्य पदार्थों और उर्वरकों की तत्काल और अबाधित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य विकासशील और अल्प विकसित देशों, विशेषकर अफ्रीका में, मांग को पूरा करने में मदद करना है। इस संदर्भ में, हम खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा को बनाए रखने के महत्व पर जोर दे रहे हैं। हमने सैन्य विनाश या अन्य हमलों को रोकने का आग्रह किया है, जो प्रासंगिक बुनियादी ढांचे पर हो सकते हैं। हमने संघर्षों से पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के बारे में भी गहरी चिंता व्यक्त की है, जो नागरिकों की सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं और मौजूदा सामाजिक-आर्थिक कमजोरियों को और बढ़ा सकते हैं। ये कमजोरियां और प्रभावी मानवीय प्रतिक्रिया में बाधा डाल सकती हैं। हम सभी राज्यों से क्षेत्रीय सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को बनाए रखने का आग्रह करते हैं। यह कानून अखंडता और संप्रभुता, अंतरराष्ट्रीय

मानवीय कानून और बहुपक्षीय प्रणाली की मान्यता करता है, जो शांति और स्थिरता की रक्षा करता है। संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान और संकटों के समाधान के साथ-साथ कूटनीति और संवाद भी महत्वपूर्ण हैं। हम अपने में एक हो जाने का प्रयास करते हैं ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर युद्ध के प्रतिकूल प्रभाव को संबोधित कर सकें, और हम सभी प्रासंगिक और रचनात्मक पहलों का स्वागत करते हैं जो व्यापक, न्यायपूर्ण, और यूक्रेन में स्थायी शांति और मैत्रीपूर्ण और अच्छे पड़ोसी संबंधों को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। यह हमारी एक पृथ्वी, एक परिवार, और एक भविष्य की भावना में राष्ट्र के सभी उद्देश्यों और सिद्धांतों को कायम रखने का संकल्प है। आज का दौर बेशक युद्ध का दौर नहीं है।

भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वह हासिल कर दिखाया जिसे राजनीतिक संकटों के समाधान के लिए बने अंतरराष्ट्रीय मंच हासिल नहीं कर पा रहे थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए कुछ नहीं कर पा रही और आमसभा जैसे मंचों के प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित न हो पाने के कारण निष्प्रभावी रहे। इसीलिए भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में संपन्न जी-20 शिखर सम्मेलन के कुछ दिन पहले तक किसी को उम्मीद नहीं थी कि घोषणा पत्र पर सहमति बन पाएगी।

चीनी राष्ट्रपति के इस सम्मेलन में न आने का अर्थ यह लगाया गया था कि चीन की मंशा भारत का खेल बिगाड़ने की है, परंतु भारतीय राजनयिकों के कौशल और अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में भारत के बढ़ते कद ने असंभव को संभव कर दिखाया। शिखर सम्मेलन के पहले दिन ही घोषणा पत्र पर आम सहमति जुटाकर भारत ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की अपनी दावेदारी को भी मजबूत किया। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई द्विपक्षीय शिखर वार्ता में भारत की इस दावेदारी के समर्थन को दोहराया।

घोषणा पत्र में रूस का नाम न लेते हुए यूक्रेन में जारी युद्ध से हो रही मानवीय यातना और वैश्विक खाद्य एवं ऊर्जा संकट पर चिंता व्यक्त की गई। इस पर जोर दिया गया कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मुताबिक सभी देशों को किसी अन्य देश की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरूद्ध धमकी या बलप्रयोग से बचना चाहिए। साथ ही परमाणु हथियारों के प्रयोग या प्रयोग की धमकी को भी अस्वीकार किया गया।

यूक्रेन और यूरोप के देश यूक्रेन में युद्ध हो रहा कहने और हमलावर का नाम न लेने से नाखुश हैं, परंतु यूक्रेन युद्ध के बाद से अमेरिका-नाटो और रूस-चीन के बीच बढ़ते तनाव के माहौल में नाम लिए बिना भी ऐसे घोषणा पत्र पर रूस और चीन की सहमति जुटाना किसी ऐतिहासिक उपलब्धि से कम नहीं। इस घोषणा पत्र से यूक्रेन युद्ध में तो किसी बदलाव के आसार नहीं, लेकिन इससे अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में यह संदेश अवश्य गया कि यदि कोई देश रूस को समाधान के लिए तैयार कर सकता है तो वह शायद भारत ही होगा।

55 देशों के संगठन अफ्रीकी संघ को जी-20 की सदस्यता दिलाकर इसे जी-21 में बदल देना भी भावी विकास और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की दृष्टि से भारत की बड़ी उपलब्धि है। अफ्रीकी संघ के सदस्य बनने से जी-20 में दक्षिणी देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। अभी तक वहां जी-7 देशों, यूरोपीय संघ के 25 देशों, रूस, चीन और तुर्किए को मिलाकर उत्तर का पलड़ा भारी था। अफ्रीकी देशों की सदस्यता के बाद दक्षिणी देशों की संख्या बढ़ जाएगी। वैसे चीन और रूस दोनों अफ्रीकी देशों को सदस्यता दिलाने का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं।

चीन ने पिछले दो-तीन दशकों से अफ्रीकी देशों में भारी निवेश किया है और रूस भी निवेश के साथ-साथ राजनीतिक उठापटक कराने में लगा रहता है, पर चीनी निवेश से अफ्रीकी देशों में कर्ज संकट पैदा हुआ है और रूस के भाड़े के सैनिक अफ्रीकी देशों में विद्रोह करा रहे हैं। भारत के अफ्रीका से हजारों साल पुराने व्यापारिक और सामाजिक रिश्ते हैं। भारत का स्वाधीनता आंदोलन अफ्रीकी देशों के स्वाधीनता आंदोलनों का प्रेरणास्रोत बना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व करते हुए भारत हमेशा दक्षिणी देशों की आवाज बुलंद करता आया है। इसलिए अफ्रीकी संघ को उत्तर और दक्षिण के साझा मंच जी-20 की सदस्यता दिलाने से भारत को स्वाभाविक रूप से दक्षिण की आवाज बनने में मदद मिलेगी।

जी-20 में भारत के चौके से निकलेगी चीन की हेकड़ी

भारत ने जी-20 शिखर सम्मलेन का सफल आयोजन कर दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखा दी। दुनिया के ताकतवर नेताओं का भारत ने भव्य स्वागत किया। जी-20 की सफलता से अगर किसी को मिर्ची लगी तो वो चीन है। समिट में कुछ ऐसे फैसले भी लिए गए, जिसने अब चीन की नींद उड़ा दी है। अब चीन में इसे लेकर खलबली मची है। दुनिया को धौंस दिखाने वाला चीन अब टेंशन में है। भारत, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमीरात मिलकर एक ऐसा रेल और समुद्री कॉरिडोर तैयार करने जा रहे हैं, जो कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) से कहीं बेहतर है। चीन के वन बेल्ट रोड के जवाब में जी-20 में भारत ने मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर मुहर लगा दी। सिर्फ यही नहीं जी-20 में ऐसे फैसले हुए, जिससे चीन की धौंस, उसकी हेकड़ी निकल जाएगी। जाहिर है कि भारत के इस सफल आयोजन से चीन में खलबली तो मचेगी। चीन की नाराजगी दिखने भी लगी। चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेंपरी इंटरनेशनल रिलेशन्स ने कहा कि भारत ने जी-20 के वैश्विक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए किया। जी-20 में कुछ ऐसे फैसले लिए गए, जो चीन की दादागिरी को खत्म करने के लिए काफी हैं। भारत और अन्य देशों के बीच हुए इस समझौते ने चीन की हेकड़ी को कम करने का काम किया है। ऐसे ही फैसलों में सबसे बड़ा समझौता इंडिया मिडल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है। भारत से यूरोप तक पहुंचने का ऐसा रूट तैयार कर लिया गया, जो चीन के बीआरआई रूट का मुंहतोड़ जवाब है। पश्चिमी एशिया होते हुए यूरोप ट्रेड कॉरिडोर बनाने के प्रोजेक्ट पर सहमति बनी है। भारत ने चीन के बीआरआई के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है। इसके तहत रेल, पोर्ट, ट्रांसपोर्ट, हवाई मार्ग, डेटा केबल और दूसरी तकनीकों के जरिए तीनों क्षेत्रों को जोड़ने का फैसला हुआ है। इसका असर चीन के दबदबे पर होगा। वहीं भारत के कारोबार में तेजी आएगी।

एक देश एक उर्वरक योजना कितनी जरूरी

कालाबाजारी या फिर धोखाधड़ी रुकेगी

इस योजना के माध्यम से सभी निजी और सार्वजनिक कंपनियां भी अब अपनी उर्वरक खादों को भारत ब्रांड नाम से बेच सकेंगी। सरकार के द्वारा बनाई जाने वाली इन बोरियों का डिजाइन छपने के बाद भी अगर कोई उर्वरक खादों की खरीद और बिक्री में कालाबाजारी या फिर धोखाधड़ी करता पाया जाता है, तो उसके लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान होगा। इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार का मकसद किसानों का हित करके उनकी आय बढ़ाना है। अभी तक देश में 45.6 प्रतिशत किसान कृषि करते हैं। इन किसानों के कल्याण के लिए सरकार ने एक देश एक उर्वरक योजना के माध्यम से उनको एक ही छत के नीचे उर्वरक खादों को सुलभता से उपलब्ध कराने का निर्णय लेकर कृषि उपज बढ़ाने का सपना देखा है। इस योजना की सफलता के सूत्रधार प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र बनेंगे। इस योजना के सफल होने पर पूरे देश में 3,00,000 से अधिक प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खोले जाएंगे, जिनके माध्यम से एक छत के नीचे देश के किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरकों-खादों, सभी प्रकार के बीजों, खरपतवारों और कीटों को नष्ट करने वाली सभी गुणवत्तापूर्ण दवाओं और कृषि यंत्रों, छोटे उपकरणों को भी उपलब्ध कराया जाएगा।

कृषि से पैदा होने वाली चीजें शाकाहारियों का भोजन हैं। कह सकते हैं कि शाकाहारियों के जीने का साधन यही चीजें होती हैं। इसीलिए पुराने समय में ही मानव की जीवन शैली में कृषि का विकास कर लिया था। बढ़ती जनसंख्या से कृषि भूमि हर दिन कम होती जा रही है, जिसके लिए कृषि उपज बढ़ाने की कोशिश होती रही है। हमारे कृषि प्रधान देश में किसानों की यही कोशिश रहती है कि वे अपने खेतों में खूब सारा अनाज और खूब सारी सब्जियां उपजाएं। उनकी यह कोशिश तो इसलिए होती है कि उनकी आय बढ़े, लेकिन कृषि उपज बढ़ती है, तो उन सबका पेट भी भरता है, जो कृषि नहीं करते और जिनके पास खेत नहीं हैं। कृषि उपज बढ़ाने को सबसे जरूरी है- खेत की मिट्टी का उपजाऊ होना। इसके लिए किसान अपने खेतों में खाद लगाते हैं। किसानों को गुणवत्ता वाली फसल उगाने के लिए अच्छी खादों, अच्छे बीजों और अच्छी मेहनत की जरूरतें होती हैं। केंद्र सरकार ने कृषि उपज बढ़ाने के लिए एक देश एक उर्वरक योजना शुरू की है। केंद्र सरकार की मंशा है कि किसानों को बिना किसी मिलावट के अच्छी उर्वरक और खादें मिल सकें और फसलों के लिए जरूरी खादों में मिलावट न हो। खादों की कालाबाजारी न हो सके। खादों के भाव अलग-अलग होते हैं।

केंद्र सरकार यह चाहती है कि किसानों को इन सब समस्याओं से छुटकारा मिले और उनको खेती के लिए आसानी से कम और एक कीमत पर सभी प्रकार की खादें और उर्वरक मिल सकें। इस योजना के अंतर्गत अब तक देश में बिकने वाली अलग-अलग कंपनियों की खादें अब एक ही पैकिंग में उर्वरक-खाद भारत ब्रांड के नाम से पूरे देश में हर राज्य के किसानों को केवल भारत ब्रांड के नाम से ही बेची जाएंगी। इससे पूरे देश के किसानों को एक ही दाम में एक ही पैकिंग में सभी खादें और उर्वरक मिल सकेंगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना के अंतर्गत एक देश एक उर्वरक योजना-2023 (वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम-2023) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट (डीएपी), म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी), नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम (एनपीके) अगले समय में भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी और भारत एनपीके के नाम से ही बाजार में बिकेंगी। केंद्र सरकार में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी उर्वरक (फर्टिलाइजर) कारखानों को सरकारी बोरों के नमूने भेजे हैं, जिनमें अब सभी खादों की पैकिंग की जाएगी। अब इन उर्वरक कारखानों, स्टेट ट्रेडिंग कंपनियों और उर्वरकों की विपणन कंपनियों को केंद्र सरकार द्वारा सभी सब्सिडी वाली खादों और उर्वरकों को उन्हीं बोरियों में भरकर बेचना होगा, जिन पर सिंगल ब्रांड नाम होगा और प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का लोगो लगा होगा। इससे पूरे देश के किसानों को अब एक ही जैसी पैकिंग में एक ही भाव में सभी उर्वरकों, खादों को उपलब्ध कराया जा सकेगा। एक देश एक उर्वरक योजना के तहत एक ही वजन की बोरियों में एक ही तरह की लिखावट में सभी खादों को उनके नाम से बेचा जाएगा, तो इससे यह तय हो जाएगा कि ये केंद्र सरकार की सब्सिडी वाली खादें हैं, जिससे किसानों को कोई दुकानदार नकली खादें ऊंचे भाव में नहीं बेच सकेगा। किसान दूसरी ब्रांड की उर्वरक भी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उनको दूसरी ब्रांड की उर्वरक और खादों पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। इससे सरकारी खादों के अलग-अलग ब्रांडों की खादों के बीच की असमानता भी खत्म होगी और सरकारी ब्रांडों की नकल बाजारों में नहीं मिल सकेगी।

केंद्र सरकार की योजना के अनुरूप सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने इसी साल की 24 अगस्त को एक अधिसूचना जारी करके बताया है कि एक देश एक उर्वरक योजना के अंतर्गत नए उर्वरक बैगों में खादों को भरकर आगामी महीने 2 अक्टूबर से प्रचलन में लाया जाएगा, जो कि किसानों को मिल सकेंगे। एक देश एक उर्वरक योजना के तहत उर्वरक कंपनियां इन उर्वरक खादों की बोरियों के एक-तहाई हिस्से पर अपना नाम, ब्रांड का नाम, अपना लोगो और अन्य आवश्यक सूचनाएं अंकित करेंगी, जो कि जरूरी है। इन खादों की बोरियों के दो-तिहाई हिस्सों पर भारत ब्रांड और प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का लोगो होगा, जिसे संक्षेप में पीएमबीजेपी कहा जाएगा। कुछ लोग इस नाम को पीएम और बीजेपी का प्रचार बता रहे हैं, तो कुछ इसे केंद्र सरकार की किसान हितैषी योजना बता रहे हैं। माना जा रहा है कि पूरे देश में यह व्यवस्था होने से देश के किसानों को सहूलियत हो जाएगी और निर्माता कंपनियों को नुकसान नहीं होगा। पुराने बोरों की खादों के उपयोग करने के लिए सरकार ने कंपनियों और वितरकों को 31 दिसंबर, 2023 तक का समय दिया है। इसके बाद से सभी कंपनियों द्वारा प्रमाणिक खादों और उर्वरकों को केंद्र सरकार के द्वारा जारी बोरियों में ही बेचा जाएगा।

● **राजेश बोरकर**

4 राज्यों में 'इंडिया' की अग्निपरीक्षा

कुछ समय पहले तक यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि 2024 में 27 विपक्षी दल एक साथ आकर एक मजबूत विकल्प के रूप में केंद्रीय सत्ता के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। पर अब यह एक हकीकत है कि अपने तमाम मतभेदों, वैचारिक भिन्नताओं के बावजूद ये दल अब काफी हद तक इंडिया नामक गठबंधन में बंध गए हैं।

पटना, बेंगलुरू और मुंबई की तीन शिखर बैठकों के बाद 27 दल गठबंधन की दिशा में इतनी दूर तक आगे बढ़ चुके हैं कि इनमें से अब किसी एक का भी पीछे लौटना उसकी राजनीतिक साख के लिए घातक साबित हो सकता है। इसलिए अब यह मानकर चलना होगा कि इंडिया गठबंधन अब एक नई राजनीतिक सच्चाई है, जो आगामी आम चुनावों में जनता को आश्वस्त और अपनी ओर आकर्षित करने की पूरी क्षमता रखता है। यह एक ऐसी सच्चाई बन चुका है, जिसे सत्तापक्ष व जनता द्वारा हल्के में नहीं लिया जाएगा। इस गठबंधन पर अनाप-शनाप टीका-टिप्पणी करके, अंतर्विरोधों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाकर और मजाकिया नाम देकर इसे सत्ता की दौड़ से दूर दिखाना असंभव हो गया है। इसके अलावा यह भी स्वीकार करना होगा कि चुनाव पूर्व और चुनाव बाद इंडिया गठबंधन के घटक दलों की संख्या बढ़नी ही है, घटनी नहीं है।

राजनीति के सामाजिक आधारों की बात करें तो इसका आधार पिछड़े, आदिवासी, दलित व अल्पसंख्यक समुदायों में है, जो आबादी की दृष्टि से बहुसंख्यक हैं। संभवत: इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी ने मुंबई में दावा किया कि गठबंन्धन देश की 60 फीसदी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, इसे हराना असंभव है। यदि सामाजिक बहुमत राजनीतिक बहुमत में बदल सके तो यह गठबंधन सत्ता में भी आ सकता है।

यह गठबंधन एक ऐसा देशव्यापी गठबंधन है जो 11 बड़े राज्यों में सरकार में है, विधायकों की संख्या की दृष्टि से एनडीए से थोड़ा ही कम है, लोकसभा में इसके 142 और राज्यसभा में 98 सांसद हैं। इसके पास एनडीए के विपरीत प्रधानमंत्री पद के लिए कोई तय चेहरा भले न हो लेकिन देश के कई वरिष्ठ, अनुभवी और जनाधार वाले नेता हैं जिनके पास चुनावी राजनीति और प्रशासन का अप्रश्नेय अनुभव है। मुंबई बैठक के बाद संयोजक, मीडिया व संचार और चुनाव रणनीति व प्रचार समितियों के गठन से यह पता चलता है कि ये दल अब मिलकर कार्रवाई करने को तैयार हैं। सहयोग अब केवल शीर्ष नेताओं की बैठकों तक ही सीमित नहीं रह गया है। इस बैठक के बाद संयुक्त बयान में आगामी दिनों में देश के अनेक भागों में बड़ी जनसभाओं के आयोजन की भी बात कही गई है। इसके अलावा इसी माह के अंत तक सीटों के बंटवारे को लेकर भी फैसले लिए जाने की बात सामने आई है। कहने का आशय यह है कि स्वयं को 2024 में मतदाताओं के सामने सत्ता के दावेदार विकल्प के रूप में पेश करने के लिए इंडिया गठबंधन एक-एक करके धीरे-धीरे अपनी सभी बाधाएं दूर करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है।

फिर भी इसकी कामयाबी और एकजुटता के मामले में मुख्यधारा के मीडिया संस्थानों और एनडीए नेताओं को छोड़ भी दें तो भी अब भी कुछ राजनीतिक प्रेक्षक और टीकाकार यह अंदेशा जताते हैं कि गठबंधन अंतत: आंतरिक विघटन का शिकार होकर सुस्त हो जाएगा और परिणामस्वरूप मतदाताओं की नजरों में नहीं चढ़ पाएगा। राजनीति संभावनाओं का खेल है। इसमें कभी भी कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता है जैसा कि महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ हो चुका है। ऐसा और भी किसी प्रदेश में किसी दल के साथ हो सकता है। पर 2024 में नई सरकार का गठन दलबदल और पार्टियों को तोड़कर नहीं, बल्कि मतदाताओं के दिल जीतने की अग्निपरीक्षा से गुजरने के बाद होना है। ऐसे में संभावनाओं के द्वार पूरी तरह से खुले हुए हैं। ऐसे प्रेक्षक और टीकाकार उन सकारात्मक तत्वों और राजनीतिक वास्तविकताओं की उपेक्षा करते हैं जिन्होंने ऐसे विशाल और बहुरंगी गठबंधन की असंभव संभावना को संभव बना दिया है। कांग्रेस को छोड़कर सभी पार्टियों के शीर्ष नेता या तो राज्यों में सरकार चला रहे हैं या फिर उनका पूरा ध्यान राज्य में सत्ता हासिल करने पर है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार पहले तो उम्र के कारण और दूसरे अपनी पार्टी को एकजुट न रख पाने के कारण प्रधानमंत्री की रेस से बाहर हैं।

सीपीएम में प्रधानमंत्री बनने लायक

भोपाल में हो सकती है बड़ी रैली

विपक्षी आईएनडीआईए के शीर्षस्थ नेताओं की चौथी बैठक चुनावी राज्य मप्र की राजधानी भोपाल में होगी। वैसे इसकी तारीखें अभी तय नहीं हुई है, मगर संकेतों से साफ है कि संसद के बुलाए गए विशेष सत्र के बाद अक्टूबर की शुरूआत में यह बैठक होगी। इस बैठक के साथ ही आईएनडीआईए की पहली साझा राजनीतिक रैली भी भोपाल में ही होगी। मप्र चुनाव के मद्देनजर भोपाल रैली के जरिए विपक्ष की एकजुटता को लेकर उठने वाले किंतु-परंतु के सवालों को थामने का भी प्रयास होगा। विपक्षी खेमे के सूत्रों के अनुसार मुंबई में 1 सितंबर को हुई आईएनडीआईए की तीसरी बैठक के दौरान ही भोपाल को अगली बैठक का पड़ाव बनाने का फैसला नेताओं ने कर लिया। साथ ही यह भी तय हुआ कि आईएनडीआईए की पहली साझा रैली के लिए भोपाल कई मायनों में अनुकूल होगा। इसमें सबसे अहम है कि जिन पांच राज्यों में इस वर्ष के आखिर में चुनाव होने हैं उनमें मप्र ही एकमात्र राज्य है जहां भाजपा की सरकार है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हैं तो मिजोरम में क्षेत्रीय पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट की सत्ता है जो फिलहाल भाजपा गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में जाहिर तौर पर 2024 के चुनाव में मोदी सरकार को चुनौती देने की ताल ठोक रहे विपक्ष के लिए मप्र का 2023 का चुनावी सेमीफाइनल एक सियासी टेस्ट केस है।

कोई दूसरा ज्योति बसु नहीं है, और उसे कोई मुगालता भी नहीं है। डीएमके के नेता स्टालिन राज्य में ही खुश हैं। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं ही, और 2024 के बाद भी बने रह सकने की संभावना से भरे हुए हैं। ऐसे में वे प्रधानमंत्री न भी बने तो उनका कोई नुकसान नहीं है, सिवाय नीतीश कुमार के, जिन पर तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री की गद्दी खाली करने का दबाव हो सकता है। क्षेत्रीय दलों का कोई और नेता दिल में भले पीएम बनने की लालसा पाले हो पर सामने शायद ही आए। राहुल गांधी ने भले ही अपनी इच्छा न जाहिर की हो पर कांग्रेस के नेता व मुख्यमंत्री निजी हैसियत में उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बता चुके हैं। इसके बावजूद राहुल गांधी भी सत्ता के लिए बेचैन नहीं हैं बल्कि वे भाजपा को बेदखल करने में ज्यादा रुचि रखते हैं। वे तभी प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे जब उनकी पार्टी की सीटों की स्थिति मजबूत हो। इसके लिए उसे 150 से अधिक सीटें जितनी होंगी। अभी तक के माहौल में यह मुश्किल लगता है पर चुनाव नजदीक आने पर जनता उसके पक्ष में मूड बना ले तो यह हो भी सकता है। उसका आधार अब भी बहुत बड़ा है। ऐसे में इंडिया घटक दलों का कोई नेता पीएम बनने के लिए बेचैन हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। यह एक सकारात्मक बात है जो गठबंधन को बांधे रह सकती है।

लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम अपनी पार्टियों के नुकसान करके भी साथ चुनाव लड़ेंगे। ऐसा और पार्टियां भी सोचती होंगी। इसका कारण यह है कि इन पार्टियों के शीर्ष नेताओं को निजी स्तर पर कोई नुकसान नहीं उठाना है और न ही त्याग का कष्ट करना है। वे तो पार्टी के दूसरे नेता होंगे जो सीटें सहयोगी दलों के खाते में चले जाने के बाद नुकसान का खामियाजा भुगतेंगे। पर वे भी शायद न पार्टी का कुछ नुकसान करने की स्थिति में होंगे न शीर्ष नेतृत्व को नाराज करने की स्थिति में। ऐसे में सीटों का बंटवारा भी आसानी से हो सकता है। पर इंडिया गठबंधन इस महत्वाकांक्षा में नहीं जी रहा है कि उसे एक सीट पर एक ही उम्मीदवार देना है। मुंबई बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया है जहां तक संभव होगा हम मिलकर लड़ेंगे। यानि कि जहां भाजपा या एनडीए या गुटनिरपेक्ष दलों से उनकी टक्कर नहीं है, जहां घटक दल आपस में ही एक-दूसरे के मुख्य प्रतिद्वंद्वी हैं वहां अलग-अलग चुनाव लड़ने के विकल्प खुले रखे हुए हैं। बंगाल व केरल इसके लिए सबसे प्रासंगिक राज्य हैं। दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस और आप मिलकर भी लड़ सकते हैं। रणनीति की यह उदारता भी गठबंधन की एक शक्ति है। चुनाव लड़ने की इस उदार रणनीति ने उसकी राह आसान कर दी है। इनके अलावा एक और सकारात्मक बात है जो विपक्षी गठबंधन को आंतरिक विघटन से बचाए हुए है। वह है गठबंधन के संयोजक व प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर किसी एक नेता के नाम पर चुनाव पूर्व आमराय न बनाने की कोशिश। नेता के बजाय टीम की तरह काम करना भी एक अच्छी रणनीति है। कुल मिलाकर कहें कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के सिवा अन्य घटक दलों को खोने के लिए कुछ खास नहीं है जबकि पाने के लिए सारा जहां है।

केंद्र की मोदी सरकार को हटाने के लिए एकजुट विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस यानी आईएनडीआईए (इंडिया) की अगली बैठक चुनावी राज्य मप्र के भोपाल में हो सकती है। हालांकि इसकी तारीख तय नहीं हो सकी है। सूत्रों के अनुसार भोपाल में बैठक के साथ ही विपक्षी नेताओं की एक जनसभा भी हो सकती है। सूत्रों की मानें तो अगली बैठक आयोजित करने के विकल्प पर मुंबई में विपक्षी दलों की हाल ही में हुई बैठक में चर्चा की गई थी और भोपाल में बैठक आयोजित करने पर व्यापक सहमति थी। हालांकि कोई तारीख तय नहीं की गई थी और इसके तौर-तरीकों पर काम नहीं किया गया था। सूत्रों ने कहा कि विपक्षी गठबंधन की अगली बैठक अक्टूबर की शुरुआत में हो सकती है। विपक्षी नेताओं ने दिल्ली को भी एक विकल्प माना है।

बता दें कि विपक्षी नेता एनडीए से मुकाबला करने के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं, जो संसद सत्र के दौरान भी दिखाई दिया था। इंडिया गठबंधन पहले ही पटना, बेंगलुरू और मुंबई में तीन बैठकें कर चुका है और अब वह चुनाव नजदीक आने पर विभिन्न स्थानों पर एनडीए के खिलाफ संयुक्त रैलियां आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। बता दें मप्र में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसलिए बैठक को अहम माना जा रहा है। बता दें विपक्षी दलों के गठबंधन ने आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए एकजुट होकर लड़ने का ऐलान किया है।

● **विपिन कंधारी**

अन्य पार्टियों को साधेगी कांग्रेस

सूत्रों का कहना है कि भोपाल में इंडिया की बैठक के पीछे कांग्रेस की कोशिश है कि विधानसभा चुनाव से पहले सपा और आप जैसी पार्टियों का साधा जाए। विपक्षी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण यह है कि सूबे में भाजपा से ही उसकी सीधी लड़ाई है और पार्टी भोपाल रैली के जरिए पूरे देश में विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने का संदेश दे सकती है। आईएनडीआईए की अगली बैठक के लिए मप्र का चुनाव करना विपक्षी खेमे के नेताओं के लिए भी सहज है क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे दलों के लिए मप्र में अभी कोई सियासी गुंजाइश नहीं है। समाजवादी पार्टी का कुछ एक जिलों में प्रभाव है भी तो वह ऐसा नहीं कि कांग्रेस की सिरदर्दी बढ़ाए। इस लिहाज से भोपाल में आईएनडीआईए की पहली रैली में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जैसे नेताओं को ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। विपक्ष की भोपाल बैठक के मेजबान स्वाभाविक रूप से मप्र कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ होंगे। कांग्रेस के लिए यह सुखद इसलिए भी है कि ममता बनर्जी, शरद पवार, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव से लेकर सीताराम येचुरी समेत तमाम अन्य विपक्षी दिग्गजों से कमलनाथ के अच्छे निजी संबंध भी हैं। आईएनडीआईए की संयुक्त रैली मप्र में कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान को विपक्ष की साझा ताकत की ऊर्जा देगी। वहीं आईएनडीआईए इसके जरिए गठबंधन की एकजुटता को लेकर बार-बार उठाए जा रहे सवालों को थामने का मौका देगा।

अगस्त महीने का अंतिम दिन और सितंबर महीने का पहला दिन विपक्ष के लिए बहुत ही अचंभित करने वाला प्रमाणित हुआ। 31 अगस्त को सरकार ने सूचित किया कि 18 से 23 सितंबर तक संसद का पांच दिन का विशेष अधिवेशन बुलाया जाएगा। अभी विपक्ष अनुमान ही लगा रहा था कि यह विशेष अधिवेशन किसलिए बुलाया जा सकता है कि सरकार ने दूसरी अचंभित करने वाली घोषणा 1 सितंबर को कर दी। सरकार ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा जो भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श कर सरकार को सलाह देगी।

वन नेशन वन इलेक्शन कितना जरूरी... ?

दो-तीन क्षेत्रीय दलों को छोड़कर देश के राजनीतिक दल इस समय एनडीए और इंडिया एलायंस में बंटे हैं। ऐसे राजनीतिक टकराव के माहौल में वन नेशन वन इलेक्शन संभव नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक कानून नहीं बनना है। लोकसभा और विधानसभाओं की फिक्स्ड टर्म करने के लिए कई संविधान संशोधन भी करने पड़ेंगे। कहीं भी सरकार गिरने पर क्या होगा, मध्यावधि चुनाव होगा तो नए निर्वाचित सदन की अवधि क्या होगी। कई तरह के पेच हैं, जिनका समाधान और फिर संविधान संशोधन, जिसके लिए मोदी सरकार के पास दो तिहाई बहुमत होना जरूरी है, जो इस समय कतई संभव नहीं है। लेकिन राजनीतिक दलों में खलबली मची है। दो तरह की अटकलें हैं, या तो मोदी पांच विधानसभाओं का चुनाव लोकसभा चुनावों तक टालेंगे, इसके लिए इन राज्यों में राष्ट्रपति राज लगाना पड़ेगा। वह भी इतना आसान नहीं है। दूसरी चर्चा यह है कि भाजपा शासित हरियाणा, महाराष्ट्र को साथ जोड़कर लोकसभा चुनाव ही इसी साल नवंबर-दिसंबर में करवा देंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने पांच साल के कार्यकाल का एक दिन भी जाया होने नहीं देंगे, वह श्रीरामजन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किए बिना चुनावों में नहीं उतरेंगे, इसलिए इसी साल लोकसभा चुनावों की अटकल फिजूल है। हां, बिना कुछ ज्यादा संशोधन किए मोदी सरकार अप्रैल-मई 2024 में लोकसभा चुनावों के साथ 12 राज्यों के चुनाव करवाने की रणनीति बना सकती है।

राजनीतिक हलकों में अटकले हैं कि इस साल होने वाले पांच राज्यों में भावी लोकसभा चुनावों तक राष्ट्रपति राज लगाया जा सकता है। जिसे बहुमत के सहारे संसद के दोनों सदनों से पास करवाया जा सकता है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, ओडिशा और सिक्किम के चुनाव तो लोकसभा के साथ होते ही हैं। इनके साथ भाजपा शासित महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव भी साथ हो सकते हैं। हालांकि पांच राज्यों में राष्ट्रपति राज के खिलाफ देशभर में आंदोलन शुरू हो जाएगा, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी इस राजनीतिक आंदोलन का सामना नहीं करना चाहेंगे। इसलिए आम सहमति के बिना देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा फिजूल है। वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा नई नहीं है। 1952 से 1967 तक पहले चार चुनाव साथ-साथ ही हुए थे। हालांकि केरल में यह सिलसिला 1959 में ही टूट गया था जब जवाहर लाल नेहरू सरकार ने ईएमएस नम्बुदरीपाद की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त करके केरल विधानसभा को भंग कर दिया था।

1967 के बाद तो दलबदल से सरकारें टूटने

एक राष्ट्र एक चुनाव में आने वाली चुनौतियां

एक राष्ट्र एक चुनाव में आने वाली कुछ संवैधानिक चुनौतियां हैं, जैसे अनुच्छेद 356 कहता है कि बिना वैध कारण के किसी भी विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता। इस कारण जिन विधानसभाओं में विपक्षी दलों की बहुसंख्या है या जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां पर बड़ी अड़चन आ सकती है। उन्हें यह लग सकता है कि यह भाजपा का एक षड्यंत्र है जिसके अंतर्गत उनकी सरकार के कार्यकाल को छोटा किया जा रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि इस पर एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए एक राष्ट्रव्यापी सहमति हो जिसमें सभी विपक्षी दल इस बात पर सहमत हों कि उनकी विधानसभा का जो भी कार्यकाल बचा है उसे समाप्त कर दिया जाए और लोकसभा के साथ ही उनके चुनाव कराए जाएं। यदि ऐसा हो जाता है तो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो सकते हैं। परंतु चुनौती यहीं समाप्त नहीं होती। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मान लीजिए किसी कारणों से किसी विधानसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता या पार्टियां टूट जाती हैं, जिसके कारण विधानसभा को भंग करना पड़ता है तो उस स्थिति में क्या होगा?

लगीं, और मध्यावधि चुनाव होने लगे तो चुनाव तमाशा बनकर रह गए। हर साल कहीं न कहीं चुनाव होता रहता है, साल में भी कई-कई बार चुनाव होता रहता है। चुनाव आयोग पूरे साल चुनावों में उलझा रहता है। देश में कहीं न कहीं आचार संहिता लगी ही रहती है, इसलिए विकास कार्य प्रभावित होते हैं। एक बार चलता हुआ काम रुक जाए, तो आचार संहिता हटने के बाद भी लंबा समय रुका रहता है। इसलिए एक साथ चुनाव करवाने की परंपरा को फिर से पटरी पर लाने के लिए देशभर में विमर्श चलता रहा है। खुद इंदिरा गांधी भी इसकी पक्षधर थीं। उन्हीं की पहल पर 1983 में चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाने का सुझाव दिया था। दुर्भाग्य से 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और चुनाव आयोग की सिफारिश पर काम नहीं हुआ। राजीव गांधी का एजेंडा ही कुछ और था, वह तात्कालिक विषयों में ही उलझे रहे, और इस गंभीर विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस विषय को बड़ी गंभीरता से उठाया था।

अटल बिहारी वाजपेयी ने विधि आयोग से इस संबंध में अध्ययन करने को कहा था, क्योंकि 1967 के बाद बहुत कुछ बदल गया था। दलबदल कानून आ चुका था, अनुच्छेद 356 लगाकर विधानसभा भंग करने के केंद्र सरकार के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट की बंदिश लग चुकी थी। बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी कर दी थी। केंद्र सरकार और संसद के अधिकार में पहले जैसी ताकत नहीं रह गई थी। वाजपेयी की पहल पर 1999 में विधि आयोग ने विचार-विमर्श के बाद एक साथ चुनाव करवाने की सिफारिश की थी। सिफारिश में यह सुझाव भी था कि अगर कोई सरकार गिर जाए, तो विधानसभा खुद मुख्यमंत्री चुन ले, ऐसा पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो चुका है। 1998 में जब उप्र के राज्यपाल रोमेश भंडारी ने भाजपा के कल्याण सिंह को हटाकर कांग्रेस के जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से विधानसभा में कल्याण सिंह और जगदम्बिका पाल में मुकाबला हुआ था, जिसमें कल्याण सिंह दोबारा मुख्यमंत्री बने थे।

दूसरा सुझाव यह भी था कि अगर विधानसभा भंग होती है, तो जो मध्यावधि चुनाव हो वह विधानसभा के बाकी बचे कार्यकाल के लिए हो, अब यह संशोधन संसद में दो तिहाई बहुमत के बिना तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें विधानसभाएं भी शामिल हैं, इसलिए आधी विधानसभाओं से अनुमोदन की जरूरत भी होगी। इतने बड़े बदलाव के लिए क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की सहमति जरूरी है। एक दर्जन के करीब विधानसभाओं में क्षेत्रीय दलों का बहुमत है। सभी राजनीतिक दलों में आम सहमति बनाने के लिए वाजपेयी ने उपराष्ट्रपति भैरोसिंह शेखावत को जिम्मेदारी दी थी। गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी राष्ट्रीय दलों कांग्रेस और वामपंथियों से बात कर रहे थे, और भैरोसिंह शेखावत ने विभिन्न क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू किया था। इसके लिए उन्होंने विभिन्न राज्यों का दौरा किया और क्षेत्रीय दलों से बातचीत को आगे बढ़ाया।

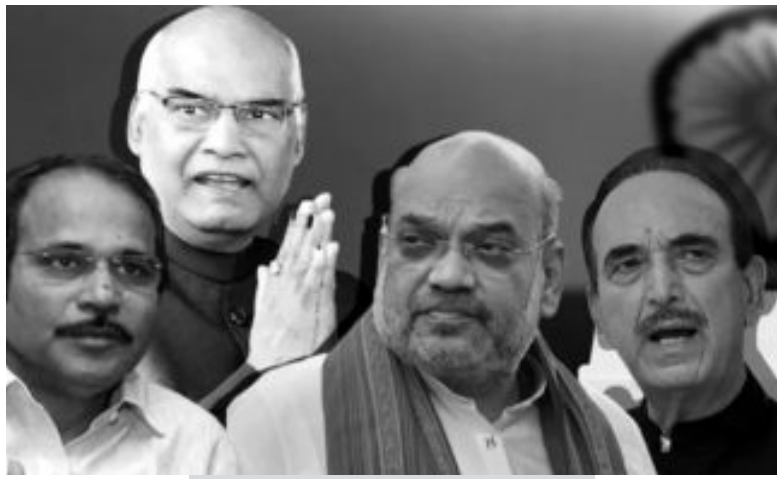

2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद पहल करके कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी को बुलाया था, वह एक साथ चुनावों के लिए सहमत थीं, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गए, जिसमें भाजपा हार गई। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बात ही नहीं की। यूपीए शासनकाल में तबके विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने 2010 में पहल करके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी से इस मुद्दे पर चर्चा की थी, और उन्होंने तब अपने ब्लॉग में लिखा था कि इन दोनों ने लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल फिक्स करने और एक साथ चुनाव करवाने पर सहमति प्रकट की है। लेकिन वह सहमति सिर्फ सैद्धांतिक थी। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही एक देश एक चुनाव की वकालत की। 2015 में संसद की स्टेंडिंग कमेटी ने भी एक साथ चुनावों की सिफारिश की थी, लेकिन इस रिपोर्ट में महत्वपूर्ण यह था कि कांग्रेस ने इसे अव्यवहारिक, तृणमूल कांग्रेस ने अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने असंभव और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा था कि इसमें कई तरह की व्यवहारिक समस्याए हैं। इसलिए यह बात वहीं पर खत्म हो गई थी।

2019 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मोदी ने एक बार फिर मंशा जाहिर की और इस संबंध में कमेटी बनाने का वायदा भी किया था। उसी साल मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने एक साथ चुनाव की वकालत करते हुए कहा था कि इसके लिए राजनीतिक दलों में आम सहमति और कई तरह के संविधान संशोधनों की जरूरत पड़ेगी। इस बीच नरेंद्र मोदी एक साथ चुनाव की चर्चा करते रहे हैं, उनकी ताजा वन नेशन वन इलेक्शन थ्योरी के पीछे सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाना नहीं, बल्कि नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव भी साथ करवाना है। अब जब लोकसभा चुनावों में सिर्फ आठ महीने बचे हैं, मोदी सरकार ने संसद के विशेष सत्र के ऐलान के साथ ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रहनुमाई में आठ सदस्यीय कमेटी बना दी है, तो वन नेशन वन इलेक्शन पर माहौल गर्म हो गया है।

● इन्द्र कुमार

एक राष्ट्र एक चुनाव के लाभ

एक राष्ट्र-एक चुनाव से सबसे बड़ा लाभ तो यह होगा कि राष्ट्र को पॉलिसी पैरालिसिस से बचाया जा सकता है, क्योंकि बार-बार जब चुनाव होते हैं तो चुनाव संहिता लागू होने के कारण नीतिगत निर्णय नहीं लिए जा सकते जिससे विकास के कार्य में बाधा पड़ती है। दूसरा, चुनाव आयोग को भी प्रतिवर्ष मतदाता सूची का नवीनीकरण करना पड़ता है जिससे जल्दबाजी में कई बार ठीक तरीके से नवीनीकरण नहीं होता और काम भी बढ़ता है। इससे भी छुटकारा मिलेगा। तीसरा, आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा कि जो राष्ट्र के ऊपर इतना बड़ा बोझ आता है वह कम होगा और हमें लगभग 60,000 करोड़ रुपए या 8 बिलियन डॉलर या इससे अधिक की बचत होगी। इसके साथ ही चुनाव के दौरान होने वाले आर्थिक भ्रष्टाचार, सुरक्षाबलों व शिक्षकों की नियुक्ति भी पांच साल में सिर्फ एक बार होगी बाकी समय वो अपना निर्धारित कार्य करेंगे। कुल मिलाकर एक राष्ट्र एक चुनाव राष्ट्र के परम हित में है और इसका जो कुछ भी मूल्य हो उसे अदा करके इसकी ओर बढ़ना चाहिए।

नौकरशाही से राजशाही

अफसरों का राजनीति से मोह

प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी दल अपनी तैयारियों को धार देने में लगे हैं। प्रदेश के नौकरशाहों की नजर भी विधानसभा चुनाव पर है। अलग-अलग पेशे से जुड़े अफसर इस बार चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। कोई भाजपा और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो कोई इन दोनों दलों को टक्कर देने के लिए तीसरे दल के साथ जा रहा है। प्रदेश में दो दर्जन सीटों पर प्रशासनिक सेवा से जुड़े अफसर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। 2023 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कई पूर्व नौकरशाह तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी लगभग दो-तीन महीने का समय बाकी है। ऐसे में कई और अफसरों की हसरतें निकलकर सामने आएंगी। इंतजार करना होगा चुनाव के नजदीक आने का। उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि कौनसा प्रशासनिक चेहरा कौन से दल से चुनाव मैदान में उतरेगा। लेकिन यह तय है कि अफसरों का राजनीति से बढ़ रहा मोह विधानसभा चुनाव में भी जरूर नजर आएगा।

राजनीति के फलक पर अपना सितारा चमकाने, नौकरशाहों की सियासी गलियारों में एंट्री हो रही है। पूर्व आईएएस और पूर्व जज भी सियासत का दामन थाम रहे हैं। चुनावी साल में नौकरशाहों का आना, क्या कुछ कमाल दिखा पाएगा। छत्तीसगढ़ के चुनावी समर में इस बार ब्यूरोक्रेट्स भी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहें हैं। किसी ने जज की नौकरी से इस्तीफा दिया, तो कोई जाने-माने आईएएस अधिकारी रहे हैं। कांकेर के रहने वाले नीलकंठ टेकाम ने चुनाव के लिए आईएएस की नौकरी छोड़ दी और केशकाल में भाजपा की सदस्यता ली। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और पूर्व सीएम रमन सिंह की मौजूदगी में टेकाम भाजपा में शामिल हुए।

ये पहला मौका नहीं है जब किसी अधिकारी ने सेवा छोड़कर राजनीति का दामन थामा है। बीते दिनों कांकेर के जज रहे कृष्णकांत भारद्वाज भी कांग्रेस की सदस्यता ले चुके हैं। इस फेहरिस्त में गणेश शंकर मिश्रा और ओपी चौधरी जैसे नेताओं का नाम भी शामिल है। दोनों तरफ नौकरशाहों की आमद से राजनीति गुलजार है। उम्मीद है कि दोनों पार्टियां पूर्व नौकरशाहों को मैदान में उतार सकती हैं। हालांकि इससे पहले करीब दर्जनभर अधिकारी सियासी पिच पर अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि नौकरशाहों का सियासी ग्राफ बेहद कमजोर रहा। सियासत में सबसे सफल नाम पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व आईएएस अजीत जोगी का लिया जाता है। अब देखना होगा कि सियासी फलक पर इस दर्जे तक कोई पहुंच पाता भी है या नहीं। छत्तीसगढ़ की सेवानिवृत्त आईएएस जिनेविवा किंडो ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी है। प्रमोटी आईएएस किंडो ने रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में कांग्रेस में प्रवेश किया। चर्चा है कि किंडो सरगुजा संभाग से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में यह कोई पहला मौका नहीं है जब कोई पूर्व नौकरशाह राजनीति में प्रवेश कर रहा है। इससे पहले करीब दर्जनभर अफसर सियासी पिज पर अपना भाग्य आजमा चुके हैं या आजमा रहे हैं। हालांकि चुनावी राजनीति में इनकी सफलता का ग्राफ बेहद कमजोर है। पीआर खुंटे और शिशुपाल सोरी जैसे चंद नाम हैं जो चुनाव जीते हैं। आज के दौर के आईएएस अफसरों में सबसे बड़ा नाम ओपी चौधरी का है। 2005 बैच के आईएएस रहे चौधरी ने 2013 के चुनाव के पहले नौकरी छोड़कर भाजपा के साथ सियासी पारी की शुरुआत की। पार्टी ने उन्हें कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ खरसिया सीट से मैदान में उतारा और चौधरी हार गए।

सियासत में सबसे सफल पूर्व नौकरशाह में अजीत जोगी का नाम सबसे ऊपर आता है। जोगी पहले आईपीएस और फिर आईएएस रहे। उन्होंने भी कलेक्टरी छोड़कर राजनीति में प्रवेश किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में जोगी बड़ा नाम बन गए थे। जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे। राज्यसभा और लोकसभा सदस्य भी रहे हैं। 2018 के चुनाव में पूर्व आईएएस शिशुपाल सोरी ने कांग्रेस के टिकट पर भाग्य आजमाया था, आज वे विधायक हैं। सोरी और चौधरी के साथ ही अभी कई और पूर्व आईएएस और आईपीएस चुनावी रण में भाग्य आजमाने की तैयारी में हैं। इनमें एसीएस के पद से सेवानिवृत्त और अब कांग्रेस नेता सरजियस मिंज भी शामिल हैं। मिंज अभी राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में आए पूर्व आईएएस आरपी त्यागी तो दलबदल भी कर चुके हैं। पहले वे कांग्रेस में थे अब भाजपा में पहुंच गए हैं। वहीं 2023 में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे पूर्व नौकरशाहों में गणेश शंकर मिश्रा और नीलकंठ टेकाम का नाम भी शामिल हैं। दोनों भाजपा से टिकट के दावेदार हैं।

2013 में कांग्रेस की टिकट पर गुंडरदेही विधानसभा से चुने गए आरके राय ने डीएसपी पद से नौकरी छोड़कर राजनीति में प्रवेश किया था। हालांकि 2018 में वे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की टिकट पर चुनाव लड़े और हार गए। आहिवारा से विधायक रहे सांवलाराम डहरे वाणिज्यककर अधिकारी थे। इसी तरह पुलिस से सेवानिवृत्त हुए रामलाल चौहान भाजपा की टिकट पर सरायपाली से विधायक चुने गए थे। सेवानिवृत्त पुलिस अफसर श्यामलाल कंवर भी कांग्रेस की टिकट पर रामपुर सीट से विधायक चुने गए थे। 2018 के चुनाव में जकांछ ने सेवानिवृत्त आईएएस एमएस पैकरा और सेवानिवृत्त एसडीओ अर्जुन हिरवानी को प्रत्याशी बनाया था। इसी तरह रिटायर्ड डीएसपी विभोर सिंह को कांग्रेस ने कोटा से टिकट दिया था। पूर्व नौकरशाहों के लिए कांग्रेस और भाजपा ही नहीं सर्व आदिवासी समाज भी एक विकल्प है। सेवानिवृत्त आईपीएस अकबर राम कोर्राम ने सर्व आदिवासी समाज की तरफ से भानुप्रतापपुर सीट पर हुए उपचुनाव में अपना भाग्य आजमाया था। कोर्राम तीसरे स्थान पर रहे। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंड़िया दिवंगत रविंद्र भेंड़िया की पत्नी हैं। भेंड़िया आईपीएस अफसर थे। उनके सेवा में रहते ही उनकी पत्नी ने चुनावी राजनीति में कदम रख दिया था।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

मराठा बनाम ओबीसी की टकराहट

महाराष्ट्र के जालना जिले में मराठा आरक्षण को लेकर चला आंदोलन काफी हिंसक नजर आया। इसमें 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने दो बसों को आग के हवाले कर दिया और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। इस आंदोलन की आग में घी डालने के लिए मराठा नेता शरद पवार जालना पहुंचे। प्रदेश के मराठा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आंदोलनकारियों से शांति बनाने की अपील तो की है, लेकिन मामला ठंडा होता नजर नहीं आ रहा है। असल में मराठा समुदाय के लोग अपनी दुर्दशा के लिए महाराष्ट्र की सभी सरकारों को जिम्मेदार मान रहे हैं। कभी महाराष्ट्र में राजनीतिक और आर्थिक रसूख रखने वाला यह समुदाय अपने घटते प्रभुत्व से विचलित और चिंतित है। महाराष्ट्र में प्रभुत्वशाली माने जाने वाले मराठाओं का कहना है कि लंबे समय तक मुठ्ठीभर परिवारों की कामयाबी को समूचे समुदाय की कामयाबी के तौर पर पेश किया जाता रहा है।

2013 में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता रहे नारायण राणे की अध्यक्षता वाली एक समिति ने मराठाओं की समस्याओं को लेकर एक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि राज्य की आबादी में मराठा 34 फीसदी हैं लेकिन सरकारी कर्मचारियों में उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 14 फीसदी है। उच्च शिक्षा और तकनीकी संस्थानों में इनका दाखिला सिर्फ 12 फीसदी है, जबकि महाराष्ट्र में आत्महत्या करने वाले किसानों में 36 फीसदी इसी मराठा समुदाय से हैं। नारायण राणे के नेतृत्व में बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि बहुसंख्यक मराठा या तो किसान हैं या फिर रोजगार गारंटी योजना के तहत काम करने वाले मजदूर हैं, उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है।

राणे समिति ने सिफारिश की थी कि मराठाओं को शिक्षा और सरकारी नौकरी में 16 फीसदी आरक्षण दिया जाए। जुलाई 2014 में कांग्रेस एनसीपी की तत्कालीन सरकार ने इस बारे में एक आरक्षण नीति लागू भी की थी लेकिन मुंबई हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में 1990 से 2008 के बीच आई तीन आयोगों की रिपोर्ट को आधार बनाया था जिसमें कहा गया था कि मराठाओं को पिछड़ा नहीं माना जा सकता है। इसके बाद बनी देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने मराठा आंदोलन की आंच से बचने के लिए एक विधेयक पारित कर दिया था। इसके तहत राज्य की सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में मराठाओं को 16 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मराठा समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इसे लागू करने से 50 फीसदी की सीमा का उल्लंघन होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मराठा समुदाय से संबंध रखने वाले एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री होते हुए भी सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। महाराष्ट्र में फिलहाल अनुसूचित जाति को 15 फीसदी, अनुसूचित जनजाति को 7.5 फीसदी, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी और अन्य को 2.5 फीसदी आरक्षण मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मराठा आरक्षण मामला सुलगने की तैयारी में था लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने राजनीतिक कौशल का इस्तेमाल कर उस आंदोलन को ठंडा कर दिया था। लेकिन अब एक बार फिर मराठा आंदोलन की चिंगारी भड़क गई है। लेकिन सरकार के सामने मुश्किल यह है कि अगर मराठा समाज को अलग से आरक्षण दिया जाता है तो आरक्षण की अधिकतम सीमा पार हो जाएगी और अगर उन्हें पिछड़ा वर्ग में शामिल कर आरक्षण दिया गया तो ओबीसी की नाराजगी का खतरा है।

भाजपा तथा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और पश्चिम महाराष्ट्र के दिग्गज मराठा नेता एनसीपी के अजित पवार के लिए समस्या यह है कि अगर मराठा आरक्षण की मांग स्वीकार नहीं की जाती है तो मराठा वोट बैंक शरद पवार और उद्धव ठाकरे की ओर खिसकने का जोखिम है और अगर मराठा आंदोलन की मांग मानकर मराठा को ओबीसी में शामिल कर लिया जाता है तो महाराष्ट्र में ओबीसी वोट से हाथ धोना पड़ सकता है और ओबीसी आंदोलन भी शुरू हो सकता है। महाराष्ट्र में मराठा और ओबीसी में हमेशा छत्तीस का आंकड़ा रहा है। पहले भी जब मराठा को ओबीसी में शामिल करने की बात होती रही है तब हमेशा इसका विरोध ही हुआ है। यहां तक कि भाजपा के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे और एनसीपी के नेता छगन भुजबल जो दोनों ही ओबीसी की राजनीति करते रहे हैं, वो दोनों भी इस मामले में अपनी-अपनी पार्टियों की नीति से परे जाते हुए एक साथ आ गए थे। ऐसे में तमाम विरोधाभासों से घिरी वर्तमान सरकार अपने ही ओबीसी नेताओं की नाराजगी लेने की स्थिति में नहीं है। महाराष्ट्र सरकार के सामने दूसरी समस्या यह भी है कि यदि वह मराठा आरक्षण को मान भी लेती है तो राज्य में कई दूसरी जातियां भी आरक्षण हासिल करने का दबाव शिंदे सरकार पर बना सकती है। अभी तो सरकार यह कहकर खुद को सेफ जोन में रखे हुए है कि संविधान की ओर से तय आरक्षण की अधिकतम सीमा से छेड़छाड़ उसके हाथ में नहीं। चुनाव के दहलीज पर खड़ी खिचड़ी सरकार किसी भी तरह का जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है।

● **बिन्दु माथुर**

महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा

महाराष्ट्र में उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, कोंकण, मराठवाड़ा मराठा प्रभुत्व वाले क्षेत्र हैं और यही वह क्षेत्र हैं जहां कुछ हिस्सों में भाजपा मजबूत है तो कुछ में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना ताकतवर है। राजनीतिक ताकत के रूप में देखा जाए तो राज्य की आबादी में 34 प्रतिशत हिस्सा रखने वाले मराठा समुदाय ने अब तक 11 मुख्यमंत्री अपने समुदाय से दिए हैं। 51 प्रतिशत विधानसभा सीटों यानी कुल 288 में से 148 सीटों में उनके 50 फीसदी से ज्यादा वोट हैं। कुल 48 लोकसभा सीटों में से 25 सीटों पर 50 फीसदी से ज्यादा मतदाता मराठा हैं। मराठा समुदाय से इस समय 23 सांसद हैं और महाराष्ट्र की विधानसभा और विधान परिषद की कुल 366 सीटें में से 210 विधायक मराठा समुदाय से आते हैं। राजनीतिक रूप से पूरी तरह से मजबूत होने के बाद भी यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य में खुदकुशी करने वाले ज्यादातर किसान मराठा ही हैं। 67 प्रतिशत मराठा किसान भारी कर्ज में दबे हैं। प्रदेश में जमीन बेचने वाले किसानों में 50 फीसदी मराठा हैं और राज्य की नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 14 प्रतिशत है।

खेलों से राजनीति के माहिर खिलाड़ी

क्रिकेट हो या निशानेबाजी, मुक्केबाज हो या धावक, सियासी पिच पर कई खिलाड़ियों ने अपनी चमक बिखेरी है। राजस्थान की राजनीति में भी कई ऐसे चेहरे हैं, जिनके सिर जनता ने जीत का सेहरा बांधा और वे सांसद-विधायक-मंत्री बने। अगले विधानसभा व लोकसभा चुनावों में भी कुछ खिलाड़ी चुनावी मैदान में कूद सकते हैं। बहुत से खिलाड़ियों पर कांग्रेस-भाजपा दोनों पार्टियों की नजरें टिकी हुई हैं।

निशानेबाजी से धाक जमाने वाले राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी खेलों से राजनीति में उतरे। वर्ष 2004 में एथेंस ओलिंपिक में भारतीय सेना के मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राइफल शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता था। राजस्थान से लेकर दिल्ली और एथेंस तक राठौड़ बहुत प्रसिद्ध हो गए। तब राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थीं। राजे ने राठौड़ के स्वागत की तैयारियां कीं और अपने काबिना मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ को दिल्ली भेजा। उसके बाद से राजनीति में उनके कदम बढ़ते चले गए। वर्ष 2014 में भाजपा ने उन्हें जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। उस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज राजनेता तत्कालीन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री सीपी जोशी को हराया। राठौड़ को वर्ष 2014 से 2019 के बीच केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद भी मिला। वे वर्ष 2019 में लगातार दूसरी बार भी जयपुर ग्रामीण से सांसद बने। वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं।

हरियाणा के हिसार जिले में एक ग्रामीण परिवार की बेटी हैं। उन्होंने दो बार भारत की तरफ से डिस्कस थ्रो में ओलिंपिक में हिस्सा भी लिया। उन्हें अर्जुन अवॉर्ड भी मिल चुका है। कई राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में कृष्णा ने मेडल जीते। वर्तमान में कृष्णा पूनिया सादुलपुर से विधायक होने के साथ-साथ राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की चेयरमैन हैं। उन्हें सरकार ने राज्यमंत्री का दर्जा दिया हुआ है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर वर्ष 2019 में हुए चुनावों में भाजपा ने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट दिया था और कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थीं कृष्णा पूनिया। उस वक्त चुनाव को दो विश्व स्तरीय खिलाड़ियों के बीच राजनीतिक भिड़ंत के रूप में देखा गया। दोनों के बीच अच्छा मुकाबला हुआ। अंतत: राठौड़ विजयी रहे।

राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना ने भी खेलों से ही सियासी एंट्री पाई। चांदना एक नहीं दो-दो स्पोर्ट्स के माहिर खिलाड़ी हैं। इसके अलावा भी घुड़सवारी, तैराकी और वॉलीबॉल में भी स्टेट लेवल के खिलाड़ी हैं। खेलों से राजनीति में आए चांदना लगातार दूसरी बार हिंडोली (बूंदी) से विधायक हैं और वर्तमान कांग्रेस सरकार में वे खेल राज्य मंत्री भी हैं। हाल ही में राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने जो ग्रामीण और शहरी ओलिंपिक का आयोजन करवाया था, उसमें चांदना ने खास भूमिका निभाई है। दोनों प्रतियोगिता में 30-32 लाख प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है।

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे मोहम्मद अजहरूद्दीन ने कांग्रेस के टिकट पर वर्ष 2014 में टोंक-सवाईमाधोपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, हालांकि वे भाजपा के सुखबीर सिंह जौनापुरिया के सामने चुनाव हार गए थे। उससे पहले वे वर्ष 2009 में मुरादाबाद (उप्र) से कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने थे। वर्ष 1984 से 2000 तक भारतीय टीम के खिलाड़ी रहे अजहर मूलत: हैदराबाद (तेलंगाना) के रहने वाले थे, लेकिन वहां से करीब 1500 किलोमीटर दूर उत्तर भारत के शहर से सांसद बन गए थे, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान होने से पूरे देश में उनका नाम था। यही कारण था कि उन्हें राजस्थान की टोंक-सवाईमाधोपुर सीट पर भेजा था।

वर्तमान में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन वैभव गहलोत भी खेलों और राजनीति में चमके हुए हैं। वैभव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र हैं। जोधपुर से कांग्रेस के टिकट पर 2019 में सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि वे चुनाव हार गए थे। हाल ही में वैभव ने क्रिकेट जगत में राजस्थान की पहली प्रीमियर लीग आरपीएल को लॉन्च किया है। राजनीति के क्षेत्र में इसे जोधपुर से वैभव के फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। बीसीसीआई कोच व राजस्थान क्रिकेट रणजी टीम के पूर्व तेज गेंदबाज शैलेंद्र गहलोत का कहना है कि खिलाड़ियों को हमारे देश में बहुत सम्मान दिया जाता है। उन्हें युवा वर्ग मेहनती, संघर्षशील, देशप्रेमी और ईमानदार व्यक्ति के रूप में देखता है। ऐसे में उन्हें जनता का सम्मान मिलता ही है। राजनीति में जाने पर खिलाड़ी ज्यादा बेहतर काम कर पाते हैं। खेलों के लिए ही नहीं बल्कि वे संपूर्ण युवावर्ग को प्रेरणा देने वाले होते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि राजनीतिक दलों को हमेशा ऐसे लोगों की जरूरत होती है, जिनमें भीड़ जुटाने की क्षमता हो। खिलाड़ी उनकी इस जरूरत को पूरा करते हैं। साथ ही किसी क्षेत्र विशेष में संबंधित खिलाड़ी के जाति-समुदाय की अच्छी संख्या हो तो चुनाव जीतने के अवसर बढ़ जाते हैं। ऐसे में राजनीतिक दल आम तौर पर खिलाड़ियों का दिल खोलकर स्वागत करते हैं।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

खिलाड़ियों की लोकप्रियता भुनाने में जुटे नेता

खिलाड़ियों की लोक्रप्रियता को भी चुनावी सभाओं में खूब भुनाया जाता है। विधानसभा चुनाव राज्य में करीब तीन महीने दूर ही रह गए हैं। ऐसे में प्रदेशभर में बहुत से ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने चुनाव लड़ने की तैयारी स्पोर्ट्स पर्सनेलिटी को बुलाकर की है। एक महीने पहले सांगानेर (जयपुर) के विधायक अशोक लाहोटी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में क्रिकेट प्रतियोगिता करवाई और मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को बुलाया था। इसी तरह एक प्रतियोगिता दो महीने पहले नवलगढ़ के विधायक राजकुमार शर्मा ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में करवाई और क्रिकेटर दीपक चाहर को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। चाहर राजस्थान से क्रिकेट खेलते रहे हैं और भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य भी रहे हैं। दोनों विधायकों ने इन क्रिकेट प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपने क्षेत्र का राजनीतिक तापमान भी माप लिया है।

अपात्रों को मिला शौचालयों का पैसा

सन् 2014 में न खाऊंगा, न खाने दूंगा के वादे के साथ नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता संभाली, लेकिन उनकी सरकार भी दूसरी सरकारों की तरह कई योजनाओं में भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम साबित हो रही है। दरअसल हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार किसी एक व्यक्ति के संकल्प से नहीं रुकेगा। इसके लिए ऊपर से नीचे तक सबको ईमानदार होना पड़ेगा। पश्चिमी उप्र में भी कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारियों के चलते कई तरह के घोटाले सामने आते रहते हैं। समाजसेवी, आरटीआई एक्टिविस्ट और पेशे से किसान सुमित मलिक ने कड़ी मेहनत करके स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय योजना में इसी तरह का भ्रष्टाचार उजागर किया है।

दरअसल, स्वच्छ भारत अभियान केंद्र सरकार का वो राष्ट्रीय अभियान है, जिसका मकसद देश को हर तरह से साफ-सुथरा बनाना है। 2 अक्टूबर, 2014 को खुद प्रधानमंत्री ने झाड़ू लगाकर दिल्ली से इस अभियान की शुरुआत की थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आजादी का सपना तो पूरे देश ने मिलकर पूरा किया, लेकिन उनका स्वच्छ भारत का सपना पूरा नहीं हो सका है, जिसकी शुरुआत पूर्व सरकारों से हटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। प्रधानमत्री मोदी के इसी स्वच्छ भारत अभियान की एक योजना है- खुले में शौच मुक्त भारत; जिसके तहत केंद्र की मोदी सरकार ने घर-घर शौचालय होने का संकल्प लिया। इस योजना के तहत जिस व्यक्ति के यहां शौचालय बनना था, उसके पात्र होने पर, उसके खाते में केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से 12,000 रुपए भेजे गए।

पूरे देश के साथ-साथ पश्चिमी उप्र के मुजफ्फरनगर जिले में भी इस योजना के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाखों लोगों को शौचालय बनाने के लिए पैसा दिया गया। घरों में शौचालय बनाने के लिए व्यक्ति की पात्रता गरीबी रेखा के नीचे आने वाले व्यक्तियों की थी, और उन्हें ही शौचालय के लिए 12,000 रुपए की धनराशि मिलनी थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस योजना के तहत मुजफ्फरनगर जिले के ग्रामीण इलाकों में 53,183 शौचालय बनाए गए। मुजफ्फरनगर में कुल 498 गांव हैं, जो कि नौ ब्लॉकों के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सुमित मलिक के मुताबिक, उन्होंने गांव-गांव जाकर पहले शौचालयों के बनने और अपात्रों को पैसा मिलने की जानकारी इकट्ठी की और फिर आरटीआई के जरिए भ्रष्टाचार को उजागर किया। सुमित मलिक ने आरटीआई और खुद के सर्वे में पाया कि फर्जी तरीके से हजारों अपात्र लोगों को शौचालय का पैसा मुहैया कराया गया है। सुमित मलिक के मुताबिक, जिला राज पंचायत अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी तरीके से कई कर्मचारियों के ही परिवार वालों के बैंक खातों में ही पहली किस्त के 6,000 रुपए भेजे गए।

2,05,10,000 रुपए की रिकवरी नहीं हो पाई

हैरत की बात है कि प्रदेश सरकार के आदेश के बावजूद करीब पांच साल से अधिक समय में अगस्त, 2023 तक भी 2,05,10,000 रुपए की रिकवरी नहीं हो पाई है, जिससे जिला प्रशासन, खासतौर पर जिला राज पंचायत अधिकारी की लापरवाही साफ झलकती है। गलत लोगों से भी इस सरकारी धन की रिकवरी न कर पाने से अफसरों के इस भ्रष्टाचार में लिप्त होने की आशंका होती है। सुमित के मुताबिक, वह कई बार लगातार इस सरकारी धन की रिकवरी के संदर्भ में बार-बार संबंधित अफसरों को प्रार्थना-पत्र देते हैं; लेकिन बकाया धन की रिकवरी अपात्र लोगों से नहीं हो पा रही है। ग्रामीण इलाकों में बड़े-बड़े घरों में फर्जी तरीके से एक ही घर दिखाकर 6 शौचालय तक दिए गए। इतना ही नहीं, जिला राज पंचायत अधिकारी के कुछ कर्मचारियों के खाते से भी 3,00,000 रुपए की धनराशि बरामद की गई।

सुमित मलिक बताते हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी से भी इस भ्रष्टाचार की शिकायत 25 जून, 2018 में की थी। मुख्यमंत्री योगी के संज्ञान में शौचालय भ्रष्टाचार का मामला आते ही, इसकी जांच के लिए उप्र शासन ने एक जांच दल का गठन करके जांच के आदेश दिए। जांच दल ने पाया कि सिर्फ मुजफ्फरनगर के ग्रामीण इलाकों में 2,130 अपात्र लोगों को शौचालय का पैसा मिला। जांच के बाद इन अपात्र लोगों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की गई और मुजफ्फरनगर के कई ब्लॉकों में अधिकारियों ने रिकवरी अभियान चलाया गया। इस रिकवरी अभियान के तहत अभी तक सरकार को तकरीबन 2,30,000 रुपए वापस मिल चुके हैं, जबकि अभी भी तकरीबन 1,82,10,000 रुपए की रिकवरी बाकी है। रिकवरी राशि तकरीबन 2,05,10,000 रुपए की है, जो अभी तक अफसरों द्वारा अपात्र लोगों से वापस नहीं ली जा सकी है। इस रिकवरी के लिए प्रदेश सरकार का आदेश तो है ही, सुमित मलिक भी अफसरों को प्रार्थना-पत्र दे चुके हैं। सुमित ने सन् 2016 से ही इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए संबंधित अफसरों को प्रार्थना-पत्र लिखा, लेकिन इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), जिसे दुनिया का सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम कहा गया है; के तहत जमीनी स्तर पर जन-आंदोलन पैदा करके इस असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा किया गया। इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण स्वच्छता कवरेज जो सन् 2014 में 39 फीसदी था, सन् 2019 में बढ़कर 100 फीसदी हो गया और 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 10.28 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए। स्वच्छ भारत का उद्देश्य व्यक्ति, क्लस्टर और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से खुले में शौच की समस्या को कम करना या समाप्त करना है। यहां बताना जरूरी है कि केंद्र की मोदी सरकार के पहले सन् 1999 से सन् 2012 तक केंद्र की सरकारों ने हिंदुस्तान को साफ-सुथरा बनाने के लिए निर्मल भारत अभियान चलाया था, जिसका मकसद भी पूर्ण स्वच्छता अभियान था। लेकिन उस योजना के तहत भी हिंदुस्तान कितना साफ-सुथरा हो सका, आंकलन करने की जरूरत है। आगामी 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को मजबूत बनाने के लिए अभी से अपने तीसरे कार्यकाल के वादे कर रहे हैं। उनका कहना है कि वह तीसरे कार्यकाल में देश के हर सपने को पूरा करेंगे। अब यह निर्णय जनता पर है कि वह प्रधानमंत्री मोदी के इस वादे को कितनी गंभीरता से लेती है।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण

बिहार के मोतिहारी में नागपंचमी के मौके पर समुदाय विशेष से जुड़े लोगों ने एक शोभायात्रा पर पथराव कर दिया। इस पत्थरबाजी में न केवल महावीरी शोभायात्रा में शामिल भक्त घायल हुए बल्कि कुछ पुलिसवालों को भी चोट लगी। सोशल मीडिया पर बाद में जो वीडियो सामने आए इसे देखकर लगता है कि पत्थरबाजों को न सामाजिक सद्भाव की चिंता थी और न पुलिस प्रशासन का डर। बिहार की स्थिति को देखें तो जनसांख्यिकी में आ रहे निरंतर बदलाव सिर्फ अपराध को ही नहीं, सांप्रदायिक वारदातों को भी जन्म दे रहे हैं और बिहार के बागों से मानों धीरे-धीरे बहार लापता होने लगी है। कहने को यहां से जंगलराज का दौर बीत चुका है, सुशासन आ गया है, लेकिन मोतिहारी जैसी एकतरफा पत्थरबाजी को देखकर विपक्षी राजनेताओं से लेकर आम आदमी तक से पूछें तो शायद वो यह बात बहुत विश्वास से नहीं कह पाएगा।

आम आदमी को सवाल करने पर सरकारी डंडा दिखा देने वाली बिहार पुलिस सुनियोजित अपराधों को नियंत्रित करने में अपनी हनक खो देती है। हाल ही में एक बयान में बिहार के डीजीपी ने पुलिस के अच्छे काम के बारे में बड़े-बड़े दावे जरूर किए लेकिन एक नजर हाल की घटनाओं पर डालते ही ऐसे दावों की पोल खुल जाती है। सीधे आतंकवाद की बात करें तो जनवरी से जुलाई 2023 में ही अलग-अलग अखबारों-समाचार चैनल ये बता रहे थे कि एनआईए ने गुजरात, उप्र के अलावा बिहार के पटना और दरभंगा में गजवा-ए-हिंद मॉड्यूल को ध्वस्त करने के लिए कार्रवाई की है। बम बनाने की फैक्ट्री या बम बनाने के दौरान हुए धमाकों की बात करें, तो नवादा, बिहारशरीफ, पटना, भागलपुर समेत दर्जनभर जिलों से ऐसी खबरें इसी वर्ष आ चुकी हैं। बांका और सिवान से आने वाली खबरों के अलावा, कई खबरें तो ऐसी हैं जिनमें बम मस्जिद में छुपाकर रखे गए थे और उनके फटने से कभी ईमाम तो कभी आम लोग हताहत हुए। राजद के विधायक मुहम्मद नेहालुद्दीन तो सासाराम में हुए विस्फोट पर ये तक कह चुके हैं कि मुस्लिम आत्मरक्षा में बम बना रहे थे।

बिहार में हाल ही में जो दंगे और शोभायात्राओं पर पथराव की घटनाएं सुनाई दे रही हैं, उनकी आहट पहले से सुनाई दे रही थीं। ये और बात है कि जब सवाल उठाए गए तो सवालों को सांप्रदायिक घोषित करके पूछने वालों को ही पॉलिटिकली करेक्ट लोगों ने चुप करवा दिया था। एक समुदाय विशेष के दबदबे वाले इलाकों में सरकारी स्कूल जब नियत दिन के बदले जुम्मे की छुट्टी करने लगे, उस समय भी कई नेताओं और आम लोगों ने पूछा था कि किस भीड़तंत्र के दबाव में नियमों को ताक पर रखा जा रहा है? सीमांचल के क्षेत्रों, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार आदि क्षेत्रों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण हो रहे जनसांख्यिकीय बदलाव चिंता का विषय है। पूरे भारत में जहां मुस्लिम आबादी 4 प्रतिशत की दर से बढ़ी, वहीं सीमांचल में ये आंकड़ा सीधा चार गुना करीब 16 प्रतिशत का था। इस विचित्र दर से बढ़ रही आबादी की ओर से सुशासन ने आंखे मूंद ली थीं, क्योंकि ये समुदाय विशेष सत्ताधारी दल राजद का वोट बैंक माना जाता है। जिस माय समीकरण से राजद चुनावी जीत हासिल करती है, उसमें एम मुस्लिम और वाय से यादव मिलाकर एमवाय समीकरण बनता है।

इन समीकरणों के बदलने का नतीजा जो हुआ, बिहार अब वही झेल रहा है। हिंदुओं की शोभायात्राओं पर पत्थरबाजी अब इतनी आम हो गई है कि स्थानीय समाचार पत्रों के अलावा कोई उसे मुख्य समाचार भी नहीं मानता। वो राष्ट्रीय चैनलों की प्राइम टाइम बहसों का हिस्सा नहीं बनती। लगातार ऐसी हिंसा के कारण जारी हिंदुओं के पलायन को मालदा और कैराना की ही तरह भुला दिया जाना, या फिर सीधे असत्य घोषित कर दिए जाने में क्या हर्ज है? वैसे भी नाम तो अखलाक का याद रहेगा, चंदन गुप्ता नाम का कोई युवक तिरंगा यात्रा के दौरान एक समुदाय विशेष की भीड़ का शिकार बन भी जाए, तो उसके परिवार को मुआवजा तक नहीं मिलता।

दरभंगा इत्यादि जगहों पर समुदाय विशेष की भीड़ ने रामनवमीं इत्यादि त्योहारों के दौरान जो किया, वो सिर्फ एक समुदाय विशेष ने नहीं किया है। जिन्हें याद होगा, वो बता देंगे कि बिहार में चुनावों के दौरान ही दुर्गा पूजा थी। दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान ही अनुराग कुमार पोद्दार को पुलिस की गोलियों का निशाना बना दिया गया था। उस वक्त मुंगेर में जिस एसपी की तैनाती थी, उसके पिता सत्ताधारी दल के उस वक्त एक प्रमुख नेता थे। बाद में आरसीपी सिंह का जदयू और नीतीश कुमार से अलगाव हो गया। जाहिर है कि जब हमलावरों के गिरोह रोज तैयारियां कर रहे हों, सत्ता स्वयं आततायी के अपराधों के प्रति आंख बंद करने लगी हो और एक पक्ष पहले से ही पलायन कर रहा हो, उस दौर में दंगे होंगे ही। मोतिहारी जैसी ही घटना तो करीब-करीब हर शहर में हो चुकी है। पुलिस-प्रशासन की पोल 2021 के एनसीआरबी आंकड़ों से भी खुल जाती है। जमीन विवाद संबंधित 3,336 मामले बिहार में दर्ज हुए जो देश में सर्वाधिक हैं। जमीन से जुड़े विवादों में 2021 में बिहार में 815 हत्याएं हो चुकी हैं। पुलिस और सरकारी अधिकारियों पर डेढ़ सौ हमलों के साथ ही बिहार टॉप पर है। हत्या के प्रयासों में बिहार 8393 मामलों के साथ पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर है।

● **विनोद बक्सरी**

दंगा फैलाने के 6,298 मामले

दंगों की गिनती देखेंगे तो सीधे-सीधे धार्मिक-सांप्रदायिक दंगों के 51 मामलों के अलावा दंगा फैलाने के 6,298 मामले बिहार में सामने आए। महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों में बिहार 3,400 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर है। बलात्कार के 786 मामले आए और दहेज के मामलों में भी बिहार 3,367 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। बिहार में 2021 में दहेज के लिए एक हजार महिलाओं को मार दिया गया। दलितों पर अत्याचार के मामले में बिहार चौथे स्थान पर है, इसके 5,842 मामले दर्ज हुए। शादी या फिरौती के लिए स्त्रियों के अपहरण के 6,589 मामले दर्ज हुए हैं। एटीएम फर्जीवाड़े में भी बिहार 557 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है। बिहार में अपराध के आंकड़ों को देखते हुए अगर कोई ये कहता है कि बिहार की शासन व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, तो क्या गलत कहता है? चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में अगर बिहार को अपने पूर्व के जंगलराज वाली छवि से मुक्ति पाना है तो उसे विकास और शासन को ही मुद्दा बनाकर वोट करना होगा। हालांकि जातिवाद में गहरे धंसे बिहार से यह उम्मीद करना अपने आप में थोड़ा कठिन है, लेकिन आज नहीं तो कल इस दिशा में हर नागरिक को सोचना ही होगा।

ANU SALES
CORPORATION
When time matters,
Real 200 t/h throughput
Even with double reagent reactions, the analyzer keeps its speed. Up to 4 volumes can be handled in every cycle.
Dispensation
Aspiration
We Deal in Pathology
& Medical Equipment
BA200
BioSystems
The Highest Flexibility
Address : M-179, Gautam Nagar,
Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
9329556524, 9329556530
Email : ascbhopal@gmail.com

तबाही की ओर पाकिस्तान

कुछ समय पहले तक पाकिस्तान में काफी कुछ ठीक दिख रहा था, लेकिन अब सब कुछ गड़बड़ है। वर्ष 2017 में पाकिस्तान की जीडीपी में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई थी। अंतरराष्ट्रीय पत्रिका द इकोनमिस्ट ने 2017 में पाकिस्तान को सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला मुस्लिम देश बताया था। उस समय प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ के अमेरिका, चीन और इस्लामिक देशों विशेषकर संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के शाही परिवारों के साथ बढ़िया रिश्ते थे। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपैक का काम पूरी तेजी पर था। पाकिस्तान के भविष्य से जुड़े संकेतक सही दिशा में थे। फिर 2022 तक आते-आते सब कुछ बदरंग दिखने लगा।

गुलाम कश्मीर सहित पूरे पाकिस्तान में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। गुलाम कश्मीर में भारत के साथ विलय की मांग करते प्रदर्शनकारियों के वीडियो वायरल होने लगे। पाकिस्तान में महंगाई अप्रत्याशित रूप से बढ़कर करीब 40 प्रतिशत तक पहुंच गई। बिजली के दामों में बेतहाशा वृद्धि से परेशान लोगों ने पिछले दिनों बंद का ऐलान किया, जो पूरे देश में प्रभावी दिखा। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के आगे कराहते हुए 300 रुपए के स्तर को भी पार कर गया। वहां आटे जैसी वस्तुओं की किल्लत हो गई। याद रहे कि यह वही इलाका है, जिसे विभाजन पूर्व भारत का अन्नदाता कहा जाता था। वहां लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। महंगाई के सामने वहां की कार्यवाहक सरकार असहाय और निरुपाय दिख रही है। पाकिस्तान में स्थितियां इमरान खान के सत्ता संभालने के बाद से बिगड़नी शुरू हुईं। क्रिकेटर से नेता बने इमरान के पास कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था। उनका अड़ियल और अहंकारी रवैया जगजाहिर रहा है। इमरान ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए कट्टरपंथियों के साथ गलबहियां करने से भी परहेज नहीं किया। उन्हें कोई अंदाजा ही नहीं था कि पाकिस्तान की आर्थिकी किस प्रकार चलती है। साथ ही वह देश के संस्थानों और उनके संचालन से भी अनभिज्ञ थे। यह आर्थिक नीति में अनुभवहीनता का ही परिणाम था कि उनकी सरकार ने तीन वर्ष और आठ महीनों की अवधि में 52 अरब डॉलर का कर्ज लिया, जो पाकिस्तान की आर्थिकी के लिहाज से बहुत ज्यादा था।

स्थिति ऐसी बनी कि पाकिस्तान के वार्षिक राजस्व संग्रह से अधिक कर्ज की देनदारी हो गई। पाकिस्तानी रुपए के अवमूल्यन के गलत फैसले से आर्थिक तबाही ने पाकिस्तान को अपनी चपेट में ले लिया। आर्थिक विशेषज्ञता का अभाव, नागरिक सरकार और अर्थव्यवस्था पर फौजी नियंत्रण, बेलगाम भ्रष्टाचार और कोविड महामारी के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने से पाकिस्तान तबाही के कगार पर पहुंच गया। अप्रत्याशित बाढ़ ने रही-सही कमर तोड़कर रख दी। जिस सीपैक परियोजना से पाकिस्तान अपनी तरक्की की आस लगाए बैठा था, वह भी इमरान की नीतियों के चलते अटकती गई। अब पाकिस्तान बिखराव की ओर बढ़ रहा है। सेना और राजनीतिक बिरादरी के बीच पसंद-नापसंद का खेल हाल तक पर्दे की पीछे चलता रहा, लेकिन इमरान खान के चलते यह कड़वाहट पूरी तरह सतह पर आ गई। मई में इमरान की गिरफ्तारी के बाद जो हुआ, वह पाकिस्तान के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। इमरान के समर्थकों ने सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले में जमकर उत्पात मचाया और सैन्य अधिकारी देखते रह गए। हालांकि, उसके बाद से सेना ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक के बाद एक दांव आजमाए। उसने कुछ तत्वों की धरपकड़ के साथ ही जो कार्रवाई की, उसने इमरान की पार्टी में खलबली मचाई, जिससे कई नेता इमरान का साथ छोड़कर चलते बने। सेना के लिए परेशानी की बात यही है कि इस सबके बावजूद इमरान की लोकप्रियता और बढ़ने पर ही है।

छह साल पहले तक जो देश सही ढर्रे पर जाता दिख रहा था, वह पटरी से कैसे उतर गया? आंतरिक पहलू तो जो हैं सो हैं। उनसे इतर प्रधानमंत्री मोदी के रणनीतिक दांव से भी पाकिस्तान की हालत पस्त हुई है। ऐसे रणनीतिक दांव के लिए ही आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। चाणक्य नीति का अर्थ है कि बिना युद्ध में उतरे ही बाजी अपने नाम कर ली जाए। चाणक्य ऐसे युद्ध में विश्वास रखते थे, जिसमें प्रत्यक्ष लड़ाई के बजाय दुश्मन को भावनात्मक रूप से तोड़ दें, ताकि उसका मनोबल रसातल में पहुंच जाए। पाकिस्तान को लेकर मोदी-नीति भी कुछ इसी प्रकार की रही। मोदी ने कई देशों का दौरा किया और वैश्विक नेताओं के साथ व्यक्तिगत संबंध बढ़ाए। इसका खाका तैयार करने में अजीत डोभाल और एस. जयशंकर की अहम भूमिका रही। जयशंकर तब विदेश मंत्रालय में सचिव थे। इस नीति से जुड़े समग्र प्रयासों का परिणाम रहा कि पाकिस्तान विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अलग-थलग पड़ता गया।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

दमन और उत्पीड़न से लोग बेहाल

एक ओर जहां भारत में कश्मीर को प्रगति के नए पंख लग रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर से नागरिकों के लगातार दमन और उत्पीड़न की ही खबरें आ रही हैं। यही कारण है कि सीमा के इस पार भारतीय नागरिकों की दशा में हो रहे सुधार को देखते हुए गुलाम कश्मीर के लोगों में भी पाकिस्तानी शिकंजे से मुक्त होने की इच्छा जोर पकड़ रही है। भारत सरकार को इन भावनाओं और संसद द्वारा पारित उस संकल्प की दिशा में आगे बढ़ने पर विचार करना चाहिए, जिसमें देश की सबसे बड़ी पंचायत ने एकमत से पूरे कश्मीर के भारत में एकीकरण पर सहमति जताई थी। उस संकल्प की पूर्ति के लिए सही समय और अवसर का लाभ उठाने से नहीं चूकना चाहिए। मोदी के साथ प्रगाढ़ संबंधों के चलते उन तमाम देशों ने भी पाकिस्तान के लिए मदद के दरवाजे बंद कर दिए, जो पारंपरिक रूप से उसकी सहायता करते आए थे। जब तक पाकिस्तान के सिर पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ की तलवार लटकी रही, तब तक आईएमएफ से उसे राहत पैकेज भी नहीं मिल पाया। मोदी के इन प्रयासों का ही परिणाम रहा कि पाकिस्तान के हाथ तंग होते गए और कश्मीर में वह चाहकर भी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम नहीं दे पाया। मोदी ने जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद-370 और 35-ए की जकड़न से भी मुक्ति दिलाई। उसके बाद से अशांत कश्मीर घाटी में शांति और समृद्धि की नई बयार महसूस हो रही है। वहां 22 से 24 मई के बीच हुई जी-20 की बैठक के दौरान विदेशी प्रतिनिधियों ने भी परिवर्तन को महसूस किया। पूरी दुनिया कश्मीर में आकार ले रहे बदलाव को देख रही है।

भारत के प्रति दुर्भावना से भरा चीन

जी 20 शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के न आने की आशंका पहले से थी, क्योंकि अमेरिका समेत जी-20 के कई देश यूक्रेन को ऐसे हथियार दे रहे हैं, जिनके जरिए यूक्रेनी सेना रूस के अंदरूनी इलाकों में हमले कर रही है। रूस में आंतरिक उथल-पुथल और सुरक्षा कारणों के चलते भी पुतिन लंबी दूरी की हवाई यात्राएं नहीं कर रहे हैं, पर चीनी राष्ट्रपति के मामले में ऐसा नहीं है। उन्होंने हाल में दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। वह इंडोनेशिया के बाली में हुए जी-20 शिखर सम्मेलन में भी गए थे, जबकि उस समय चीन में कोविड को लेकर भयावह स्थितियां थीं। स्पष्ट है कि भारत में हो रहे जी-20 शिखर सम्मेलन में उनके न आने के कारण असामान्य हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच चलते-चलते कुछ बात हुई थी। इसके बाद चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में शरारतपूर्ण तरीके से लिखा गया कि यह मुलाकात भारत के अनुरोध पर हुई।

भारत ने इसका खंडन करते हुए कहा कि चीनी पक्ष की ओर से लंबी औपचारिक मुलाकात का अनुरोध किया गया था, पर भारत छोटी अनौपचारिक मुलाकात के लिए ही तैयार हुआ। इसका कारण यह था कि भारत पूर्वी लद्दाख में सीमा पर अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति बहाल होने तक चीन के साथ संबंध सामान्य न होने की बात कहता चला आ रहा है। इसके विपरीत चीन चाहता है कि सीमा पर तनाव के बाद भी सब कुछ सामान्य चलता रहे। दक्षिण अफ्रीका में मोदी ने जिनपिंग से कहा था कि चीन पूर्वी लद्दाख में शांति बहाली कायम करे। दोनों नेताओं के बीच संक्षिप्त बातचीत का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें मोदी गंभीर मुद्रा में जिनपिंग से दो कदम आगे चल रहे हैं और चीनी राष्ट्रपति पीछे चलते हुए कुछ कहने की कोशिश में हैं, जिसे मोदी सुनते तो हैं, पर अधिक दिलचस्पी नहीं दिखाते। हाव-भाव का कूटनीति में बहुत महत्व होता है। इस वीडियो से जिनपिंग की मजबूत नेता की छवि को लगे धक्के से उबरने के लिए ही चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से यह झूठ बोला गया कि मुलाकात का अनुरोध भारत की ओर से आया था।

> *जी-20 शिखर सम्मेलन से चीनी राष्ट्रपति का कन्नी काट लेना चीन की भारत के प्रति गहरी दुर्भावना को दिखाता है। चीन भारत को एक एशियाई महाशक्ति मानना तो दूर, एक महत्वपूर्ण देश के रूप में भी स्वीकार नहीं करना चाहता। जिनपिंग यह जताना चाहते हैं कि अगर जी-20 भारत में हुआ तो उनके लिए उसका महत्व ब्रिक्स सम्मेलन से कम है।*

माना जाता है कि जी-20 सम्मेलन में आने के लिए जिनपिंग भारत से कुछ अटपटी मांग कर रहे थे, जिसे मोदी ने नकार दिया। इसके तुरंत बाद ही चीनी सरकार ने चीन का एक नया नक्शा जारी किया, जिसमें लद्दाख के कई भागों और अरुणाचल को चीन का हिस्सा दिखाया गया। चीन समय-समय पर ऐसे बेसिर-पैर के दावे करता रहता है, परंतु इस नए नक्शे को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि 1950 के दौरान चीनी सरकार द्वारा जारी ऐसे ही एक नक्शे के चलते दोनों देशों के बीच विवाद ने गंभीर रूप ले लिया था। यही विवाद 1962 के युद्ध का कारण बना। हालांकि बाली में दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात के बाद चीन की ओर से इसकी पुष्टि की गई थी कि दोनों नेता इस पर सहमत हैं कि सीमा पर तनाव घटाया जाए, परंतु चीनी सेना की ओर से इस दिशा में कोई गंभीर कदम नहीं उठाए गए। चीनी सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कई स्थानों से पीछे तभी हटी, जब भारतीय सेना ने कैलाश पर्वत श्रृंखला की सामरिक महत्व की कई चोटियों पर कब्जा कर लिया।

जी-20 शिखर सम्मेलन से चीनी राष्ट्रपति का कन्नी काट लेना चीन की भारत के प्रति गहरी दुर्भावना को दिखाता है। चीन भारत को एक एशियाई महाशक्ति मानना तो दूर, एक महत्वपूर्ण देश के रूप में भी स्वीकार नहीं करना चाहता। जिनपिंग यह जताना चाहते हैं कि अगर जी-20 भारत में हुआ तो उनके लिए उसका महत्व ब्रिक्स सम्मेलन से कम है। चीन की दुर्भावना का एक प्रमाण हाल में नेपाल में चीनी राजदूत के इस बयान से भी मिला कि भारत की नेपाल के प्रति नीति अच्छी नहीं। यह बयान भारत का नाम लेकर दिया गया, जो कि शत्रुतापूर्ण ही कहा जाएगा।

भारत के प्रति चीन की दुर्भावना समय-समय पर सामने आती ही रहती है। उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जैश-लश्कर के आतंकियों के विरूद्ध आए प्रस्तावों को पारित नहीं होने दिया। जब भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के फलस्वरूप भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह से छूट मिलने का प्रस्ताव आया, तब भी चीन ने रोड़े अटकाए थे। चीन की इन्हीं हरकतों के कारण अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने यह कहा कि संभवत: चीन नई दिल्ली में हो रहे जी-20 सम्मेलन का माहौल खराब करना चाहता था, लेकिन उसकी मंशा पूरी नहीं हो सकी।

● **कुमार विनोद**

चीन कमजोरियों का उठा रहा है फायदा

भारत ने जी-20 शिखर सम्मेलन के इस बड़े मंच का उपयोग रूस और अमेरिका के बीच तनाव कम करने के लिए किया, क्योंकि चीन उसका लाभ उठा रहा है। भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि रूस ने भी चीन द्वारा जारी नए नक्शे को नकार दिया। स्पष्ट है कि वह भी चीनी दादागिरी को लेकर सहज नहीं, परंतु अमेरिका और उसके साथी देशों के प्रतिबंधों के चलते वह चीन पर निर्भर होता जा रहा है। पुतिन अगले महीने चीन में होने जा रहे बेल्ट एंड रोड फोरम में जा सकते हैं। रूसी नौसेना दक्षिण चीन सागर और जापान सागर में चीनी नौसेना की पिछलग्गू बनकर गश्त कर रही है। इससे एशिया में शक्ति संतुलन चीन की ओर झुक रहा है और क्वाड के देशों और खासकर जापान एवं भारत के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं।

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

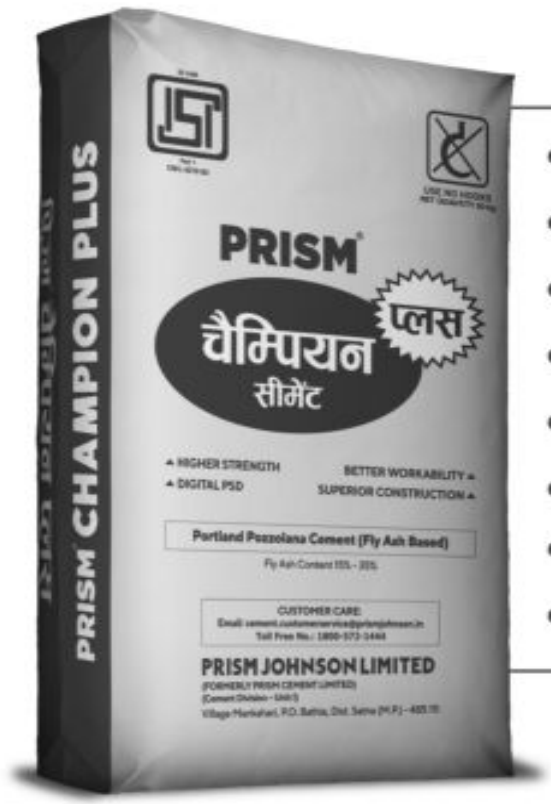

- ज्यादा मज़बूती
- ज्यादा महीन कण
- ज्यादा वर्कबिलिटी
- बेहतरीन निर्माण कार्य
- इको–फ्रेन्डली
- कन्सिसटेंट क्वालिटी
- ज्यादा प्रारम्भिक ताक़त
- ज्यादा बचत

PRISM®
चैम्पियन प्लस
सीमेंट

दूर की सोच®

Toll free: 1800-572-1444 Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

विश्वास

इस कस्बेनुमा शहर के बीचोंबीच मेरी स्टेशनरी की एक छोटी-सी दुकान है, जहां पर कटे-फटे नोट भी बदले जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैंने महसूस किया कि एक पंडित जी लगभग हर हफ्ते-दस दिन में दो, पांच और दस रुपए के 50-60 नोट बदलने के लिए आ रहे हैं। जिज्ञासावश एक दिन मैंने उनसे पूछ ही लिया, भाई साहब, आपके पास इतने सारे कटे-फटे नोट कहां से आ जाते हैं? कहीं आपने भी तो आपने मुहल्ले में नोट बदलने का काम शुरू नहीं कर दिया है?

उन्होंने बहुत ही शांत भाव से जवाब दिया, जी नहीं, मैं गोल चौक के पास वाले शिव मंदिर का पुजारी हूं।

तो? मैंने आश्चर्य से पूछा।

तो क्या? वहीं मंदिर में चढ़ावे में मिलते हैं ये सारे कटे-फटे नोट। उन्होंने बताया।

हे भगवान! क्या कलयुग आ गया है। आजकल लोग भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इन्हें देखकर आपको तो बहुत बुरा लगता होगा? मैंने कहा।

पंडित जी निःश्वास छोड़ते हुए बोले, बुरा लगने जैसी कोई बात नहीं है। मुझे इस बात की तसल्ली है कि लोगों को अब भी ईश्वर पर विश्वास तो है। यह भी विश्वास है कि उसके दरबार में खोटे सिक्के और कटे-फटे नोट भी चल जाते हैं।

अब मैं उन्हें कटे-फटे नोटों के बदले निर्धारित राशि काटकर अच्छे नोट देने लगा।

- डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा

गुब्बारे वाला

शिवमहापुराण कथा सुनने वालों की अपार भीड़ थी। धूप तेज थी; और गरमी भी खूब। बेचारा एक छोटा सा बालक गुब्बारा बेच रहा था। सर पर एक हरे रंग का रूमाल बांध रखा था। उम्र उसकी लगभग दस-ग्यारह बरस की रही होगी।

गुब्बारे वाला बालक एक व्यक्ति का तीखा स्वर सुन हतप्रभ रह गया- नहीं...नहीं...! इसके पास से कोई गुब्बारा-सुब्बारा नहीं लेंगे बेटा। सर पर हरे रंग का रूमाल बांधा है न। तुम्हीं देख लो। इस लड़के से क्यों खरीदेंगे भला। फिर बच्चे ने रूदन स्वर में कहा- मुझे गुब्बारे से मतलब है। मुझे गुब्बारा चाहिए पापा।

गुब्बारे वाला लड़का कुछ देर तक पिता-पुत्र की बातें सुनता रहा। फिर वह एक भगवा कपड़े पहने व्यक्ति के पास गया। उससे अपने माथे पर कुमकुम से त्रिशूल बनवा लिया।

- टीकेश्वर सिन्हा 'गब्दीवाला'

शुद्ध गीता छंद आधारित गीत

चांदनी फैली हुई है,
श्यामला रजनी प्रसार।
कर रही है तारिका ज्यों,
रात में नौका विहार।

टिमटिमाते जुगनुओ की,
रंग भू वह खेत मान।
बल्लरी पर श्वेत बेला,
चंद्रिका का है प्रमान।

मोतियों के झालरें बन,
झूलता वह बेल पात,
गंधमय शुभ मालती भी,
गूंथती नव पुष्प हार।

श्याम घन पट पर जड़े हैं,
ज्यों सितारे रोप्य माल।
हो चमक लोहित मनोहर,
भव्य मोहक सा प्रवाल।

ताजगी भरती सुहानी,
रातरानी मंद-मंद,
हर निमिष में प्रेम की वह,
गंध घोले विभु बयार।

श्रावणी वह मास मोहक,
प्रेम का करता विकास।
दिव्य सी वह प्रीत माला,
झूमती बन चंद्र हास।

गा रही यौवन भरी सी,
नद्य धारा नव प्रवाह,
है ललित सौंदर्य सादा,
दे रही वसुधा दुलार।

जब रजत की बांध पायल,
नाचती लहरें कमाल।
व्योम से चांदी बरसता,
बन गया थल दिव्य थाल

मोहती मन को धवलता,
जोत्सना मृदुला प्रसून,
कर रही आकाश तक वो,
रागिनी अद्‌भुत प्रचार।

- कामिनी मिश्रा अनिका

एशिया का चैंपियन बना भारत

पिछले दिनों ओमान में खेला गया पुरुष हॉकी 5 एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को शूटआउट में 2-0 से हराकर यह पहला खिताब अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ ही भारत ने विश्वकप 2024 में भी प्रवेश कर लिया है। दरअसल, हाफ टाइम तक पाकिस्तान 3-2 से आगे था लेकिन उसके बाद भारतीय टीम ने दमदार वापसी की और फुल टाइम तक स्कोर 4-4 से बराबर कर दिया। ऐसे में मैच का निर्णय शूटआउट में पहुंच गया और भारत के लिए मनिंदर सिंह और गुरजीत सिंह ने गोल किए। वहीं, गोलकीपर सूरज करकेरा ने पाकिस्तान के अरशद लियाकत और मोहम्मद मुर्तजा को गोल नहीं दागने दिया। इसके साथ ही भारत एशिया का बादशाह भी बन गया।

इससे पहले भारत के लिए मोहम्मद राहील (19वां और 26वां), जुगराज सिंह (सातवां) और मनिंदर सिंह (10वां मिनट) ने निर्धारित समय में गोल दागे। वहीं गुरजोत सिंह और मनिंदर सिंह ने शूटआउट में गोल किए। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए निर्धारित समय में अब्दुल रहमान (पांचवां), कप्तान अब्दुल राणा (13वां), जिकरिया हयात (14वां) और अरशद लियाकत (19वां) ने गोल दागे। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में मलेशिया को 10-4 से रौंदकर फाइनल में प्रवेश किया था। जबकि पाकिस्तान ने पहले सेमीफाइनल में ओमान को 7-3 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। भारत की ओर से सेमीफाइनल में मोहम्मद राहील (नौवें, 16वें, 24वें, 28वें मिनट), मनिंदर सिंह (दूसरे मिनट), पवन राजभर (13वें मिनट), सुखविंदर (21वें मिनट), टिर्की (22वें मिनट), जुगराज सिंह (23वें मिनट) और गुरजीत सिंह (29वें मिनट) ने गोल दागे। वहीं मलेशिया के लिए कप्तान इस्माइल आसिया अबू (चौथे मिनट), अकहिमुल्लाह अनवर (सातवें, 19वें मिनट), मोहम्मद दिन (19वें मिनट) में गोल किए। भारत को टूर्नामेंट के एलीट पूल चरण के मैच में पाकिस्तान से 4-5 से हार मिली थी।

भारतीय हॉकी टीम ने ओमान में खेला गया एशियाई हॉकी 5एस विश्व कप क्वालीफायर में धमाकेदार प्रदर्शन किया। हॉकी टीम ने पहले मलेशिया और इसके बाद जापान को शानदार अंदाज में पटखनी देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत ने मलेशिया को 7-5 और जापान को 35-1 से पटखनी दी। दोनों मुकाबलों में भारतीय हॉकी टीम के प्लेयर्स ने कुल 35 गोल किए। टीम के प्लेयर्स ने ज्यादातर समय गेंद को अपने पास रखा और विरोधी टीम को टिकने का मौका ही नहीं दिया। गौरतलब है कि एक तरफ क्रिकेट फैंस की नजरें जहां श्रीलंका में टिकी हुई थीं, जहां वनडे एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने थीं और बारिश से जूझती दिख रही थीं। उसी बीच दूसरी तरफ हॉकी 5 पुरुष एशिया कप में भी भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा था। हालांकि ये टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला था और इसमें भारतीय हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। हॉकी 5 फॉर्मेट में 5 खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं। भारत की तरफ से फाइनल में मनदीप मोट (कप्तान), सूरज करकेटा, जुगराज सिंह, मनिंदर सिंह और पवन राजभर मैदान पर उतरे। मैच काफी रोमांचक रहा जिसमें एक समय पाकिस्तान के 3 गोल थे और भारत के 2 (गोल) भारत एक गोल से पिछड़ रहा था, लेकिन अंतिम क्षणों में भारत ने गोल करके स्कोर 4-4 से बराबर कर दिया। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट से फैसला किया जाना था। पेनल्टी शूटआउट में भारत ने अपने दोनों शॉट को गोल में तब्दील किया जबकि पाकिस्तान गोल करने में चूक गया। इसके साथ ही भारत 2 से पेनल्टी शूटआउट में जीता और साथ ही टूर्नामेंट भी। इस टूर्नामेंट का सबसे यादगार पल रहा जब भारत ने जापान की टीम को 35 गोल करके करारी शिकस्त दी।

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई हॉकी 5एस विश्व कप क्वालीफायर के अपने अंतिम लीग मैच में गोल की बारिश कर दी और जापान को 35-1 से करारी शिकस्त दी। भारतीय टीम के सामने जापान असहाय नजर आया। उसने पहले पांच मिनट के अंदर ही सात गोल कर दिए थे और इसके बाद भी जापानी टीम पर किसी तरह का रहम नहीं दिखाया। भारत की तरफ से मनिंदर सिंह ने 10 गोल दागे। उनके अलावा मोहम्मद राहिल ने सात, पवन राजभर और गुरजीत सिंह ने पांच-पांच, सुखविंदर ने चार, कप्तान मनदीप मोर ने तीन और जुगराज सिंह ने एक गोल किया। जापान की तरफ से एकमात्र गोल मसाताका कोबोरी ने किया। भारतीय टीम के आगे जापानी टीम टिक ही नहीं पाई और मुकाबला हार गई।

मनिंदर सिंह के चार गोल और मोहम्मद राहिल की हैट्रिक की मदद से भारत ने बांग्लादेश को 15-1 से करारी शिकस्त देकर एशियन हॉकी 5एस विश्व कप क्वालीफायर में अपने अभियान की बेहतरीन शुरुआत की। भारतीय टीम ने अपने कमजोर प्रतिद्वंदी के खिलाफ शुरू से ही दबदबा बनाए रखा। बांग्लादेश ने शुरू में गोल कर दिया था लेकिन इसके बाद भारत ने विरोधी टीम को आगे ऐसा कोई मौका नहीं दिया। भारत की तरफ से मनिंदर ने 10वें, 18वें, 28वें और 30वें मिनट में जबकि राहिल ने दूसरे, 15वें और 24वें मिनट में गोल किए। इनके अलावा सुखविंदर (13वें, 22वें), गुरजीत सिंह (13वें, 23वें) और पवन राजभर (19वें, 26वें) ने दो-दो जबकि मंदीप मोर (8वें), और दिपसन तिर्की (9वें) ने एक-एक गोल दागा। बांग्लादेश के लिए एकमात्र गोल सावोन सरोवर ने किया।

● आशीष नेमा

हॉकी इंडिया ने की पुरस्कार घोषणा

पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में जीत के बाद हॉकी इंडिया ने खिलाड़ियों को 2 लाख रुपए और सहयोगी स्टाफ को 1-1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। हॉकी इंडिया ने ट्वीट करके कहा, पुरुष हॉकी टीम को 5एस एशिया कप 2023 में शानदार प्रदर्शन के लिए हॉकी इंडिया ने नकद इनाम की घोषणा की है। प्रत्येक खिलाड़ी को 2 लाख रुपए और प्रत्येक सपोर्ट स्टाफ को 1 लाख रुपए मिलेंगे। हॉकी एशिया कप अपने नाम करने के बाद अब फैंस को क्रिकेट में भी टीम इंडिया से एशिया कप का इंतजार है। इसके लिए फैंस सोशल मीडिया पर डिमांड करते दिख रहे हैं। वहीं हॉकी इंडिया ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि टीम इंडिया को एशिया कप के लिए शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि क्रिकेट का एशिया कप भी भारत ही आएगा।

20 साल से गायब हैं शाहरुख की हीरोइन, प्यार के लिए पलभर में ठुकरा दिया बॉलीवुड

शाहरुख खान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाने वाली मूवी स्वदेस साल 2004 में रिलीज हुई थी। फिल्म में गायत्री जोशी के किरदार को भी खूब प्यार मिला और पहली ही फिल्म से गायत्री जोशी स्टार बन गईं। लेकिन गायत्री ने अपने करियर के पीक पर ही फिल्मों की रंगीन दुनिया को अलविदा कह दिया।

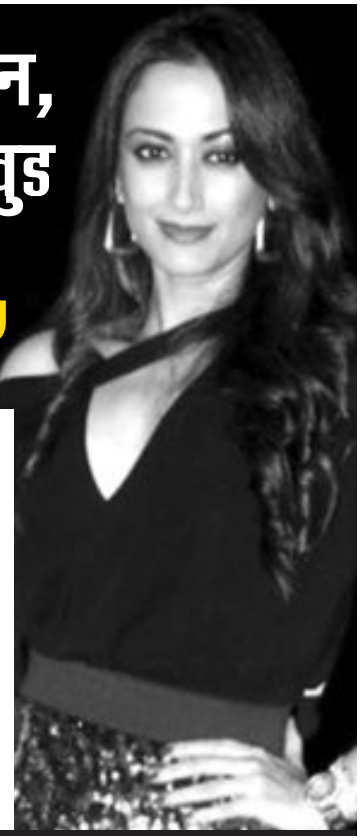

डेब्यू मूवी के जरिए छा जाने वाली गायत्री ने अपने प्यार के लिए करियर की कुर्बानी दे दी। बॉलीवुड छोड़ते समय गायत्री ने इसके पीछे की कोई वजह नहीं बताई और अचानक गायब हो गईं। करीब 15 साल बाद गायत्री ने मीडिया से बात की और इंडस्ट्री छोड़ने के फैसले के पीछे की वजह बताई।

साल 2019 में दिए एक इंटरव्यू में गायत्री जोशी ने बताया, मैं अपने परिवार और बच्चों को पूरा समय देना चाहती थी। इसलिए मैंने अचानक इंडस्ट्री छोड़ दी। स्वदेस के बाद मेरे पास कई फिल्मों के ऑफर आ रहे थे। लेकिन इन सभी में मेरे पास स्वदेस जैसे ही किरदारों की लाइन लगी थी। लेकिन मैं फिर से इस तरह का किरदार नहीं करना चाहती थी। दरअसल, गायत्री जोशी ने अपने प्यार विकास ओबेरॉय से शादी कर ली थी।

आज 2800 करोड़ की मालकिन हैं गायत्री जोशी

गायत्री जोशी के पति विकास ओबेरॉय एक बड़े बिजनेसमैन हैं और उनकी 2800 करोड़ रुपयों से ज्यादा की मार्केट कैप है। पति के बिजनेसमैन होने के बाद गायत्री ने अपने करियर को पीक पर ही अलविदा कह दिया। गायत्री जोशी आज अपने पति विकास ओबेरॉय के साथ खुशी-खुशी जिंदगी बिता रही हैं। गायत्री के 2 बेटे भी हैं। गायत्री अब ग्लैमर की दुनिया से पूरी तरह दूर हैं।

'कॉमन मैन' ने जब गोविंदा को सिखाया सबक, एक्टर के छूटे पसीने, चौपट हुआ करियर, दे डालीं 12 डिजास्टर फिल्में

गोविंदा बॉलीवुड का वो नाम हैं जो 90 के दशक में दर्शकों के दिलों पर छा गया था और देखते ही देखते ये एक्टर बॉक्स-ऑफिस का बादशाह भी बन गया था। स्टारडम के नशे में डूबे गोविंदा का एक वाकया ऐसा भी है, जिसने उनके करियर को बर्बाद करके रख दिया था।

दरअसल, ये वाकया साल 2008 में आई एक्टर की फिल्म मनी है तो हनी है के सेट पर का है। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान चीची ने सेट पर मौजूद एक फैन को किसी बात पर थप्पड़ जड़ दिया था और फिर क्या था गुस्से से बौखलाए फैन ने भी सुपरस्टार को सबक सिखाने की कसम खा ली। गोविंदा के फैन ने सबके सामने कसम खा ली थी कि वह गोविंदा से मांफी मंगवा कर ही मानेंगे और इसके लिए उन्होंने एक्टर को बकायदा एक साल का समय भी दिया था। 1 साल का समय दिए जाने के बावजूद गोविंदा द्वारा माफी न मांगे जाने पर एक्टर के फैन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला लिया। सालों तक कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने और जज द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद इस स्टार के सिर से स्टारडम का खुमार उतरा और उन्होंने न सिर्फ फैन से माफी मांगी बल्कि उन्हें सालों तक कोर्ट का चक्कर काटने के लिए लाखों का मुआवजा भी दिया।

जब मनोज कुमार से भिड़ गईं जया बच्चन, अमिताभ बच्चन की वजह से हुई लड़ाई, कहा- आपने तो बर्बाद कर दिया...

जब मनोज कुमार बॉलीवुड के मेगास्टार थे, तब अमिताभ बच्चन अपने करियर में एक हिट फिल्म के लिए तरस रहे थे। अमिताभ बच्चन की डेब्यू फिल्म के करीब 5 साल बाद मनोज कुमार ने अपनी एक फिल्म में उन्हें मौका दिया। उनकी उस फिल्म का नाम रोटी कपड़ा और मकान था।

कहा जाता है कि फिल्म में अमिताभ को मिले कम स्क्रीन स्पेस से उनकी वाइफ जया बच्चन मनोज कुमार से काफी नाराज हो गई थीं। उन्होंने मीडिया के सामने मनोज कुमार पर कई सारे आरोप लगाए थे। ये बातें तब की हैं, जब फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज हुई और शानदार कमाई कर उन दिनों खबरों में थी। जया बच्चन ने मीडिया में फिल्म को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि मनोज कुमार ने फिल्म में अमिताभ को बर्बाद कर दिया। उन्हें स्क्रीन पर अधिक समय मिलना चाहिए था, लेकिन मनोज ने ऐसा जानबूझकर किया। रिपोर्ट्स के अनुसार, जया के इस बयान के बाद मनोज ने जवाब देते हुए जया बच्चन की काफी तारीफ की थी। मनोज कुमार ने जया का पटवार करते हुए कहा था कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि जया जैसी दिग्गज अभिनेत्री ने इस बारे में सोचा तो कि अभिनय में फुटेज मायने रखता है।

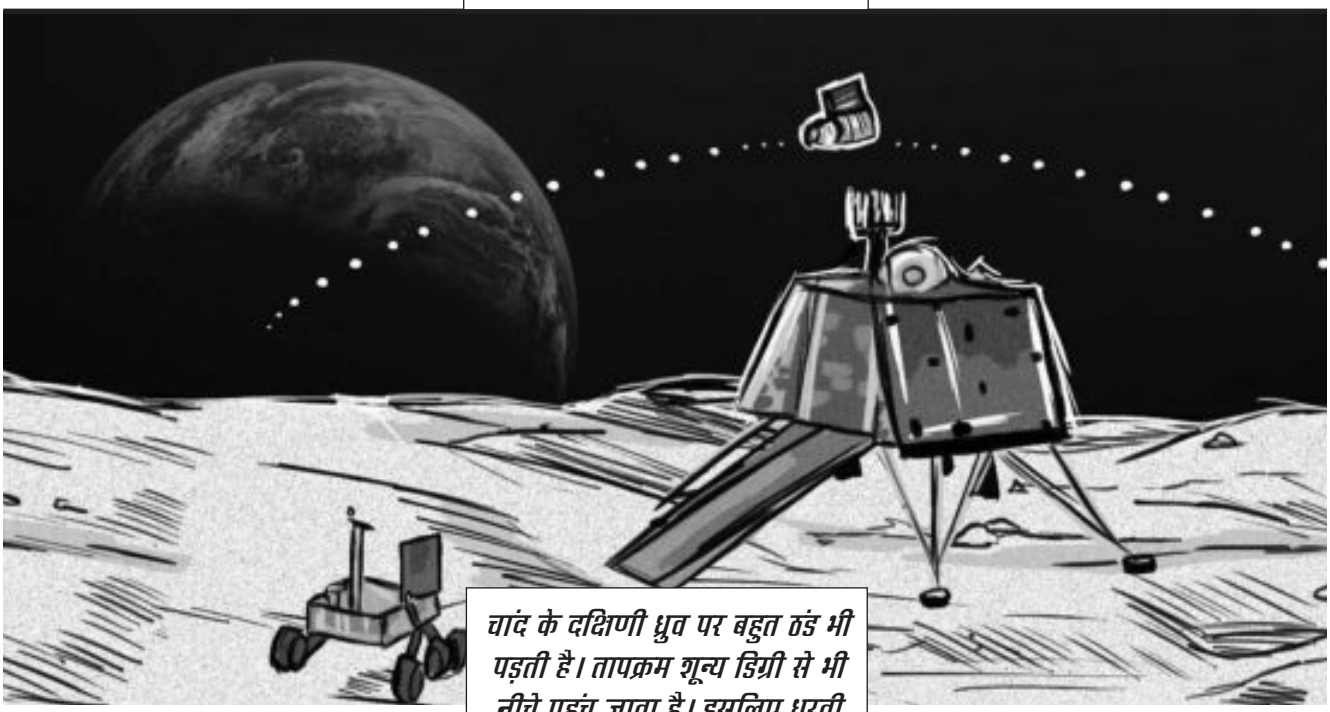

चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बहुत ठंड भी पड़ती है। तापक्रम शून्य डिग्री से भी नीचे पहुंच जाता है। इसलिए धरती के रजाई-गद्दे वहां काम नहीं आएंगे। उस दशा में हीटर, ब्लोअर और नए किस्म के गरम हवा देने वाले एसी के कारोबार के लिए वहां असीम संभावनाएं हैं। देश के उद्योगपति वहां इनकी फैक्ट्री लगाने के बारे में सोच सकते हैं।

चंद्रयान ने बदल दिए कल्पनाओं के रंग

चांद पर अपना तिरंगा पहुंचने के साथ ही विकास के नए द्वार खुले हैं। साथ ही कुछ आशंकाएं और संभावनाएं भी पैदा हुई हैं। पहले आशंकाओं की बात कर लेते हैं। अब आंख बंद करके महबूबा या पत्नी के चेहरे की तुलना चांद से नहीं की जा सकेगी। मानहानि के दावे का खतरा है, क्योंकि महबूबा और पत्नी भी अब चांद की असली सूरत से वाकिफ हो चुकी हैं। वहां तो बड़े-बड़े गड्ढे हैं।

अब ऐसे सभी फिल्मी गीत, कविताएं और शेर-ओ-शायरी भी निरर्थक मानी जाएंगी, जिनमें चांद को हाजिर-नाजिर मानकर प्रेमिका की शान में कसीदे काढ़े गए हैं। उनकी जगह महंगे और स्वास्थ्य वर्धक टमाटर, चुकंदर आदि से उनकी खूबसूरती की तुलना की जा सकती है। अब शादी तय करते समय लड़की को चांद या उसका टुकड़ा बताने पर पाबंदी लगानी होगी। यदि बताना आवश्यक ही होगा तो यह भी बताना होगा कि वह चांद के किस हिस्से का टुकड़ा है...उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव का। पूरी दुनिया में अकेले हमने ही अभी तक दक्षिणी ध्रुव पर विजय हासिल की है। इसलिए अंतरिक्ष कानून के मुताबिक, जो अभी बना नहीं है, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर हमारी मिल्कियत है। ऐसे में विवाह योग्य कन्या को किसी और ध्रुव का बताना, स्वत: खारिज हो जाएगा।

इसरो के चंद्रयान-3 की लैंडिंग ने चांद पर संभावनाओं के तमाम द्वार भी खोल दिए हैं। हमारा देश तो ऐसे कर्मठ लोगों की मातृभूमि है, जो आपदा में भी अवसर खोज लेते हैं। अफसरों की नाक के नीचे सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेने वाले भू-माफिया के लिए चांद सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित हो सकता है। वे चाहें तो पूरा ग्रह नाप लें...फिलहाल कौन है मना करने या नोटिस देने वाला। इसी तरह दस फीट की गली में बीस मंजिला अपार्टमेंट खड़ा कर देने में दक्ष बिल्डरों के लिए भी सुनहरा मौका है। अमेरिका, रूस और चीन वहां बस्ती बसाने के बारे में सोचें, उसके पहले ही वे प्लाटिंग कर अपना बोर्ड लगा सकते हैं। कॉलोनी बना सकते हैं, माल खड़ा कर सकते हैं। अभी न तो कोई उसे अवैध बताने वाला है और न बुलडोजर चलवाने वाला।

चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बहुत ठंड भी पड़ती है। तापक्रम शून्य डिग्री से भी नीचे पहुंच जाता है। इसलिए धरती के रजाई-गद्दे वहां काम नहीं आएंगे। उस दशा में हीटर, ब्लोअर और नए किस्म के गरम हवा देने वाले एसी के कारोबार के लिए वहां असीम संभावनाएं हैं। देश के उद्योगपति वहां इनकी फैक्ट्री लगाने के बारे में सोच सकते हैं। विज्ञानियों को उम्मीद है कि वहां शायद बर्फ के रूप में पानी हो। मिल जाता है तो सोने पर सुहागा। वहां व्यापारी भाइयों के लिए आरओ, मिनरल वाटर या चंद्र नीर नाम से बोतलबंद पानी का कारोबार शुरू करने की प्रचुर संभावनाएं हैं। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया है कि अब चंदा मामा दूर के नहीं, बल्कि टूर के तो ट्रैवल ऑपरेटर भी सक्रिय हो सकते हैं।

चांद पर अभी किसी आबादी का पता नहीं चला है। पूरा ग्रह पाकिस्तान के सरकारी खजाने की तरह वीरान पड़ा है। यानी अगर किसी का दस का नोट वहां गिर जाए तो कोई उठाने वाला नहीं है। इसलिए हमारे चंद्रयान में चोरी-चकारी का कोई खतरा नहीं है, लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि किसी और ग्रह का यान अपने देश में लैंड कर जाता तो! पहले तो यातायात पुलिस उसे नो पार्किंग में बताकर उठवा लेती। फिर 1,100 या 2,100 रुपए जुर्माने के बाद वह छूटता और रात में रुक जाता तो उसकी स्टेपनी वगैरह हिस्से चोरी हो जाते।

अगले दिन वह निश्चित ही कोई प्रयोग करने के बजाय, सिर पर पैर रखकर उलटे वापस लौट जाता। मान लीजिए इसके बाद भी वह बेशर्मी से अड़ा रहता कि मिशन पूरा करके ही मानेंगे तो जानते हैं क्या नजारा होता। उधर एलियंस अपने कंट्रोल रूम में बैठे कमांड दे रहे होते और इधर उनका यान चोर बाजार में पुर्जा-पुर्जा होकर बिक रहा होता। एल्यूमीनियम, लोहा, वायरिंग और बाकी कलपुर्जे किलो के भाव कबाड़ी तौल रहा होता। एलियंस भूलकर भी दोबारा इधर का रुख न करते।

● **कमल किशोर सक्सेना**

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

युवाओं को हर विधा में पारंगत करने को तैयार शिवराज सरकार

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

क्रियान्वयन कार्य-योजना

शिक्षा और कौशल

[illegible]

विजन

मध्यप्रदेश के युवाओं को उनकी क्षमताओं से अवगत कराते हुए संपूर्ण विकास करने के लिए सक्षम करना, जिससे वे राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में प्रभावी योगदान कर सकें।

मध्यप्रदेश युवा नीति 2023 को युवा महापंचायत 2022 से प्राप्त सुझावों, राष्ट्रीय युवा नीति (ड्राफ्ट) 2021, विभिन्न देशों की युवा नीति, देश के अन्य राज्यों की युवा नीति एवं मध्यप्रदेश राज्य युवा नीति 2008 के अध्ययन के बाद तैयार किया गया है। यह नीति प्रदेश के समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लिया गया कदम है, जिसमें युवा एक अहम भूमिका निभाएंगे। इस नीति से मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बनकर उभरेगा, जिसमें युवाओं की ऊर्जा और योग्यता के सभी बहुआयामी सरोकार समाहित होंगे। इसमें क्षेत्रीयता, जातिवाद और लिंग असमानता नहीं होगी।

क्रियान्वयन रूपरेखा

- राज्य युवा आयोग का पुनर्गठन।
- जिला स्तर पर युवा संसाधन केंद्रों की स्थापना।
- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विभिन्न क्षेत्र में सक्रिय युवा प्रतिनिधियों को सम्मिलित कर राज्य युवा सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा।
- राष्ट्रीय तथा राज्य युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को राज्य एवं जिला स्तर की विभिन्न सलाहकार समितियों में सम्मिलित करना।
- मध्यप्रदेश युवा कल्याण सूचकांक विकसित करना।
- युवा बजट का निर्माण।

युवा नेतृत्व एवं सामाजिक कार्य

- युवाओं को विधान मंडल, कार्यपालिका न्यायपालिका, पंचायत राज संस्थाओं/ स्थानीय निकायों तथा शासकीय विभागों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश विकसित किए जाएंगे।
- 30 वर्ष से कम आयु के जन-प्रतिनिधियों को क्रॉस लर्निंग के अवसरों का लाभ उठाने के लिए देश भर में मॉडल पंचायतों/शहरी स्थानीय निकायों में एक्सपोज़र भ्रमण करवाया जाएगा, जिससे वे अपने-अपने क्षेत्रों में उपयुक्त सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू कर सकें।
- युवाओं एवं प्रोफेशनल्स के द्वारा सेवानिवृत्त तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑन-ग्राउंड एवं ऑनलाइन स्वयंसेवा को बढ़ावा देने तथा एक मंच प्रदान करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य स्वयंसेवक कार्यक्रम विकसित किया जाएगा।
- ग्रामीण स्तर पर युवाओं को संगठित कर स्वामी विवेकानंद युवा क्लब गठित किए जाएंगे।
- सामाजिक कार्य करने वाले सक्रिय युवाओं को राज्य एवं जिला युवा सलाहकार परिषद में जोड़ा जाएगा।
- युवा महापंचायत जैसे कार्यक्रमों का प्रतिवर्ष आयोजन किया जाएगा।
- अंतर्राष्ट्रीय सीमा भ्रमण के लिए संचालित माँ तुझे प्रणाम योजना में जन अभियान परिषद एवं नेहरू युवा केंद्र के युवाओं को भी जोड़ा जाएगा।
- युवाओं से संबंधित योजनाओं का समय-समय पर सोशल ऑडिट किया जाएगा।

रोज़गार और उद्यमिता

[illegible]

खेल एवं फिटनेस

[illegible]

स्वास्थ्य

[illegible]

कला-संस्कृति

[illegible]

पर्यावरण

1. ग्रीन इकोनॉमी एवं ग्रीन जॉब्स विषय पर केन्द्रित प्रशिक्षण सामग्री तैयार की जायेगी एवं मास्टर ट्रेनर का एक कैडर विकसित किया जाएगा।
2. इको फिलॉसफी, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास लक्ष्य, पर्यावरण प्रदूषण, वेटलैंड्स एवं अपशिष्ट प्रबंधन विषयों पर शोध / अध्ययन के लिये यथासंभव के साथ समय एवं विशेष इंटर्नशिप, फेलोशिप प्रदान की जाएगी।
3. महाविद्यालय के विद्यार्थियों को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल की प्रयोगशालाओं एवं विभिन्न मॉनिटरिंग वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन जैसी सुविधाओं में शैक्षणिक भ्रमण कराए जायेंगे।
4. पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न विषयों पर केन्द्रित लघु अवधि वाले कार्यक्रम जैसे नेचर वॉक, पक्षी दर्शन एवं भ्रमण, वेटलैंड वॉक इत्यादि को विभिन्न विभाग एवं गैर-शासकीय संगठन के साथ मिलकर आयोजित किया जाएगा।
5. शासकीय विभागों, गैर-शासकीय संस्थाओं, अन्य संस्थाओं के साथ प्रत्येक वर्ष जिला स्तर पर महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं के लिए जलवायु परिवर्तन, सतत विकास लक्ष्य, वायु प्रदूषण, भोजन के अपव्यय, मिशन LIFE, वेटलैंड संरक्षण, जैव-विविधता संरक्षण आदि पर केन्द्रित पर्यावरण प्रतियोगिताएँ की जाएंगी।
6. एनजीओ द्वारा ग्रामीण युवाओं के लिए जैविक कृषि, जीरो बजट, नेचुरल फार्मिंग, संरक्षित कृषि एवं कम्पोस्ट [illegible] जैसे विषयों पर कार्यशालाएँ की जाएंगी।

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

सुराज से होंगे
जनता के सपने साकार

मध्यप्रदेश में सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के बाद खाली हुई भूमि पर आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के लिए आवास निर्माण के लिए सुराज नीति-2023 लागू की गई है।

सरकार ने माफिया से मुक्त कराई गई सरकारी जमीन पर सुराज कॉलोनी बनाने का निर्णय लिया है। यहाँ लोगों को सभी जरूरी सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी। नीति का उद्देश्य बिना सरकारी बजटीय सहायता के पुनर्धनत्वीकरण नीति के अनुरूप सुराज कॉलोनी के तहत ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के आवासहीनों के लिए किफायती आवास प्रदान करना और अतिक्रमण से मुक्त की गई भूमि का शहर के विकास के लिए सर्वोत्तम उपयोग करना है।

सुराज नीति के मुख्य बिंदु...

- 1 अप्रैल 2020 के बाद अतिक्रमण से मुक्त कराई गई शासकीय भूमि पर आवासहीन तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास निर्माण की योजना।
- अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि का एक टुकड़ा निजी डेवलपर को सौंपा जाएगा, जिसके बदले शेष भूमि में ईडब्ल्यूएस आवास के लिए सुराज टॉवर बनेगा।
- निजी डेवलपर को दिए जाने वाले भू-खंड के आरक्षित मूल्य की गणना लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग की स्थापित नीति के अनुसार खुली निविदाओं के आधार पर की जाएगी।
- छोटे शहरों में मल्टी स्टोरी के स्थान पर 450 वर्ग फीट तक के आवासीय प्लॉट भी कॉलोनी विकसित कर दिए जा सकेंगे।
- सुराज कॉलोनी में सड़क, जल-प्रदाय, बिजली, बगीचा आदि की सुविधा होगी।
- निर्माण होने के बाद इकाइयों का आवंटन कमजोर आय वर्ग के आवासहीन को नगरीय निकाय द्वारा किया जायेगा।
- संबंधित भूमि के एक भाग का उपयोग आवासहीन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सुराज कॉलोनी के अंतर्गत भवन/ प्रकोष्ठ/ भूखण्ड के निर्माण के लिए किया जायेगा। सुराज कॉलोनी की अनुमानित परियोजना लागत के अनुरूप मूल्य के टीडीआर को निजी विकासकर्ता द्वारा 'भू-स्वामी अधिकार' में उपयोग किया जायेगा।
- योजना के क्रियान्वयन के लिए अन्य सभी प्रक्रियाएँ राज्य में स्थापित रिडेंसीफिकेशन नीति-2022 के अनुसार की जाएगी।
- सुराज टॉवर/कॉलोनी का निर्माण समय-सीमा और गुणवत्ता से करने के प्रावधान किए गए हैं। सुराज टॉवर कॉलोनी निर्माण के बाद अगले पाँच वर्ष तक डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड का दायित्व और 3 वर्ष तक कॉलोनी का रख-रखाव संचालन एवं मरम्मत का दायित्व निजी डेवलपर का रहेगा।

> मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के अंतर्गत गाँव में चिन्हित करके हर परिवार को जमीन का टुकड़ा उपलब्ध कराया जाएगा। मध्यप्रदेश में 23000 एकड़ से ज्यादा जमीन माफियाओं से मुक्त कराई गई है। हम उस जमीन पर सुराज कॉलोनी की स्थापना कर गरीबों को उस जमीन पर बसाएंगे।
>
> - शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

35000 लोगों को मिले भूखंड

टीकमगढ़ और सिंगरौली जिले में सरकार ने माफिया से मुक्त कराई जमीन भूमिहीनों को दी है। मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना में दोनों जिले में 35 हजार से अधिक लोगों को योजना का लाभ दिया गया है।

सरकार के प्रयासों से बढ़ता मध्यप्रदेश